राष्ट्रीय संस्करण

विराट ने खोला भारत में तेज गेंदबाजों की सफलता का राज >>12

वर्ष 3 अंक 121

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 9 अक्टूबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

प्रस्तावित राम मंदिर जैसे मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने किया रावण का दहन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **मंच पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट के गुंबद की प्रतिकृति अंत समय में हटाई गई**
- **पीएम ने कहा, हर मां-बेटी का सम्मान व गरिमा बनाए रखने का लें संकल्प**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर राजधानी दिल्ली के द्वारका में रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने 107 फीट ऊंचे रावण का दहन किया। पीएम मोदी ने रामलीला के जिस मंच से रावण पर बाण चलाया, उसे अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर का रूप दिया गया था और इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। वहीं, मंच के बीचोबीच सुप्रीम कोर्ट के गुंबद की प्रतिकृति बनाई गई थी। हालांकि पीएम मोदी के आने से पहले श्रीरामलीला सोसायटी के पदाधिकारियों ने अंतिम समय में सुप्रीम कोर्ट का गुंबद हटा लिया। पदाधिकारियों ने बताया कि राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए हमने कोर्ट के गुंबद को हटाना उचित समझा।

पीएम मोदी ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा कि इस बार यह पर्व अपने साथ अद्भुत संयोग लेकर आया है। देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का जन्मदिन भी आज ही है। इस पवित्र संयोग पर हम सभी को देश की भलाई के लिए कम से कम एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए, जिससे किसी न किसी की भलाई हो। इस संयोग का उपयोग अपनी कमियों और आसुरी शक्तियों को नष्ट करने में करें। यह संकल्प किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे-पानी बचाना, खाना खाते हुए जूठा नहीं छोड़ना, बिजली बचाना, देश की संपत्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाने का संकल्प।

द्वारका के सेक्टर 10 के डीडीए मैदान की रामलीला में तीर चलाते प्रधानमंत्री मोदी।

रामलीला का मंच अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के माडल जैसा बनाया गया था, यहीं से प्रधानमंत्री ने मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर रावण के पुतले का दहन किया। ध्रुव कुमार

देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, जहां शक्ति साधना न हुई हो : उन्होंने कहा कि भारत के सामाजिक जीवन का प्राणतत्व उत्सव है। उत्सव के साथ हमारे यहां प्रतिभा को निखारने का, प्रतिभा को सामाजिक गरिमा देने का, उसे पुरस्कार देने का निरंतर प्रयास रहा है। हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत में कला साधना और उत्सवों के कारण भारतीय परंपरा में रोबोट नहीं, जीते- जागते इंसान पैदा होते हैं। नवरात्र के नौ दिनों में देश का कोई ऐसा कोना नहीं होगा, जहां शक्ति साधना, उपासना न हुई हो। मां की उपासना करने वाले हमारे देश में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हर मां-बेटी का सम्मान, गौरव, गरिमा को बनाए रखने का संकल्प लें। इस दिवाली पर हमें अपनी उन बेटियों के सम्मान का संकल्प लेना चाहिए, जो अपने कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनी हों।

सामूहिक शक्ति का सामाजिक कार्यों में करें उपयोग

सामूहिकता की शक्ति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, प्रभु श्री राम ने अपने साथियों के बल पर समुद्र पर पुल बना दिया, लंका तक पहुंच गए। इस सामूहिक शक्ति का हमें भी सामाजिक कार्यों में उपयोग करना चाहिए। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए सभी को साथ लेते हुए आंदोलन चलाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज वायुसेना का जन्मदिवस है, हम जब भगवान हनुमान को याद करते हैं तब वायुसेना और हमारे जांबाज सैनिकों के अदम्य साहस को भी याद करें।

वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दिल्ली की अलग अलग रामलीलाओं में शिरकत की। सोनिया ने प्रतीकात्मक तीर छोड़कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।

विजयादशमी पर विशेष आयोजन पेज>>13

सरोकार

सहजन वाला वाटर प्यूरीफायर दिलाएगा डायरिया से मुक्ति

सोलन (हिमाचल प्रदेश) : सहजन यानी ड्रमस्टिक के बीजों के पाउडर से बनाए गए इस वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल टी-बैग की तरह ही आसानी से किया जा सकता है। पांच मिनट में एक लीटर दूषित पानी पीने योग्य बन जाता है। कीमत मात्र पचास पैसे है। (पेज-13)

जागरण विशेष

काली मिर्च से कर रहे 'उजाले' की खेती

कोंडागांव : आर्थिक रूप से वनोजनों पर ही निर्भर रहने वाले आदिवासियों ने तंगी और बदहाली के अंधेरे में उजाला भरने के लिए काली मिर्च की खेती शुरू की है। काली मिर्च से आमदनी तो होगी ही, साल वनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होता चलेगा। (पेज-13)

हिंदू राष्ट्र है भारत : संघ प्रमुख

भागवत बोले ▶ हिंदुओं को एकजुट करने का अर्थ इस्लाम का विरोध नहीं

लिंचिंग भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं, देश को बदनाम करने के लिए लाया गया शब्द

राज्य ब्यूरो, मुंबई

हर भारतीय जो देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं शांति स्थापना के लिए काम कर रहा है, वह हिंदू है। हमारा स्पष्ट मानना है कि भारत हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशिमबाग मैदान में शस्त्र पूजा के बाद परंपरागत दशहरा रैली में मंगलवार को यह बात कही। सरसंघचालक भागवत ने 'लिंचिंग' जैसे शब्द के प्रयोग पर भी आपत्ति जताते हुए इसे आयातित करार दिया। उन्होंने कहा, भारत और हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है।

हिंदू राष्ट्र के प्रति संघ की अवधारणा पर भागवत ने कहा, 'राष्ट्र की पहचान, हम सब की सामाजिक पहचान और देश की प्रकृति को लेकर संघ का विचार स्पष्ट और दृढ़ है कि भारत हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र है। भारत से संबंध रखने वाला, भारतीय पूर्वजों की संतान व विविधताओं का सम्मान करने वाला हर भारतीय हिंदू है।' हिंदुओं को एकजुट करने का अर्थ इस्लाम का विरोध नहीं है। उन्होंने कहा, देश में कहीं भी एक समुदाय के कुछ लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के किसी व्यक्ति पर हमले की घटना सामने आती है, तो पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाने लगता है। ऐसी घटनाएं भारत की मूल प्रवृत्ति कभी नहीं रहीं। 'लिंचिंग' भारतीय सभ्यता का शब्द नहीं है, इसका संबंध अन्य धर्म की कथा से है। यह पश्चिमी अवधारणा है और देश को बदनाम करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है।

भागवत ने कहा, ऐसी घटनाओं में लिप्त लोगों का भारत ने कभी समर्थन नहीं किया। संघ हमेशा ऐसी घटनाओं के विरोध में खड़ा रहा है। कुछ लोग संघ को बदनाम करने के लिए उसका नाम भी ऐसी घटनाओं से जोड़ देते हैं। हर बात के लिए संघ पर आरोप लगाना कुछ लोगों की आदत बन गई है। अब तो पाक के पीएम इमरान खान भी संघ पर आरोप लगाना सीख गए है। कार्यक्रम में अरबपति उद्योगपति शिव नादर भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है।

सरकार की पीठ थपथपाई: संघ प्रमुख ने दोबारा चुनकर आई मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा, 2014 में सत्ता परिवर्तन तत्कालीन सरकार के प्रति मोहभंग से उत्पन्न हुई नकारात्मक राजनीतिक लहर का परिणाम था, वहीं 2019 में नई सरकार को ज्यादा बहुमत से चुनकर लाना समाज में उसके पिछले कार्यों के प्रति सम्मति और नई अपेक्षाओं का परिणाम है। संसद के दोनों सदनों में विरोधियों को भी साथ लेकर अनुच्छेद 370 हटाने के लिए पीएम, गृह मंत्री और समर्थन करने वाले सभी दल अभिनंदन के पात्र हैं। भागवत ने चंद्रयान-2 का भी उल्लेख किया।

मंदी का शोर मचाना गलत : भागवत ने आर्थिक सुस्ती का जिक्र करते हुए कहा, इस पर बेवजह चर्चा से लोगों और कारोबारियों की धारणा कमजोर हो सकती है। सुस्ती के इस चक्र से भी हम बाहर निकल जाएंगे। सरकार इससे निपटने के लिए उपाय कर रही है।

महाराष्ट्र के नागपुर में मंगलवार को आरएसएस मुख्यालय में आयोजित विजयादशमी उत्सव के दौरान आरएसस प्रमुख मोहन भागवत और एचसीएल के संस्थापक तथा अध्यक्ष शिव नादर। प्रेट्र

संघ प्रमुख ने यह भी कहा

- नई पीढ़ी में आत्म गौरव के लिए शिक्षा पद्धति में बदलाव की जरूरत
- संस्कारों का क्षरण एवं जीवन मूल्यों में गिरावट चिंता का विषय
- नारी सम्मान की परंपरा वाले देश में महिलाओं की असुरक्षा लज्जा का विषय
- मातृशक्ति को सशक्त बनाने के साथ पुरुषों की दृष्टि में भी परिवर्तन जरूरी
- युवा पीढ़ी को नशे के दुष्चक्र से बचाने के लिए बरतनी होगी सतर्कता
- कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास से ही फलीभूत होगा अनुच्छेद 370 पर फैसला
- लोकतंत्र बाहरी व्यवस्था नहीं, भारत की सदियों की परंपरा का हिस्सा

चीन का बदला रुख, कहा भारत और पाक मिलकर सुलझाएं कश्मीर मसला

- **मोदी से मुलाकात से पहले, संयुक्त राष्ट्र में दिए बयान पर साधी चुप्पी**
- **चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग शुक्रवार को भारत आ रहे हैं**

बीजिंग, प्रेट्र : राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भारत यात्रा से ठीक पहले चीन कश्मीर मुद्दे पर अपने पुराने रुख पर लौट आया है। कश्मीर को द्विपक्षीय मसला बताते हुए चीन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत के जरिए इसका समाधान निकालना चाहिए। उल्लेखनीय है कि दो हफ्ते पहले इसी चीन ने कश्मीर मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रस्तावों का राग अलापा था। वामपंथी शासन वाले पड़ोसी देश चीन का यह बयान ऐसे समय में भी आया है, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान राष्ट्रपति चिनफिंग से मिलने मंगलवार को बीजिंग पहुंचे और उससे एक दिन से पाक सेना प्रमुख कमर बाजवा बीजिंग में मौजूद हैं।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने यहां प्रेस कांफ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति चिनफिंग की भारत यात्रा के संबंध में किसी तरह की घोषणा नहीं की। परंतु, चीनी अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से बताया कि राष्ट्रपति की यात्रा के संबंध में बुधवार को बीजिंग और नई दिल्ली में एक साथ घोषणा की जाएगी।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चिनफिंग की मुलाकात में कश्मीर मसला उठाए जाने से संबंधित सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कश्मीर पर चीन का रुख यह है कि भारत और पाकिस्तान को आपस में बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाना चाहिए।

बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद चीन ने अपना रुख बदलते हुए कहा था कि कश्मीर मसले का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के आधार पर निकाला जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में बंद कमरे में हुई बैठक और फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी चीन इसी रुख पर कायम रहा था। भारत ने उसके बयान का कड़ा विरोध किया था।

अब गेंग के मंगलवार के बयान के साथ ही चीन अपने पुराने रुख पर लौट आया है। जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक वार्ता के लिए चिनफिंग की भारत यात्रा को देखते हुए चीन के रुख में यह बदलाव आया है।

भारत-चीन को मिलकर क्षेत्र में शांति-स्थिरता कायम करनी चाहिए पेज>>3

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▶ पृष्ठ 2

केजरीवाल को केंद्र की ना, डेनमार्क दौरा रद

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विदेश मंत्रालय से अनुमति नहीं मिलने के कारण सी-40 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने डेनमार्क नहीं जा पाए। उन्हें डेनमार्क के कोपेनहेगन में नौ से 12 अक्टूबर तक होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को रवाना होना था। सम्मेलन में केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण को 25 फीसद तक कम करने के सरकार के सफल प्रयासों की जानकारी दुनिया के सामने रखते।

महासमर ▶ पृष्ठ 4

मोदी ने बनाया ओबीसी आयोग : अमित शाह

बीड : केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपाध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को महाराष्ट्र के बीड जिले में दशहरा रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी आयोग का गठन करके लगातार वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं का निदान करने में जुटे हुए हैं। जबकि पिछले 70 साल में पिछली सरकारें यह नहीं कर पाईं।

अफगानिस्तान में मारा गया भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का प्रमुख आसिम उमर

- **असिम को अमेरिका ने घोषित किया था वैश्विक आतंकी**
- **उप्र के संभल में जन्मे उमर ने दारुल उलूम देवबंद से किया था स्नातक**

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अफगानिस्तान में हेलमंद प्रांत के मूसाकला जिले में तालिबान के अड्डे पर अमेरिका-अफगानिस्तान के संयुक्त हमले में भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा (एक्यूआइएस) का प्रमुख आसिम उमर मारा गया है। उसका जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ था।

अलकायदा नेता अयमन अल जवाहिरी ने सितंबर, 2014 में एक वीडियो संदेश के जरिये भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में जिहाद के लिए एक्यूआइएस का गठन किया था। तभी से असिम इसका प्रमुख था। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय ने बताया कि तकरीबन 40 वर्ष की आयु वाला आसिम 23 सितंबर को अमेरिका-अफगानिस्तान के संयुक्त हमले में मारा गया। उसके साथ छह अन्य सदस्य भी मारे गए, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे।

असिम को अमेरिका ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ था। 2016 में अमेरिका ने एक्यूआइएस को भी विदेशी आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया था। वह अमेरिका द्वारा विदेशी आतंकी संगठन घोषित पाकिस्तानी आतंकी समूह हरकत उल मुजाहिदीन का पूर्व सदस्य था। सना उल हक के रूप में जन्मे असिम उमर ने कथित रूप से 1991 में दारुल उलूम, देवबंद से स्नातक किया था। बाद में वह पाकिस्तान चला गया, जहां उसने दारुल उलूम हक्कानिया नौशेरा में पढ़ाई की थी, जिसे जिहाद का विश्वविद्यालय' भी कहा जाता है।

एक्यूआइएस ने छह सितंबर, 2016 को कराची में नौसैनिक डॉकयार्ड पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के दौरान आतंकियों ने एक पाकिस्तानी युद्धपोत को अगवा करने की कोशिश की थी। इस संगठन ने बांग्लादेश में कई कार्यकर्ताओं और लेखकों की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। इनमें अमेरिकी नागरिक अभिजित रॉय, अमेरिकी दूतावास का स्थानीय कर्मचारी जुल्हाज मन्नन शामिल हैं। एक अमेरिकी संसदीय उपसमिति के समक्ष सामरिक विशेषज्ञ सेठ जी. जोंस ने कहा था कि 2017 तक एक्यूआइएस ने सैकड़ों सदस्य जोड़ लिए थे और उसके हेलमंद, कंधार, जाबुल, पक्तिका, गजनी में सेल थे। अक्टूबर, 2015 में सुरक्षाबलों ने कंधार प्रांत में एक प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया था जिसमें एक्यूआइएस के सौ से ज्यादा आतंकी मारे गए थे।

बिहार में दशहरा समारोह में नहीं पहुंचे भाजपा नेता

राज्य ब्यूरो, पटना

- **रावण वध से अधिक भाजपा नेताओं की गैर-हाजिरी की चर्चा**
- **राज्यपाल भी नहीं पहुंचे, सुशील मोदी की कुर्सी पर बैठे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष**

पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी समारोह में हर साल की तरह भारी भीड़ उमड़ी पर भाजपा का कोई नेता नजर नहीं आया। नेताओं की गैर-हाजिरी ने बिहार में सियासी चर्चा को नया विषय दे दिया है। यह पहला अवसर है जब राज्य सरकार में शामिल रहने के बावजूद भाजपा नेता समारोह के मंच पर मौजूद नहीं थे। राज्यपाल हालांकि दलगत राजनीति से अलग माने जाते हैं, लेकिन उनकी गैर-मौजूदगी भी खल रही थी। राज्यपाल फागू चौहान को समारोह का उद्घाटन करना था, जबकि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी खास मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे।

भाजपा के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, गांधी मैदान का समारोह उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन वर्षा के कारण शहर के लोग जिस परेशानी को झेल रहे हैं, उसमें हम लोगों के लिए उत्सव मनाना उचित नहीं है। अतः पार्टी ने खुद को समारोह से अलग कर लिया।

जदयू ने नहीं की नकारात्मक टिप्पणी : भाजपा नेताओं की गैर-हाजिरी पर जदयू ने कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं की है। इसके बावजूद सियासी हलके में इसे भाजपा-जदयू के बीच बढ़ते टकराव के रूप में देखा जा रहा है। राजधानी में भीषण जल जमाव के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा भाजपा कोटे के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा राज्य के अफसरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। इन मंत्रियों पर जदयू के प्रवक्ता भी हमलावर रहे हैं, लेकिन, दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर टकराव जाहिर करने जैसे बयान नहीं आए।

मोदी की कुर्सी पर बैठे कांग्रेस अध्यक्ष : यह संयोग ही था कि मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बगल वाली कुर्सी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा बैठे थे। बैठने की इस व्यवस्था को भी सियासी चर्चा में खास महत्व दिया जा रहा है। आम तौर पर ऐसे समारोहों में नीतीश की बगल की कुर्सी सुशील मोदी के लिए ही आरक्षित रहती है। इस बाबत दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कमल नोपनी ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी राज्यपाल समेत सभी प्रमुख मंत्रियों, पटना के सांसदों और विधायकों को निमंत्रण भेजा गया था। वे क्यों नहीं आए, इस पर वे ही बता सकते हैं। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने इस बाबत पूछे जाने पर कहा, जलनिकासी के काम में लगे रहने के कारण कार्यक्रम में नहीं जा सके।

बक्सर के समारोह में शामिल हुए भाजपा नेता : बाढ़ और जलजमाव का हवाला देकर भाजपा नेता भले ही पटना के गांधी मैदान के कार्यक्रम में अनुपस्थिति की बात कर रहे हों, बक्सर में विजयदशमी समारोह में स्थानीय सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे शामिल हुए थे।

इंतजार खत्म

रक्षा मंत्री राजनाथ ने विमान पर ओम लिखा, नारियल-फूल चढ़ाकर की शस्त्र पूजा, तीस मिनट की उड़ान भर कर विमान हासिल करने का किया शुभारंभ, दक्षिण एशिया में बढ़ेगा भारत का दबदबा

विजयादशमी पर भारतीय वायुसेना को मिली राफेल की शक्ति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

विजयादशमी के दिन भारत ने दुनिया के सबसे मारक लड़ाकू जेट विमान राफेल को औपचारिक तौर पर हासिल कर लिया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में एक गरिमापूर्ण समारोह में बहुप्रतीक्षित राफेल विमान को प्राप्त किया। उन्होंने भारत को मिले पहले राफेल का विधि विधान से शस्त्र पूजन कर भारतीय वायुसेना की सामरिक ताकत में हो रहे इजाफे का शंखनाद किया। राफेल-आरबी 001 में आधे घंटे की उड़ान भर कर रक्षा मंत्री ने भारत के बढ़ते सैन्य पराक्रम का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राफेल का अर्थ हिंदी में आंधी है और उम्मीद है कि यह विमान दुश्मनों के खिलाफ अपने नाम को चरितार्थ करेगा।

फ्रांस के मेरीनेक एयरबेस पर राफेल बनाने वाली कंपनी दासौ और फ्रांसीसी सैन्य मंत्री की मौजूदगी में मंगलवार को हुए समारोह में राजनाथ सिंह को राफेल सौंपने की औपचारिकता पूरी की गई। भारत को राफेल मिलने से दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा बढ़ेगा। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी के नापाक इरादे पस्त होंगे। इस मौके पर सिंह ने कहा कि आज भारतीय वायुसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत में आज विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। वहीं आज 87वां वायुसेना दिवस भी है। रक्षा मंत्री ने कहा, 'हमारा फोकस वायुसेना की क्षमता बढ़ाने पर है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी राफेल विमान की तय समयसीमा पर आपूर्ति हो जाएगी।

राफेल हासिल करने के बाद राजनाथ सिंह ने भारतीय परंपरा और विधि विधान से शस्त्र पूजा की। इस दौरान रक्षा मंत्री ने विमान के अगले हिस्से पर कुमकुम का तिलक लगाया और ओम लिखा। फूल और नारियल भी रखे। पूजा विधि के अनुसार विमान के डैने पर सिंह ने रक्षा सूत्र बांधा। राफेल की शस्त्र पूजा के दौरान बुरी नजर से बचाने के लिए दोनों पहियों के नीचे नीबू भी रखा गया। पूजा के बाद 68 वर्षीय राजनाथ सिंह ने राफेल में करीब तीस मिनट की उड़ान भी भरी।

विजयादशमी पर मंगलवार को फ्रांस में भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान सौंपा गया। इस मौके पर मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विमान की विधिपूर्वक शस्त्र पूजा की। बुरी नजर से बचाने के लिए पहियों के नीचे नीबू भी रखा गया। इसके बाद राजनाथ ने राफेल में उड़ान भी भरी। एएफपी

आरबी 001 के भारत आने की उल्टी गिनती शुरू

राफेल के पहले विमान आरबी 001 को हासिल करने के साथ ही इस बेहद मारक लड़ाकू जेट के भारत आने की उलटी गिनती भी शुरू हो गई है। भारतीय वायुसेना के पायलट राफेल उड़ानें और इसके तकनीकी प्रबंधन का प्रशिक्षण हासिल करने के लिए पहले ही फ्रांस पहुंच गए हैं। राफेल से 1500 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद इस विमान को मई 2020 में भारत लाया जाएगा। चार राफेल विमानों का पहला जत्था भारतीय वायुसेना को अगले साल मई में मिलेगा। एक रोचक तथ्य यह है कि भारतीय वायुसेना के पहले राफेल लड़ाकू विमान के पिछले हिस्से यानी टेल पर आरबी 01 लिखा है। यह नए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेस भदौरिया के नाम पर है।

पहले चार राफेल विमानों को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। पेज>>5

जमीन से लेकर आकाश तक फिर 'अभिनंदन'

गाजियाबाद : वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर लोगों के जेहन में बालाकोट एयरस्ट्राइक और विंग कमांडर अभिनंदन के 'ऑपरेशन पराक्रम' की वीरता की यादें फिर ताजा हो गईं। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित वायुसेना दिवस समारोह में विंग कमांडर अभिनंदन ने एयर-शो में जैसे ही मिग-21 बायसन विमान से उड़ान भरी हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। (पेज-5)

ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने वाले तीन वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल

स्टॉकहोम : ब्रह्मांड के विकासक्रम और अनंत ब्रह्मांड में हमारी स्थिति को समझने की दिशा में अहम शोध करने वाले तीन वैज्ञानिकों को इस साल भौतिकी के नोबेल के लिए चुना गया है। इनमें कनाडाई मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स और स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर व डिडियर क्यूलोज शामिल हैं। शोध की महत्ता को देखते हुए पीबल्स को पुरस्कार की आधी राशि मिलेगी। शेष आधी राशि अन्य दोनों वैज्ञानिकों में बराबर बांटी जाएगी। (पेज-16)

32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया मंगलवार को राजधानी में। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मंगलवार का एयर इंडेक्स 112 रहा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 9 अक्टूबर 2019

बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव...

राजधानी में मंगलवार को विजयादशमी के पावन अवसर पर बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए गए। इस दौरान राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। आइपी एक्सटेंशन स्थित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में तीर चलाकर रावण का पुतला दहन करते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इस दौरान उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रहीं (बाएं)। साथ ही लालकिला मैदान में लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भगवान राम, लक्ष्मण व हनुमान की आरती करते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (मध्य)। लालकिला मैदान में नवश्री धार्मिक लीला में तीर चलाकर रावण का वध करते पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (दाएं)। जागरण

केजरीवाल को केंद्र सरकार की ना, डेनमार्क दौरा रद

रखा पक्ष ▶ विदेश मंत्रालय ने सम्मेलन की प्रकृति का दिया हवाला

दिल्ली के मुख्यमंत्री को सी-40 शिखर सम्मेलन में लेना था हिस्सा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सी-40 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए डेनमार्क नहीं जा पाए। उन्हें विदेश मंत्रालय से उनकी यात्रा के लिए मंजूरी नहीं मिल सकी। मुख्यमंत्री का मंगलवार दोपहर दो बजे डेनमार्क के कोपेनहेगन में सम्मेलन के लिए जाने का कार्यक्रम था। सम्मेलन 9 अक्टूबर को शुरू हो रहा है और 12 अक्टूबर तक चलेगा।

मुख्यमंत्री को आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना था। इस सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक दिल्ली के नेता के रूप में केजरीवाल को आमंत्रित किया गया था। केजरीवाल दुनिया के उन 20 नेताओं में शामिल होने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जा रहे थे जो इस बात का प्रण लेंगे कि लघु और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं से अपने-अपने शहर की हवा को स्वच्छ किया जाए। अरविंद केजरीवाल को सम्मेलन के मंच से दिल्ली के प्रदूषण को 25 फीसद तक कम करने के लिए सरकार की ओर से किए गए सफल प्रयास की जानकारी दुनिया के सामने रखते।

विदेश मंत्रालय ने कहा : विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा- मैं राजनीतिक मंजूरी के लिए सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। यदि आप समझदार हैं तो आपको इसकी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी होगी। हमें हर महीने मंत्रालयों, सचिवों, नौकरशाहों से राजनीतिक मंजूरी के लिए सैकड़ों अनुरोध मिलते हैं। एक निर्णय कई सूचनाओं पर आधारित होता है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की प्रकृति का भी ध्यान रखा जाता है, जहां व्यक्ति भाग लेने जा रहा है।

संजय सिंह ने कहा-केंद्र से अनुमति न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण : अरविंद केजरीवाल को डेनमार्क जाने की अनुमति न मिलने पर आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सीएम केजरीवाल छुट्टी मनाने के लिए डेनमार्क नहीं जा रहे थे। एशिया के 100 शहरों के मेयरों से प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लड़ने के तरीकों के विषय में चर्चा करने जा रहे थे।

सिंह ने कहा कि हमने सवा महीने पहले आवेदन किया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिल सकी। जबकि बंगाल सरकार के शहरी विकास मंत्री फरहाद हाकिम ने विदेश जाने के लिए सप्ताह भर पहले आवेदन किया और उन्हें अनुमति मिल गई। इससे पता चलता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इससे उन लोगों को क्या संदेश मिला जो सम्मेलन में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले पिछले साल भी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मास्को और दो साल पहले मोहल्ला क्लीनिक योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने से भी रोका गया था।

डेनमार्क में बताना था, कैसे कम किया प्रदूषण

- चार साल पहले तक दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल थी। वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सफलता मिली।
- मुख्यमंत्री को दिल्ली में बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रयास पर प्रकाश डालना था।
- किस तरह जेनरेटर सेट का चलन दिल्ली में लगभग बंद हुआ।
- कैसे 95 फीसद उद्योगों के सीएनजी में शिफ्ट होने से औद्योगिक प्रदूषण में गिरावट आई। दो थर्मल पावर प्लांट को बंद किया।
- किस तरह सरकार के प्रयास से निर्माण स्थलों से होने वाले प्रदूषण में कमी देखने को मिली। हरियाली का दायरा बढ़ा।
- मुख्यमंत्री एशियन मेयर और सिटी लीडर्स कम कार्बन समावेशी विकास बैठक नामक शिखर सम्मेलन के दौरान एक कार्यक्रम में वरिष्ठ वक्ता भी थे।

'विजयादशमी पर लोग पर्यावरण संरक्षण का लें संकल्प'

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

विजयादशमी पर प्रभु श्रीराम ने अहंकारी रावण पर जीत दर्ज कर बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया। भारतवासियों को इस दिन पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। भगवान राम की परंपराएं, आदर्श आज भी विश्व में प्रासंगिक हैं। यह बातें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामलीला के मंच से कहीं।

दशहरे पर राष्ट्रपति अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ पूर्वी दिल्ली के आइपी एक्सटेंशन स्थित श्रीरामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ में पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने श्रीराम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की आरती की और उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने मंच से तीर छोड़कर रावण, मेघनाद, कुंभकरण के साथ चौथी बुराई पंच सर्प कालिया (वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक और लैंडफिल साइट) के पुतले का दहन किया। इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने यमुनापार की रामलीला में पहुंचकर रावण के पुतले का दहन किया। राष्ट्रपति ने अपने आठ मिनट के भाषण में रामचरित मानस, महात्मा गांधी और पर्यावरण स्वच्छता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस पर्यावरण स्वच्छता का संदेश देती है। भगवान राम कण-कण में बसे हैं। उन्होंने कहा रामलीला के मंच से पर्यावरण और जल संरक्षण का संदेश दिया जाना चाहिए।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि रामलीलाओं में प्रतिस्पर्धा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में रामराज्य लाना चाहते हैं, इस काम में हर नागरिक साथ दे। विजयादशमी पर यह शपथ लें। उन्होंने कहा कि यमुनापार के लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रपति ने यहां आकर रावण के पुतले का दहन किया। रामलीला समिति के प्रधान सुरेश बिंदल ने राष्ट्रपति को शॉल और अन्य पदाधिकारियों ने गदा, त्रिशूल आदि भेंट किए।

वेंकैया ने सामाजिक बुराइयों पर विजय पाने की दी नसीहत

लालकिला मैदान में श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शांति के प्रतीक कबूतर को उड़ाते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। संजय

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दशहरे के मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों से सामाजिक बुराइयों पर विजय पाने को कहा। उन्होंने कहा कि जातिवाद, कट्टरवाद, छुआछूत और भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयां समाज और देश के विकास में बाधक हैं। इन पर विजय पाना आवश्यक है। वह लाल किला की श्रीधार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने सांकेतिक तीर छोड़कर रावण का दहन किया और शांति के प्रतीक कबूतर छोड़े। उनके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व लीला समिति के अध्यक्ष धीरजधर गुप्ता भी मौजूद थे।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वां जन्मदिवस मना रहे हैं, जिन्होंने भारत में राम राज्य का सपना देखा था। राम राज्य को हम एक आदर्श राज्य मानते हैं। जिसका नैतिकता और न्याय प्रमुख प्रतीक है।

साउंड इफेक्ट से हुआ धूम-धड़ाका : पर्यावरण रक्षा के लिए लाल किला की श्री धार्मिक लीला ने अनूठा प्रयोग किया। लीला में रावण, मेघनाद और कुंभकरण का पुतला तो जला पर पटाखे नहीं फोड़े गए। हालांकि धूम-धड़ाके में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि पटाखों की आवाज साउंड इफेक्ट से निकाली गई।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लाल किला की नवश्री धार्मिक रामलीला में प्रतीकात्मक तीर छोड़कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।

दिल्ली वालों संग कनॉट प्लेस में दीपावली मनाएंगे केजरीवाल

जासं, नई दिल्ली : प्रदूषण के खिलाफ जारी जंग में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बार दीपावली दिल्लीवालों के संग कनॉट प्लेस में मनाएंगे। छोटी दीपावली के दिन कनॉट प्लेस में सरकार द्वारा खास लेजर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए केजरीवाल ने सभी दिल्लीवालों को आमंत्रित किया है। लालकिला में लवकुश रामलीला में अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक रावण, मेघनाथ व कुंभकरण के पुतला दहन के अवसर पर पहुंचे केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदूषण के खिलाफ जंग जारी है। इसपर हमें विजय पाना है। यह अच्छी बात है कि हम सब के प्रयासों से इस युद्ध में कुछ सफलता पाई है। खुशी है कि दिल्ली में प्रदूषण 25 फीसद तक कम हो गया है, लेकिन यह जंग जारी है।

सीएम ने कहा, हमने दीपावली दिल्ली वालों के संग मनाने का फैसला किया है। कनॉट प्लेस में लेजर शो का आयोजन होगा। लोग पूजा पाठ कर इस आयोजन में शामिल होने आएं। पर शर्त यह है कि लोग इस दीपावली पर पटाखे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने डेंगू के खिलाफ अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोगों ने डेंगू का वध करके दिखा दिया है। चिकित्सक और विशेषज्ञ कहते थे कि इस बार डेंगू का मामला बहुत बढ़ेगा। इसे लेकर दिल्ली सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि इस बीमारी के खिलाफ जंग जारी रखें। एक ही महीने की बात है। 15 नवंबर तक ही डेंगू होता है। उसके बाद चिंता की कोई बात नहीं होगी। इसके पहले उन्होंने प्रतीकात्मक तीन तीर छोड़कर रावण, मेघनाथ व कुंभकरण का वध किया।

एम्स में दिसंबर में शुरू होगा बर्न व प्लास्टिक सर्जरी सेंटर

▶ 102 बेड और छह ऑपरेशन थियेटर की होगी सुविधा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

एम्स में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी सेंटर बनकर तैयार है। एम्स प्रशासन इसे जल्द शुरू करने की तैयारी में है। उम्मीद है कि दिसंबर में एम्स में बर्न व प्लास्टिक सर्जरी सेंटर शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि बेड क्षमता के मामले में यह सफदरजंग अस्पताल के बर्न सेंटर के लगभग बराबर होगा, लेकिन एम्स के बर्न व प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही रिकंस्ट्रक्टिव व प्लास्टिक सर्जरी की बेहतर सुविधा मिल पाएगी।

मौजूदा समय में बर्न के इलाज की सुविधाएं दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सीमित है। यही वजह है कि सफदरजंग अस्पताल के 108 बेड के बर्न सेंटर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश व बिहार से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। इस वजह से सफदरजंग अस्पताल के बर्न सेंटर में पीड़ितों को बेड मिल पाना मुश्किल होता है। वैसे दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के अलावा आरएमएल व लोकनायक अस्पताल में भी बर्न का अलग वार्ड है। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में काफी संख्या में ऐसे हादसा पीड़ित पहुंचते हैं जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि एम्स में बर्न व प्लास्टिक सर्जरी के सेंटर की जरूरत महसूस की जा रही थी। ट्रॉमा सेंटर के परिसर में बर्न व प्लास्टिक सर्जरी सेंटर का भवन करीब तैयार है। इसमें 102 बेड की सुविधा होगी। जिसमें 30 आइसीयू बेड शामिल होंगे। इसके अलावा इसमें छह ऑपरेशन थियेटर होंगे। एम्स के अनुसार अभी तक बर्न सेंटर का भवन अस्पताल प्रशासन को सुपुर्द नहीं हुआ है। क्योंकि फायर व अन्य संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की प्रक्रिया चल रही है। अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद इस सेंटर में चिकित्सा सुविधाएं शुरू करने का रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन एक साथ पूरे बेड क्षमता के अनुसार इसका संचालन शुरू नहीं हो पाएगा। इसलिए शुरुआत में कम बेड क्षमता के साथ इसमें इलाज शुरू होगा। एम्स में बर्न व प्लास्टिक सर्जरी का विभाग पहले से कार्यरत है, जिसमें पांच फैकल्टी हैं। इसलिए कम बेड क्षमता के साथ इलाज शुरू करने में डॉक्टरों की कमी आड़े नहीं आएगी। बाद में अगले साल इसमें सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

एलपीजी सिलेंडर फटने से मां-बेटी की मौत

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली

न्यू सभापुर गुजरान स्थित मकान में इसी जगह हुई सिलेंडर फटने की घटना। जागरण

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू सभापुर गुजरान में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे आग लगने से एलपीजी के दो सिलेंडर फट गए। इस हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के समय मैकेनिक राजेश सिलेंडर रिसाव बंद करने का प्रयास कर रहा था। हादसे में मां-बेटी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रामश्री देवी (62) और इनकी बेटी हेमलता (38) के रूप में हुई है। वहीं घायल मैकेनिक राजेश (42) का सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों को जीटीबी अस्पताल में रखवा दिया है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर बिना पोस्टमार्टम के शव देने की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समझाने पर वह माने। करावल नगर थाना पुलिस केस दर्जकर मामले की जांच कर रही है।

हेमलता परिवार के साथ 246, न्यू सभापुर में रहती थीं। आठ साल पहले उनके पति प्रवीण की मौत हो गई थी। हेमलता का एक बेटा अरुण (18) और एक बेटी कशिश (12) है। घर से थोड़ी दूरी पर ही हेमलता का मायका है, वहां उनके पिता इंद्रपाल पत्नी रामश्री और दो बच्चों के साथ रहते हैं। मंगलवार को विजयादशमी का त्योहार होने की वजह से रामश्री बेटी के घर प्रसाद लेकर गई थीं। मां के आने पर हेमलता रसोई में चाय बनाने लगीं। इस दौरान उन्होंने सिलेंडर से गैस रिसाव होते देखा। हेमलता ने मैकेनिक राजेश को रिसाव ठीक करने के लिए बुलाया। रसोई में उस वक्त मां-बेटी के अलावा राजेश था। रिसाव को ठीक करते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई और कुछ सेकेंड बाद ही वह फट गया। इसकी चपेट में आने से रसोई में रखा दूसरा सिलेंडर भी फट गया। इससे रामश्री और हेमलता के शरीर के चिथड़े उड़ गए। वहीं राजेश बुरी तरह झुलस गया। रसोई में आग लग गई। सिलेंडर के धमाके की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस और कैट्स एंबुलेंस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एंबुलेंस से राजेश को जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जबकि मां-बेटी के शवों को शवगृह में रखवा दिया। दमकल की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जीटीबी में राजेश की हालत बिगड़ने पर उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। हादसे के वक्त हेमलता का बेटा काम पर गया हुआ था और बेटी मौसी के घर मंडोली गई हुई थी। हेमलता भी एक जींस की फैक्ट्री में काम करती थीं। मंगलवार को दशहरा की छुट्टी की वजह से घर पर थीं। मृतकों के परिजनों का आरोप है दमकल की गाड़ियां काफी देरी से पहुंचीं, जबकि दमकल विभाग के अधिकारियों ने आरोपों को नकारा है।

ग्रामसभा की जमीन अब अपने कब्जे में लेगा डीडीए

▶ पिछले 62 वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण को नहीं मिल सका है कब्जा

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

दिल्ली में ग्रामसभा की जमीन पर अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का कब्जा होगा। डीडीए ने दिल्ली सरकार से इसे अपने अधीन लेने की तैयारी कर ली है। पहले चरण में डीडीए को लगभग 250 हेक्टेयर जमीन मिलने के आसार हैं। इस सारी जमीन को लैंडपूलिंग पॉलिसी में शामिल किया जाएगा।

यूं तो दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामले डीडीए के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन सन 1957 में हुए डीडीए के गठन से लेकर अभी तक भी डीडीए के पास ग्रामसभा की जमीन का कब्जा नहीं है। दरअसल, यह जिम्मेदारी पहले दिल्ली प्रशासन एवं अब दिल्ली सरकार की है कि वह ग्रामसभा की जमीन को अधिग्रहीत कर उसे डीडीए के सुपुर्द करे। यदि इस जमीन पर कहीं अतिक्रमण है, तो उसे हटाने का दायित्व भी दिल्ली सरकार का ही है। दिल्ली सरकार ग्रामसभा की जमीन को अधिग्रहीत तो करती रही है, लेकिन उसे डीडीए को सौंपने की प्रक्रिया कागजों तक ही सिमटकर रह गई।

डीडीए अधिकारियों के मुताबिक जमीन की सुपुर्दगी के लिए उसका सीमांकन और सर्वे होना जरूरी है, जो कराया ही नहीं जाता। इसलिए पिछले 62 वर्षों में भी डीडीए को इस जमीन का कब्जा नहीं मिल पाया है। उपराज्यपाल एवं डीडीए के अध्यक्ष अनिल बैजल के इस दिशा में लगातार किए गए प्रयासों के फलस्वरूप अब जल्द ही दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग डीडीए को यह जमीन सौंप देगा। डीडीए को उम्मीद है कि पहले चरण में उसे ग्रामसभा की 200 से 250 हेक्टेयर तक जमीन मिल जाएगी। इस जमीन को लैंडपूलिंग पॉलिसी में उन जोनों में इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पर अभी तक न्यूनतम 70 फीसद जमीन एकत्र नहीं हो पाई है।

> ग्रामसभा की जमीन डीडीए की है, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिल सका। अब उपराज्यपाल के सहयोग से जल्द ही यह कब्जा मिल जाएगा। ग्रामसभा की यह जमीन मिल जाने से न सिर्फ लैंडपूलिंग पॉलिसी को रफ्तार मिलेगी, बल्कि दिल्ली की विकास योजनाओं में भी इस जमीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
> **-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए**

तैयारी

राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा हासिल इस मकबरे के संरक्षण की योजना बनाई है एएसआइ ने, इसके तहत जौक की कब्र के आसपास के क्षेत्र की दशा सुधारी जाएगी

कौन जाए जौक, दिल्ली की गलियां छोड़कर ...

वी.के. शुक्ला, नई दिल्ली

शेर-ओ-शायरी की बात आती है तो सभी कुछ गालिब पर आकर ही अटक जाता है, मगर यहां जौक भी ऐसे शायर हुए हैं जिन्होंने देश और दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया है। 'कौन जाए जौक, दिल्ली की गलियां छोड़कर' यह शेर कहने वाले दिल्ली पर फिदा मशहूर शायर जौक कहीं बाहर नहीं गए और यहीं रह भी गए। मगर जौक को शायद पता नहीं था कि दिल्ली उन्हें ऐसे भुला देगी। नबी करीम इलाके में स्थित शेख इब्राहीम जौक की मजार पर वीरानी छाई है। जौक अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर थे।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा दिया है। मगर अब इसकी हालत ऐसी नहीं रहेगी। एएसआइ ने इसके संरक्षण की योजना बनाई है। योजना के तहत उनकी कब्र के आसपास के क्षेत्र की दशा सुधारी जाएगी। स्मारक के अंदर के फर्श का संरक्षण कार्य किया जाएगा। प्रवेश द्वारा को इस तरह बनाया जाएगा कि वह बेहतर दिखे। इस स्मारक तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता पहाड़गंज में होटल टुडे के पास से संकरी गली से है जो करीब एक किलोमीटर अंदर जाने के बाद इस स्मारक तक पहुंचती है। दूसरा रास्ता कुतुब रोड से है। इन दोनों रास्तों पर अब सूचना बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसपर स्मारक के इतिहास के बारे में जानकारी लिखी होगी। जौक की मजार नबी करीम की चिन्नौर बस्ती में है। 1996 में यहां पहले से बने शौचालय को हटाकर उच्च न्यायालय के दखल से जौक की मजार को फिर से सम्मानित तरीके से स्थापित किया गया। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) का स्मारक है।

जौक का मकबरा। जागरण

शेख इब्राहीम जौक का जन्म 1789 में दिल्ली के काबुली दरवाजा निवासी एक सिपाही शेख रमजान के घर हुआ था। इनमें शुरू से ही शायरी के प्रति दीवानगी थी और बड़े होकर मात्र 19 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर के दरबार में उस्ताद की पदवी मिली। जौक कभी सुल्तान के दरबार में महज चार रुपये माह के वेतन पर मुलाजिम हुआ करते थे। बाद में जब जफर सत्ता पर काबिज हुए तो उनका वेतन चार रुपये से बढ़ाकर सौ रुपये कर दिया गया। जिस वक्त देश में आजादी को लेकर पहली क्रांति जन्म ले रही थी उस वक्त तक जौक दरबार में बतौर शाही शायर रहे। जौक की शायरी की सबसे खास बात थी कि उनके हर कलाम में बेहद आम और हल्के फुल्के शब्द हुआ करते थे।

एक आंसू ने डुबोया मुझको उनकी बज्म में।
बूंद भर पानी से सारी आबरू पानी हुई।।

यही वजह थी कि उनके कलाम जल्द ही लोगों को समझ में आ जाया करते थे। वो तुरंत गजल कहने में माहिर थे। 1854 में शायरी की दुनिया का यह चमकता सितारा आसमान में कहीं खो गया।

जौक के कुछ शेर

इन दिनों गरचे दकन में है बड़ी क़द्र-ए-सुखन।
कौन जाए ज़ौक़, दिल्ली की गलियां छोड़ कर।।
जब तक मिले न थे जुदाई का मलाल था।
अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई।।

ममेरे भाई ने की थी मुथुट कंपनी के प्रबंधक की हत्या

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

उत्तर प्रदेश के बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते जून के महीने में मुथुट फिनकार्प कंपनी के प्रबंधक आजाद की गोली मारकर हुई हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। प्रबंधक की हत्या की वारदात को उसके ममेरे भाई परविंदर ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। परविंदर कंपनी का चार किलो सोना लूटना चाहता था, लेकिन प्रबंधक इस योजना में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। इस वजह से आरोपित ने प्रबंधक की हत्या कर दी। घटना में शामिल दो आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि दो अभी फरार है।

एसएसपी वैभव कृष्ण ने बताया कि बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में कल्दा नहर की पुलिया के पास बीते 20 जून को एक अज्ञात युवक का शव पड़ा मिला था। इसकी पहचान हापुड़ के काठी खेड़ा गांव के रहने वाले आजाद के रूप में हुई थी। आजाद मुथुट फिनकार्प लिमिटेड गाजियाबाद की शाखा में प्रबंधक के पद पर तैनात थे। परिजन ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। बादलपुर कोतवाली प्रभारी पटनीश कुमार की टीम ने मामले में सीसीटीवी से अहम सुराग हासिल किया। इसके आधार पर पुलिस ने प्रबंधक आजाद के ममेरे भाई परविंदर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने बताया कि उसने कुछ दिनों पहले आजाद से दस हजार रुपये उधार लिए थे। आजाद उस पर रुपये पैसे वापस करने का दबाव बना रहा था। आरोपित ने बताया कि 20 जून को परविंदर ने उधार के रुपये वापस देने की बात कहकर आजाद को कलदा गांव के समीप बुलाया था। जहां परविंदर के तीन साथी चमनलाल, दीपक और सुनील पहले से मौजूद थे। आरोपितों ने पहले आजाद को शराब पिलाई। जिसके बाद उसके बैग से उसके लॉकर की चाबी निकाल ली। इसके बाद आरोपित चाबी लेकर कंपनी की शाखा में पहुंचे और लॉकर खोलकर सोना लूटने का प्रयास किया। लेकिन लॉकर नहीं खुला। उन्होंने यह बात आजाद को बताई तो वह नाराज हो गया। इस पर आरोपितों ने आजाद की गोली मारकर हत्या कर दी।

प्रबंधक की हत्या करने वाले आरोपितों के बारे में जानकारी देते एसएसपी वैभव कृष्ण। जागरण

4378 शहरी निकायों में से अब तक 4284 निकायों ने खुद को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया है। शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़ों में यह बात सामने आई।

पात्रता के फेर में फंसे देश के करीब 12 लाख शिक्षक

कानूनी पेच ▶ बिहार से शुरू हुई समस्या, दूसरे राज्यों में भी होने लगी सुगबुगाहट

18 माह के प्रशिक्षण को शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता में नहीं किया गया शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रतीकात्मक फोटो

देश के करीब बारह लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने तय समय में नया प्रशिक्षण पूरा करके भले ही अपनी मौजूदा नौकरी को जाने से बचा लिया है, लेकिन भविष्य की उनकी राहें फिलहाल बंद है। वजह स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) की अर्हता का एक नियम है। इसके तहत दो साल का डीईएलएड (डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन) करने वाले ही इसके पात्र हैं। ऐसे में 18 महीने का विशेष डीईएलएड कोर्स करने वाले इन लाखों शिक्षकों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है। वह इस कोर्स के आधार पर कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकते हैं।

हालांकि इस सब के बीच देश भर के इन अप्रशिक्षित शिक्षकों को यह विशेष कोर्स कराने वाली मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संस्था एनआइओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। संस्थान का कहना है कि उनकी डीईएलएड के कोर्स में कोई कमी नहीं है। वह डीईएलएड के दो साल के कोर्सों जैसी ही है। सरकार ने शिक्षकों के शिक्षण अनुभव को देखते हुए उन्हें राहत देते हुए 18 महीने में कराया है। जिसे एनसीटीई की भी मंजूरी है। ऐसे में वह इसके आधार पर कहीं भी नौकरी करने के लिए पात्र हैं। वहीं इस विवाद के बढ़ने पर एनसीटीई ने चुप्पी साध ली है। खास बात है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों के इस प्रशिक्षण में निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक शामिल थे। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा थे।

वहीं इस पूरे विवाद की शुरुआत भी बिहार में शिक्षकों की भर्ती से शुरू हुई। इस दौरान निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले उन शिक्षकों ने भी इसके लिए आवेदन किया, जिन्होंने सरकार के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एनआइओएस से 18 महीने का डीईएलएड कोर्स किया था। इस बिहार सरकार ने एनसीटीई से इसे लेकर सलाह मांगी, तो एनसीटीई ने सीधे तौर पर कुछ कहे बगैर स्कूली शिक्षकों की अर्हता को लेकर पूर्व में जारी की गई गाइडलाइन उन्हें भेज दी, लेकिन इनमें कहीं भी 18 महीने के डीएलएड कोर्स करने वालों का जिक्र नहीं था। इसके बाद से विवाद बढ़ गया है। अब यह बिहार के साथ दूसरे राज्यों में भी तूल पकड़ने लगा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की मानें तो इसे लेकर मंत्रालय ने यदि जल्द ही हस्तक्षेप कर एनसीटीई की अर्हता में बदलाव नहीं किया, तो यह विवाद देश भर में तेजी से फैल सकता है।

गौरतलब है कि इन सभी शिक्षकों को यह खास प्रशिक्षण शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के उन प्रावधानों के तहत दिया गया है, जिसमें 2014 के बाद वह बगैर प्रशिक्षण के नहीं पढ़ा सकते थे। हालांकि यह काम 2014 तक जब नहीं हो पाया, तो सरकार ने संसद में आरटीई में संशोधन कर इसे पूरा करने मार्च 2019 तक का लक्ष्य रखा था। जो अब हो पूरा गया है।

हर साल 15 अगस्त तक विदेशी छात्रों को प्रवेश की दे दी जाए सूचना

माला दीक्षित, नई दिल्ली

- एमबीबीएस प्रवेश मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश
- कोर्ट के आदेश पर सात विदेशी छात्रों को प्रवेश की अंतिम तिथि बीतने के बाद एम्स में एमबीबीएस के कोर्स में मिला दाखिला

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रायोजित श्रेणी में एमबीबीएस प्रवेश मामले में निर्देश दिया है कि वह हर साल प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 15 दिन पहले चयनित विदेशी छात्रों को प्रवेश की सूचना देगी। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष प्रवेश के लिए छात्रों के नाम मंजूर किए जाने की सूचना छात्रों को 15 अगस्त तक दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश इसलिए दिए ताकि देर से सूचना पाने के कारण विदेशी छात्र प्रवेश से वंचित न रह जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतिम तिथि बीतने के बाद सात विदेशी छात्रों को एम्स में प्रवेश देने का आदेश दिया।

यह मामला प्रायोजित श्रेणी से विकसित देशों के छात्रों को एम्स में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश का था। अंतिम तिथि बीतने के कारण एम्स द्वारा प्रवेश देने से मना किए जाने के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। कोर्ट गए सात विदेशी छात्रों में तीन लड़कियां और चार लड़के हैं। जिसमें से एक ईरान, दो भूटान और चार नेपाल के हैं।

जस्टिस एल. नागेश्वर राव व जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त आदेश दिए। ईरानी छात्रा आरेफी किगनी के वकील आरके गुप्ता ने कोर्ट से एम्स को प्रवेश लेने का आदेश देने की मांग करते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय ने 30 अगस्त को प्रवेश के लिए छात्रा का नाम मंजूर होने की सूचना भेजी थी। विदेश से यहां आने में समय लगता है। जब छात्रा दो सितंबर को प्रवेश लेने एम्स पहुंची तो एम्स ने यह कहते हुए मना कर दिया कि प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त बीत चुकी है। गुप्ता ने कहा कि छात्रा की कोई गलती नहीं है फिर भी उसे प्रवेश नहीं दिया गया। उन्होंने पीठ को गत वर्ष का आदेश दिखाया जिसमें कोर्ट ने ऐसे ही विदेशी छात्रों को प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाई थी। नेपाल और भूटान के छात्रों की ओर से भी यही दलीलें दी गईं। कोर्ट ने बहस सुनने के बाद कहा कि इस साल और पिछले साल की घटनाओं को देखते हुए कोर्ट का यह मानना है कि प्रायोजित श्रेणी के विदेशी छात्रों को सरकार को प्रवेश की अंतिम तिथि से कम से कम 15 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त तक सूचना दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में संबंधित देश और संबंधित राज्यों की अथारिटी को उम्मीदवारों के बारे में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। मालूम हो कि एमएमबीबीएस प्रवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश का शिड्यूल तय कर रखा है जिसके मुताबिक, प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अगस्त है।

पनामा पेपर्स मामले में कर चोरों के नाम गुप्त रख सकता है ईडी

▶ केंद्रीय सूचना आयोग ने किया प्रावधान

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना आयोग ने स्थापित किया है कि पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय कर चोरी करने के आरोपितों के नाम को अपने तक सीमित रख सकता है। सूचना आयुक्त बिमल जुल्का ने कहा कि इस मामले के तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर जवाबदेह जनप्रशासन आरटीआइ अधिनियम, 2005 की धारा 24(1) के तहत इस मामले में अब और दखल की जरूरत नहीं है।

दुर्गा प्रसाद चौधरी की आरटीआइ याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसी से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने यह फैसला सुनाया है। वर्ष 2017 में चौधरी ने पनामा पेपर्स के मामले में तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। पहला : सूची में शामिल लोगों के नाम, दूसरा : लीक पर की गई कार्रवाई और तीसरा : जांच में देरी के लिए जिम्मेदार अफसर। जब जांच एजेंसी ने धारा 24 (1) के तहत मामले की जानकारी देने से इन्कार किया तो यह मामला आरटीआइ मामलों की सर्वोच्च संस्था में पहुंच गया।

मामले की सुनवाई के दौरान चौधरी ने कहा कि उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का यह गंभीर मामला है। उसके बाद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने आयोग का ध्यान पनामा मामले की राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों की ओर भी आकृष्ट किया। इनमें कुछ नामों का उल्लेख किया गया था, जो पनामा पेपर्स मामले से जुड़े हुए थे।

इस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का भी कहना था कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं देने की छूट है क्योंकि मामला अदालत में विचाराधीन है। इसलिए मामले से जुड़ी जानकारियां साझा नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआइ अधिनियम की धारा 24(1) के तहत कुछ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को पारदर्शिता कानून से छूट दी गई है। इन्हें तभी जारी किया जा सकता है, अगर आरोप भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के हों।

भारत–चीन को मिलकर क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करनी चाहिए

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीन के राजदूत सुन वीडांग ने मंगलवार को यहां कहा कि भारत और चीन को आपसी विवादों को क्षेत्रीय स्तर पर बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की भारत यात्रा से पहले चीनी राजदूत ने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि दोनों देशों को पंचशील के सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। उल्लेखनीय है कि चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग शुक्रवार को चेन्नई पहुंचेंगे। शनिवार को तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मामल्लापुर (महाबलीपुरम) में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। अभी तक चिनफिंग की यात्रा को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन मामल्लापुर में शिखर बैठक को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मामल्लापुर शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच बातचीत आपसी विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही समग्र संबंधों को विस्तार देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर केंद्रित रहेगी।

रैंक से नीचे के काम देने पर सीआरपीएफ में विवाद

- प्रोबेशनरी आइपीएस अफसरों के कार्यक्रम के लिए जारी सर्कुलर पर उठे सवाल
- असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अफसर को स्वच्छता प्रबंधन, खाने का इंतजाम देखने को कहा गया

नई दिल्ली, एएनआइ : सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के अधिकारियों के लिए जारी किए गए सर्कुलर पर अब खासा विवाद हो गया है। कुल 132 प्रोबेशनरी आइपीएस अफसरों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम के लिए इस सर्कुलर में सीआरपीएफ अफसरों को उनकी रैंक से कमतर काम सौंपे गए हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी विरोध और नाराजगी जताई गई है।

सर्कुलर में बताए गए कार्यक्रम के दौरान आइपीएस प्रोबेशनरी अफसरों को सीआरपीएफ के महानिदेशक आरआर भटनागर से बात करनी थी। नाम न बताने की शर्त पर एक सीआरपीएफ अधिकारी ने कहा कि नए शासनादेश से 'रुढ़िवादी मानसिकता' की झलक मिल रही है।

अफसरों ने दावा किया कि असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के अफसर को कार्यक्रम में स्वच्छता का प्रबंधन, खाने का इंतजाम देखने को कहा गया। इन्हें कैंटीन को सहयोग देते हुए खाली कटोरियों को हमेशा फूड आइटम से भरे रखना, पानी की बोतलों व टॉफी आदि का इंतजाम देखना होगा। इस सर्कुलर को लेकर ट्विटर पर कई प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं। इनमें कहा गया है कि सीआरपीएफ अधिकारियों के लिए यह आपत्तिजनक है, क्योंकि इन्हें इनके रैंक से नीचे का काम दिया गया है जिसे हटाया जाना चाहिए। सीआरपीएफ अधिकारी ने कहा कि महानिदेशक को इस मामले से अवगत करा दिया गया है। इसके लिए उन्होंने इंस्पेक्टर जनरल के साथ बैठक की। महानिदेशक की ओर से मंजूर किए गए शासनादेश में लिखा गया, 'असिस्टेंट कमांडेंट को तैयारी का प्रबंध देखना होगा, उन्हें वरीयता के अनुसार अधिकारियों की नेमप्लेट का प्रबंध करना होगा। स्क्रीन डिसप्ले, पीए सिस्टम, पावर बैकअप, स्वच्छता, आइटी कंपोनेंट आदि की देखरेख संभालनी होगी।'

अधिकारियों को मेन्यू के अनुसार खाने की तैयारी, फूड काउंटर समेत खाने से संबंधित तमाम इंतजाम देखने होंगे। कमांडेंट रैंक से नीचे के अफसरों को प्रोबेशनरी आइपीएस अफसर के वहां पहुंचने पर स्वागत करने व उन्हें कांफ्रेंस रूम तक ले जाने की ड्यूटी दी गई है।

सीबीडीटी चेयरमैन पर आरोप लगाने वाली शीर्ष कर अधिकारी प्रोन्नत

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पर तंग करने का आरोप लगाने वाली 1984 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी को विशेष सचिव के बराबर के शीर्ष ग्रेड में प्रोन्नत किया गया है।

सरकारी आदेश के मुताबिक, मुंबई में आयकर इकाई-2 की मुख्य आयुक्त अलका त्यागी ने कथित तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर सीबीडीटी के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मूडी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। पत्र में अलका त्यागी का कहना था कि मूडी ने पूर्व में खुद ही उनके खिलाफ सतर्कता जांच के एक मामले का निपटारा किया था, लेकिन अब वह ही उस मामले का इस्तेमाल उनकी पोस्टिंग रोकने के लिए ब्लैकमेल के हथियार के तौर पर कर रहे हैं।

सीबीडीटी के तीन अक्टूबर के आदेश के मुताबिक, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद अलका त्यागी को प्रमुख मुख्य आयकर आयुक्त (लेवल 17) के ग्रेड में प्रोन्नत कर दिया गया है। उन्हें नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी में प्रमुख आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण) बनाया गया है। एक अधिकारी ने कहा, प्रोन्नति 'पुराने पापों के धुलने' के समान होती है क्योंकि किसी को प्रोन्नति तभी मिलती है जब उसे सतर्कता विभाग से हरी झंडी मिल जाती है।

शहरों का अनियोजित विकास है बाढ़ का मुख्य कारण : जावडेकर

▶ कहा, स्मार्ट सिटी से दूर होगी समस्या

प्रकाश जावडेकर फाइल फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के बजाय अनियोजित शहरीकरण से देश के कई हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 'विरासत में मिली' इस गलती को सरकार अपने स्मार्ट सिटी योजना से सुधार रही है।

जावडेकर ने यहां पीटीआइ मुख्यालय में समाचार एजेंसी के पत्रकारों से कहा कि शहर बेहतर ढंग से नियोजित होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, 'यह कहना विज्ञान नहीं है कि ये (बाढ़) जलवायु परिवर्तन के चलते हुआ। बल्कि सच ये है कि देश में अनियोजित ढंग से विकास हुआ है। हमने समुचित निकास प्रणाली सुनिश्चित करते हुए चंड़ीगढ़, फिर गांधीनगर (गुजरात) की योजना बनाई। दूसरे शहरों में ऐसा नहीं हुआ।'

उन्होंने कहा, 'अनियोजित विकास से चिंताएं बढ़ रही हैं, इसलिए शहरी नियोजन बेहद महत्वपूर्ण है।' आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस मानसून सत्र के दौरान बारिश और बाढ़ में करीब 1900 लोगों को अपनी जान गवांनी पड़ी और 46 लोग लापता हैं और जिससे 22 राज्यों में 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जावडेकर ने कहा कि चंड़ीगढ़ में भवन बनाते समय जो नियम लागू होते हैं, वही नियम दूसरे शहरों में भी भवन बनाते समय लागू होने चाहिए।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, 'ये विरासत से मिली समस्या है। लुटियंस दिल्ली 130 साल पुरानी है। इसके बाद चंड़ीगढ़ बना... चंड़ीगढ़ के बाद दूसरे शहर तैयार हुए। केंद्रशासित क्षेत्र चंड़ीगढ़ को बनाने के लिए जिन नियमों का पालन किया गया, उन्हें दूसरे शहर बनाते समय भी लागू किया जाना चाहिए था।'

जावडेकर ने कहा कि 'दुर्भाग्य से हमने वह अवसर खो दिया। महत्वपूर्ण लोगों ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया।' उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब अपने स्मार्ट सिटी कार्यक्रम और विकास के अन्य उपायों जरिये अनियोजित विकास की समस्या का समाधान कर रही है।

जलवायु परिवर्तन पर नतीजों को किया खारिज

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने हाल में आए जलवायु परिवर्तन के मामले पर अंतर–सरकारी पैनल की रिपोर्ट के नतीजों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने के चलते 2100 तक भारत के मुंबई जैसे शहर और अंडमान–निकोबार जैसे द्वीप क्रमिक रूप से निर्जन हो जाएंगे।

खाली पड़ी सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा करेंगी निजी एजेंसियां

▶ सीपीडब्ल्यूडी को दी गई सुरक्षा एजेंसियों के चयन की जिम्मेदारी

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय दिल्ली में खाली पड़ी सरकारी जमीन, बंगलों और फ्लैट को कब्जों से बचाने के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं लेगा। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को निजी सुरक्षा एजेंसियों के चयन की तैनाती का काम सौंपा गया है। सुरक्षाकर्मियों में पूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि एजेंसियों को सुरक्षाकर्मियों की तैनाती से पहले उनका सत्यापन दिल्ली पुलिस से कराना होगा। उसके बाद ही उन्हें खाली पड़े सरकारी बंगलों, जमीन और फ्लैटों में तैनात किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों को एक साल के लिए नियुक्त किया जाएगा और इन्हें खाली पड़ी संपत्ति की सुरक्षा के लिए चौबीस घंटे दो सुरक्षाकर्मियों को तैनात करना होगा। बता दें कि दिल्ली में ऐसी हजारों खाली पड़ी संपत्तियां हैं, जहां अक्सर अतिक्रमण की शिकायत मिलती है। उन्हें कब्जे से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बावजूद अगर संपत्ति पर कब्जा होता है तो एजेंसी को जमीन, बंगले या फ्लैट पर अवैध कब्जा रहने तक हर दिन 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अनुमान के मुताबिक सुरक्षा एजेंसी की नियुक्ति के लिए 93 लाख रुपये की जरूरत होगी। जिन गार्डों को इन संपत्तियों पर तैनात किया जाएगा, उन्हें कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक एक बार एजेंसी को काम पर रखने के बाद उसे प्रत्येक दिन गार्डों की तैनाती का विवरण देना होगा। इतना ही नहीं गार्डों के आचरण और व्यवहार के लिए भी एजेंसी जिम्मेदार होगी।

भ्रष्टाचार मामले में पवन हंस के अफसरों के खिलाफ केस दर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने सरकारी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस के अज्ञात अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया है। अफसरों पर एमआइ-172 हेलीकॉप्टर के इंजनों की मरम्मत के लिए 1.85 करोड़ रुपये रूसी कंपनी के बैंक खाते की जगह इंडोनेशिया के बैंक खाते में डायवर्ट करने का आरोप है।

जानकारी के अनुसार, पवन हंस ने 20 मई, 2015 को तीन एमआइ-172 हेलीकॉप्टर के इंजन की मरम्मत व ओवरहालिंग के लिए रूसी कंपनी क्लीमोव जेएससी से नौ करोड़ रुपये का करार किया था। पवन हंस को अग्रिम के तौर पर रूसी कंपनी को 30 फीसद रकम का भुगतान करना था। इसके लिए 1.85 करोड़ रुपये की एनवॉयस जारी की गई थी। क्लीमोव की तरफ से भेजी गई एनवॉयस के मुताबिक, पवन हंस को न्यूयॉर्क स्थित बैंक के खाते में पैसे जमा कराने थे, लेकिन पवन हंस ने एक मेल के आधार पर इंडोनेशिया के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। पवन हंस ने जिस मेल आइडी के आधार पर इंडोनेशिया में पैसे जमा कराने की बात कही थी, क्लीमोव ने उसे फर्जी बताया था।

कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में सिद्दरमैया को बनाना चाहता है नेता विपक्ष

संजय मिश्र, नई दिल्ली

▶ भाजपा–येदियुरप्पा को टक्कर देने के लिए पूर्व सीएम ही लग रहे सबसे प्रभावी चेहरा, राज्य के दिग्गजों को एतराज

सिद्दरमैया फाइल फोटो

कर्नाटक में पार्टी के पुराने दिग्गजों के एतराज के बाद भी कांग्रेस हाईकमान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरमैया को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। सूबे में पार्टी का सियासी प्रभाव कायम रखने के लिए हाईकमान को सिद्दरमैया से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्दरमैया को कर्नाटक में विपक्ष का नेता बनाने का मन लगभग बना लिया है।

सूत्रों के अनुसार, गुटों में बंटी कर्नाटक कांग्रेस के तमाम नेताओं से विचार-विमर्श और जमीनी फीडबैक लेने के बाद हाईकमान का साफ आकलन है कि भाजपा की आक्रामक सियासत और मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से मुकाबले के लिए सिद्दरमैया से ज्यादा प्रभावी पार्टी का कोई दूसरा नेता नहीं है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे, वीरप्पा मोइली, पूर्व उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वरन ही नहीं बल्कि गांधी परिवार के निकट माने जाने वाले मुनियप्पा जैसे वरिष्ठ नेता भी सिद्दरमैया को नेता विपक्ष बनाए जाने पर एतराज जता रहे हैं।

सिद्दरमैया को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाकर नेता विपक्ष बनाने की पहल का विरोध कर रहे इन नेताओं का तर्क है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने बीते करीब 10 साल से कर्नाटक कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाया। पिछले विधानसभा चुनाव में हाईकमान ने उन्हें खुली छूट दी मगर वह सूबे में पार्टी की सत्ता बचाने में नाकाम रहे। इतना ही नहीं, कांग्रेस-जदएस की गठबंधन सरकार को बचाने में भी वह कामयाब नहीं रहे और उनके कुछ खास समर्थक विधायकों ने ही पाला बदलकर सरकार गिरवाई। सूत्रों ने बताया कि सूबे के नेताओं के इस एतराज को देखते हुए ही हाईकमान ने वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को सभी गुटों के साथ बातचीत करने का जिम्मा सौंपा था। सिद्दरमैया के विरोधी नेताओं ने इस मशविरे के दौरान साफ कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी मनमानी के जरिये पार्टी का नुकसान किया है और अपने समर्थक नेताओं के अलावा वह किसी की सुनते ही नहीं हैं।

इस एतराज के बावजूद कांग्रेस का सियासी आकलन है कि राजनीतिक चेहरे के लिहाज से ही नहीं, सूबे के सामाजिक समीकरणों के हिसाब से भी सिद्दरमैया पार्टी की जरूरत हैं। सूबे के दूसरे सबसे प्रभावशाली कुरूवा समुदाय से आने वाले सिद्दरमैया के कारण यह वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा है। शीर्ष नेतृत्व का यह भी मानना है कि सूबे के उसके सबसे जुझारू नेता डीके शिवकुमार इस समय केंद्र की भाजपा सरकार के निशाने पर हैं ऐसे में कर्नाटक में आमने-सामने की टक्कर देने वाले नेता की अभी कहीं ज्यादा जरूरत है।

चुनाव आयोग के संशोधन प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कानून मंत्रालय

नई दिल्ली, प्रेट्र : कानून मंत्रालय आवेदकों और पहले से ही मौजूद मतदाताओं के आधार डाटा संग्रह को वैधानिक समर्थन देने के चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। आयोग ने मतदाता सूची में दोहराव रोकने को यह प्रस्ताव किया है। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के संबंध में दिए गए आदेश में यूआइडीएआइ (आधार) संख्या को मतदाताओं के चुनाव डाटा के साथ जोड़ने की परियोजना पर रोक लगा दी थी। मतदाता सूची में दोहराव रोकने को चुनाव अयोग उस समय अपने राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धीकरण एवं प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत आधार नंबर जुटा रहा था।

हाल ही में कानून मंत्रालय को भेजे पत्र में आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है। आयोग ने मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों और जो मतदाता सूची में शामिल हैं उनसे आधार नंबर लेने की अनुमति देने की मांग की गई है। सूत्रों ने कहा, कानून मंत्रालय चुनाव कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

एक अधिकारी ने कहा, 'कार्रवाई की जा रही है।' आयोग के प्रस्ताव के अनुसार, मतदाता पंजीकरण कार्यालय को मतदाताओं के साथ ही सूची में नाम दर्ज कराने का आवेदन करने वालों से आधार नंबर मांगने का अधिकार देने के लिए चुनाव कानून में संशोधन होना चाहिए। मतदाता सूची में दोहराव रोकने और उसे शुद्ध बनाने के लिए आयोग ने आधार नंबर को मतदातओं के चुनाव आंकड़े से जोड़ने का कदम उठाया था। कोर्ट के फैसले से इस पर रोक लग गई है इसीलिए आयोग ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

आधार से मिलान पर ही मिलेगी किसान योजना की किस्त

नया नियम

योजना की अगली किस्त के लिए आधार का लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है, इसके चलते दूसरी किस्त जमा कराने में हो रहा है विलंब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पोर्टल के जरिये किसान अपने नाम और आधार नंबर का खुद भी कर सकेंगे मिलान
- कृषि मंत्री ने योजना में शामिल होने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री को फिर लिखा पत्र

नरेंद्र सिंह तोमर फाइल फोटो

देश के ज्यादातर राज्यों में किसानों के बैंक खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त नहीं जमा हो पा रही है। अब यह तभी संभव होगा, जब किसान के नाम और उसके आधार नंबर का मिलान हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर मिलान की पुष्टि करने को कहा है। किसान आधार नंबर से अपने नाम के मिलान की पुष्टि खुद भी पीएम किसान वेब पोर्टल पर कर सकते हैं।

कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, योजना की अगली किस्त के लिए आधार का लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। किसान खुद सीधे पोर्टल पर जाकर नाम व आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। इस तरह अब तक पांच लाख किसानों के नाम रजिस्टर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अग्रवाल ने बताया कि राज्य के दो करोड़ से अधिक किसानों में से 1.57 करोड़ किसानों को पहली किस्त का लाभ मिला था, लेकिन दूसरी किस्त के लिए उनके नामों का आधार से मिलान जरूरी है। इसके चलते बैंक खाते में दूसरी किस्त जमा कराने में थोड़ा विलंब हो रहा है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'पीएम किसान योजना में शामिल होने के लिए किसानों को मौका मिला तो सप्ताह भर में ही तीन लाख से अधिक किसानों ने पोर्टल पर अपने नाम दर्ज करा लिए।' हालांकि, योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है।

कृषि मंत्री ने इस बाबत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर पत्र लिखकर किसानों की हित वाली इस योजना को राज्य में लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने वाली इस योजना के वहां लागू हो जाने से राज्य को 4,200 करोड़ रुपये की प्राप्त होंगे। योजना के तहत प्रत्येक किसान को दो हजार रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे।

बंगाल के आठ हजार किसानों ने पोर्टल पर कराया पंजीकरण

कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर किसानों को सीधे पंजीकरण का मौका प्रदान किया है। इसके तहत देश के कुल तीन लाख से अधिक किसानों ने खुद को रजिस्टर (पंजीकृत) किया है। बंगाल के 8,000 किसानों ने भी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में हिस्सा लेने की इच्छा जताते हुए पंजीकरण कराया है। ज्ञात हो, किसान योजना में बंगाल सरकार ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था।

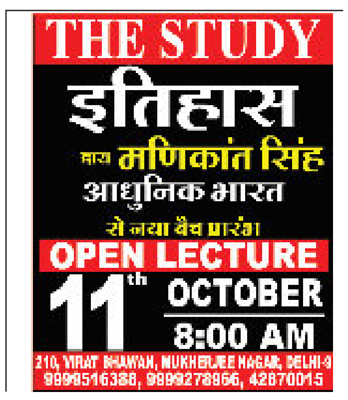

32 प्रत्याशी ग्रेजुएट हैं कांग्रेस के हरियाणा में। भाजपा इकलौती ऐसी पार्टी है, जिसके सभी उम्मीदवार कम से कम 10वीं पास हैं। भाजपा के 31 ग्रेजुएट प्रत्याशी मैदान में हैं।

8.95 करोड़ मतदाता हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। इनमें 1.16 लाख सर्विस वाले मतदाता हैं। राज्य में कुल 95,473 पोलिंग स्टेशन हैं।

हॉट सीटों पर होंगे कड़े मुकाबले, टकराएंगे सूरमा

सुधीर तंवर, चंडीगढ़

हरियाणा

हरियाणा विधानसभा के लिए चुनावी दंगल सज गया है। जिसे मैदान छोड़ना था, वे सियासी रण से हट चुके हैं। बागी प्रत्याशियों के रूठने-मनाने का दौर भी अब खत्म हुआ। चुनावी शतरंज की बिसात पर 1168 'मोहरे' बचे हैं, जो विधानसभा में पहुंचने के लिए कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं। प्रत्याशियों की भीड़ छंटते ही 90 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 183 प्रत्याशी कम हैं, लेकिन मुकाबला कहीं पर भी आसान नहीं।

यूं तो प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों में से अधिकतर पर कांटे के मुकाबले तय हैं, लेकिन करीब दो दर्जन हॉट सीट ऐसी हैं जो अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। सभी की निगाहें इन पर टिकी हैं। सीएम सिटी करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में हैं, जिनके खिलाफ इनेलो ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। यहां चर्चा जीत-हार की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की जीत के अंतर को लेकर हो रही है।

- पहलवान योगेश्वर व बबीता और हॉकी खिलाड़ी संदीप के उतरने से सुर्खियों में बरौदा, दादरी और पिहोवा सीट
- करनाल में मुख्यमंत्री की जीत के अंतर पर घमासान, गढ़ी-सांपला में हुड्डा का किला भेदने के प्रयास में भाजपा
- बाढड़ा में आमने-सामने बंसी और चौटाला परिवार, सुखविंद्र ने मुकाबला बनाया त्रिकोणीय

पिहोवा सीट से उम्मीदवार संदीप सिंह। फाइल

दादरी से मैदान में हैं बबीता फौगाट। फाइल

बरौदा से भाग्य आजमा रहे योगेश्वर दत्त। फाइल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में अपनी परंपरागत सीट गढ़ी-सांपला-किलोई में फिर ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार हुड्डा के मुकाबले में इनेलो के टिकट पर उतरे सतीश नांदल इस बार भाजपा की ओर से उन्हें टक्कर दे रहे हैं। हुड्डा परिवार के इस परंपरागत किले में सेंध लगाने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा रखा है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को गढ़ी-सांपला-किलोई में रैली करेंगे।

हॉट सीट बाढड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला है जहां पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर महेंद्रा कांग्रेस प्रत्याशी हैं। जननायक जनता पार्टी ने यहां से पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला को उतारा है, जबकि भाजपा के सुखविंद्र मांढ़ी बदले सियासी माहौल का फायदा उठाने की कोशिश में हैं।

सोनीपत के बरौदा में ओलंपियन योगेश्वर दत्त, दादरी में अंतरराष्ट्रीय पहलवान बबीता फौगाट और कुरुक्षेत्र के पिहोवा में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह भाजपा के टिकट पर चुनावी रण में हैं, जिस कारण यह तीनों सीटें राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आ गई हैं। तीनों खिलाड़ियों की जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर चल रही भाजपा की रणनीति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 15 अक्टूबर को दादरी में बबीता फौगाट और संदीप सिंह के लिए कुरुक्षेत्र में रैली करने पहुंच रहे हैं। इससे पहले योगेश्वर दत्त के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ 11 अक्टूबर को सोनीपत में रैली करेंगे।

भजनलाल परिवार की परंपरागत सीट आदमपुर में कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के मुकाबले में भाजपा द्वारा अदाकारा सोनाली फौगाट को उतारे जाने से यह सीट चर्चा में आ गई है। पंचकूला में भाजपा विधायक ज्ञानचंद गुप्ता के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन को उतारा है, जिस कारण यहां मुकाबला रोचक हो गया है।

उचाना में भाजपा द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री चौ. बीरेंद्र सिंह की विधायक पत्नी प्रेमलता को फिर से मैदान में उतारा गया है। यहां से जजपा के पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला खुद मैदान में हैं। कैथल में कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ भाजपा द्वारा लीला राम गुर्जर को उतारने से दोनों सीटों पर सभी की निगाहें हैं। ऐलनाबाद में इनेलो के अभय चौटाला, बादली में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धनखड़, नारनौंद में कैप्टन अभिमन्यु, रोहतक में मनीष ग्रोवर, डबवाली में आदित्य चौटाला, तोशाम में कांग्रेस की किरण चौधरी, टोहाना में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला और फतेहाबाद में चौधरी भजनलाल के भतीजे दुड़ाराम के मैदान में उतरने से यह सीटें हॉट हो गई हैं।

तकनीक से खुलेगी मतदान में गड़बड़ी की पोल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग से नजर रखेगा चुनाव आयोग
- हरियाणा में 3000 से अधिक हैं अतिसंवेदनशील और संवेदनशील केंद्र

हरियाणा विधानसभा चुनावों में 21 अक्टूबर को मतदान के दौरान अगर किसी भी अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथों पर धांधली हुई तो आरोपित निर्वाचन विभाग की जद में आ जाएंगे। निर्वाचन विभाग आधुनिक तकनीक वाली वेब कास्टिंग के जरिये मतदान में होने वाली गड़बड़ियों को रोकेगा।

प्रदेश में 3000 से अधिक अतिसंवेदनशील और संवेदनशील केंद्रों को सेंट्रलाइज्ड सर्वर के जरिये कैमरों से जोड़ा जाएगा। यह सर्वर मतदान केंद्र पर मौजूद चुनाव अधिकारियों के लैपटाप या टैबलेट से जुड़े होंगे। मतदान केंद्रों पर कैमरे ऐसे स्थान पर लगे होंगे, जहां से हर गतिविधि का नजारा देखा जा सकेगा। अगर किसी मतदान केंद्र पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या असामाजिक तत्व मतदान में गड़बड़ी करते हैं तो कैमरे में कैद होने के साथ ही तत्काल पुलिस प्रशासन की पकड़ में होंगे। कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी सुबह से शाम तक मतदान केंद्रों का सीधा नजारा देख सकेंगे।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत के मुताबिक, मतदान में धांधली रोकने के लिए वेब कास्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए उन मतदान केंद्रों को विशेष तौर पर चुना गया है, जिन पर बीते चुनावों में एकतरफा मतदान या गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी।

यह है वेब कास्टिंग : वेब कास्टिंग में एक वीडियो कैमरा मतदान केंद्र में उस स्थान पर लगाया जाता है, जहां से पूरे केंद्र की गतिविधियों पर निगाह रखी जा सके। यह कैमरा सेंट्रलाइज्ड सर्वर से जुड़ा रहता है। इससे केंद्र की गतिविधियों का सीधा प्रसारण केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी देखते रहते हैं। अगर उन्हें केंद्र में या आसपास कोई अवांछित गतिविधि नजर आती है तो वे निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को कार्रवाई के लिए सीधा निर्देश जारी करेंगे।

हुंकार ▸ चुनाव की घोषणा के बाद गृह मंत्री ने महाराष्ट्र में बीड में पहली रैली को किया संबोधित

पहले की सरकारें नहीं कर पाईं, लेकिन मोदी ने बनाया ओबीसी आयोग : शाह

कहा, लोगों ने मोदी जी को 300 सीटें दीं, उन्होंने तीन महीने में अनुच्छेद 370 हटा दिया

बीड, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को दशहरा रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी आयोग का गठन करके लगातार वंचितों और पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं का निदान करने में जुटे हुए हैं, जबकि बीते 70 साल में पिछली सरकारें यह नहीं कर पाईं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीड जिले के सावरगांव में पहली रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, 'पिछली सरकारों ने पिछले 70 साल में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ भी नहीं किया। यह मोदी हैं, जिन्होंने संवैधानिक ढांचे के जरिये उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया। आज मोदी सरकार देश में वंचितों और पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रही है।' अनुच्छेद 370 को लेकर मोदी की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ विलय किया। उनका काम क्षेत्र (मराठवाड़ा) के हर घर तक पहुंचना चाहिए। आपने मोदी जी को 300 सीटें (लोकसभा चुनाव में) दीं, उन्होंने सिर्फ तीन महीने में अनुच्छेद 370 हटा दिया। अब लोगों को विपक्ष से पूछना चाहिए कि वे अनुच्छेद 370 क्यों नहीं हटा पाए थे।' शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार कई विकास परियोजनाओं पर काम कर रही है।

महाराष्ट्र के बीड जिले के सावर गांव में रैली के दौरान गृह मंत्री व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे व अन्य। प्रेट्र

370 तोपों की सलामी देकर शाह का किया स्वागत

बीड में दशहरा कार्यक्रम का आयोजन कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे ने किया था। उन्होंने 370 तोपों की सलामी देकर और 370 झंडे लहराकर शाह का स्वागत किया। लोगों को संबोधित करते हुए पंकजा ने कहा, 'यहां मौजूद लोगों को गन्ने की फसल उगाने के लिए और अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए हाथों में हंसिया लेना पड़ता है। अगले पांच साल में किसी को भी अपनी आजीविका कमाने के लिए यह काम नहीं करना पड़ेगा।'

गठबंधन के सवालों पर बोले उद्धव, ...तो क्या देशद्रोही कांग्रेस का समर्थन करूं

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- शिवसेना प्रमुख ने कहा-मंदिर निर्माण की मांग हम नहीं छोड़ सकते

इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा से कम सीटें पाकर भी गठबंधन करने पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने वाली भाजपा से गठबंधन न करता तो क्या इस निर्णय का विरोध करने वाली देशद्रोही कांग्रेस को समर्थन देता?

उद्धव ने मंगलवार को शिवसेना की परंपरागत दशहरा रैली को संबोधित करते हुए याद किया कि अनुच्छेद 370 रहित जम्मू-कश्मीर उनके पिता और शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे का सपना था। उद्धव ने यह भी याद किया कि उनके पिता अयोध्या में रामजन्म भूमि पर भव्य राम मंदिर भी देखना चाहते थे। राम मंदिर से ही भाषण की शुरुआत करते हुए उद्धव ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले के कोर्ट में लंबित होने के कारण इस पर बयानबाजी न करने की हिदायत का उल्लेख करते हुए कहा कि मुकदमा तो 30 साल से चल रहा है। दशहरे और दीवाली की छुट्टी में कोर्ट बंद होता है। यानी वह मानता है कि राम ने रावण का वध किया, लेकिन राम का जन्म कहां हुआ, इस पर मुकदमा चल रहा है। मंदिर निर्माण शिवसैनिकों की मांग है। पूरे देश की मांग है। हम यह मांग छोड़ नहीं सकते। हमने देश को राम मंदिर बनाने का वचन दिया है। हमें विशेष कानून बनाकर यह वचन पूरा करना चाहिए।

उद्धव ठाकरे फाइल

हमने हिंदुत्व के लिए गठबंधन किया है : भाजपा के साथ गठबंधन पर उद्धव ने कहा कि गठबंधन-गठबंधन में फर्क होता है। एक गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच भी हुआ था। सिर्फ सत्ता की लालसा के लिए किए गए ऐसे गठबंधन का परिणाम देश देख चुका है। हमारा गठबंधन प्रामाणिक है। हमने हिंदुत्व के लिए गठबंधन किया है। इस गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार किया है।

भ्रष्टाचार के कारण हुआ कांग्रेस-राकांपा का पतन : उद्धव ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार को भी आड़े हाथों लिया। प्रवर्तन निदेशालय पर शरद पवार की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए उन्होंने अपने पिता बालासाहब ठाकरे पर वर्ष 2000 में की गई कार्रवाई याद करने की सलाह पवार को दी। उद्धव का कहना था कि कांग्रेस-राकांपा का पतन उसके भ्रष्टाचार के कारण हुआ है।

नाराज नेताओं को बगावत न करने की सलाह : उद्धव ने टिकट कटने से नाराज शिवसैनिकों से माफी मांगते हुए उन्हें बगावत न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बालासाहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना गठबंधन करके चुनाव लड़ने के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कल्याण के लिए की थी। शिवसेना की ताकत कम मत होने दो।

किसानों की पूर्ण कर्जमाफी का वादा

शिवसेना ने अपना घोषणापत्र अभी जारी नहीं किया है, लेकिन दशहरा रैली के मंच से उद्धव ने घोषणा की कि दोबारा सत्ता में आते ही शिवसेना किसानों की पूर्ण कर्ज माफी कर उन्हें उनकी जमीन के कागजात सौंपने का काम करेगी। साथ ही शहरों में 300 यूनिट तक की बिजली के दाम में 30 फीसद कटौती करने, 10 रुपये में भोजन की थाली और एक रुपये में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को मुफ्त बस सेवा की सुविधा देने की घोषणा भी उद्धव ठाकरे ने की।

...जब तीन विधायकों पर सिमट गई कांग्रेस, 38 सीटों पर जमानत जब्त

सुधीर तंवर, चंडीगढ़

इतिहास के झरोखे से

- 1977 के अलावा 1987 और 1996 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली थीं दस से कम सीटें
- पार्टी में गुटबाजी और बड़े नेताओं के दलबदल से बढ़ती दिख रही कांग्रेस की मुश्किलें

हरियाणा गठन के बाद हर चुनाव अपने दम पर लड़ती आ रही कांग्रेस पिछले पांच दशकों में कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर पहुंची। वरिष्ठ और पुराने नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के लिए मौजूदा विधानसभा चुनाव चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। प्रदेश में सर्वाधिक समय तक सत्ता में रही कांग्रेस ने सबसे बुरा दौर 1977 में देखा, जब आपातकाल के बाद हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी तीन सीटों पर ही जीत सकी। 38 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई और पार्टी को सिर्फ 17.15 फीसद वोट मिले। तब जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ 75 सीटें मिली थीं और देवी लाल मुख्यमंत्री बने थे।

कांग्रेस ने 1987 में भी कुछ ऐसा ही दौर देखा जब 90 सीटों पर केवल पांच उम्मीदवार ही जीत सके। आठ प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई और पार्टी को 29.18 फीसद वोट मिले। इसी तरह 1996 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस केवल नौ सीटों पर सिमट गई और 35 उम्मीदवार जमानत गंवा बैठे। इस दौरान पार्टी को सिर्फ 20.82 फीसद वोट मिले।

पहले और दूसरे चुनाव में यह रही स्थिति : चुनावी इतिहास की बात करें तो वर्ष 1967 में हुए हरियाणा विधानसभा के पहले और 1968 में हुए दूसरे चुनावों में कांग्रेस ने 81 में से 48-48 सीटें जीती थीं। 1972 में पार्टी के 52 उम्मीदवार जीते और प्रदेश में सरकार बनाई। पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन वर्ष 2005 में रहा, जब 67 सीटें जीतीं और 42.46 वोट के साथ सरकार बनाई। वर्ष 1991 के चुनावों में कांग्रेस ने 51 सीटें जीतीं, जबकि 11 उम्मीदवारों को जमानत गंवानी पड़ी।

2009 में हजकां विधायकों के दम पर बनाई सरकार

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि 1982 में पार्टी को 36 और 2000 में 21 सीटें मिलीं। वर्ष 2009 में कांग्रेस को 40 सीटें मिली थीं, लेकिन हजकां विधायकों के दम पर पार्टी सरकार बनाने में सफल रही। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 15 सीटों पर सिमट गई थी और 37 उम्मीदवारों ने जमानत गंवाई।

बागियों को मनाने में छूटे पसीने, 1168 योद्धा मैदान में

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के चुनावी रण के योद्धाओं के चेहरे साफ हो गए हैं। 523 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लेने के बाद अब मैदान में 1168 प्रत्याशी बचे हैं, जिनमें विधानसभा की 90 सीटों के लिए मुकाबला होगा। हालांकि, बागियों को मनाने में विभिन्न दलों के दिग्गजों के पसीने छूट गए। टिकट कटने से खफा होकर पत्नी अनीता का पर्चा भराने वाले भाजपा विधायक उमेश अग्रवाल ने अंतिम क्षणों में नामांकन वापस ले दिया। रेवाड़ी में भाजपा अपने विधायक रणधीर कापड़ीवास को नहीं मन पाई। अब वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं, जजपा के तीन उम्मीदवारों ने भाजपा में शामिल होते हुए नामांकन वापस ले लिया। हिसार में सर्वाधिक 118 उम्मीदवार बचे हैं, जबकि पंचकूला में सबसे कम 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। चुनावी मैदान के चेहरे साफ होने के साथ ही अब चुनाव प्रचार गति पकड़ेगा। 19 अक्टूबर को चुनाव प्रचार थम जाएगा। बता दें कि इस बार कुल 1846 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिनमें छंटनी के दौरान 345 उम्मीदवारों की दावेदारी निरस्त हो गई।

गुजरात में सतह पर आई भाजपा और कांग्रेस नेताओं की नाराजगी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- विधानसभा उप चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद का असंतोष खराब कर सकता है खेल

गुजरात की छह विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को होने वाले उप चुनाव के प्रचार के दौरान भाजपा व कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर नेताओं की नाराजगी सतह पर आ गई है। पूर्व मंत्री शंकर चौधरी को टिकट नहीं मिलने से नाराज चौधरी समाज थराद, राधनपुर व बायड में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है तो कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है।

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री शंकरभाई चौधरी को राधनपुर या थराद से टिकट मिलना तय माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल के हस्तक्षेप के चलते चौधरी का पत्ता कट गया। चर्चा यह भी है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने भी आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण चौधरी के मुद्दे पर पटेल का साथ दिया। दीपावली बाद गुजरात सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए अल्पेश ठाकोर तथा चौधरी दोनों ही मंत्री पद की दौड़ में थे। अब चौधरी का पत्ता कटने से नाराज उनके समर्थक थराद व राधनपुर में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। थराद में सोमवार देर शाम आयोजित चुनावी सभा में कम उपस्थिति देख प्रचार करने पहुंचे सांसद परबत भाई पटेल भड़क गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाजपा को दो-तीन सीटें नहीं भी मिलती हैं तो क्या फर्क पड़ता है। बायड सीट पर राकांपा प्रमुख शंकरसिंह वाघेला के पुत्र एवं पूर्व विधायक महेंद्रसिंह वाघेला भाजपा प्रत्याशी का खेल बिगाड़ सकते हैं। अल्पेश के करीबी धवलसिंह झाला यहां भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। महेंद्र यहां से खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें समझा-बुझा दिया गया। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस भी अंतर्कलह का शिकार है। अहमदाबाद की अमराईवाड़ी सीट को लेकर मुस्लिम नेता बदरुद्दीन शेख और खेरालू से पार्टी प्रवक्ता जयराज सिंह परमार टिकट न मिलने से नाराज हो गए थे। उधर, कांग्रेस ने सोशल मीडिया में प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा के खिलाफ पोस्ट करने पर मीडिया सेल के सदस्य जयेश गेडिया को पार्टी से बाहर कर दिया। चावड़ा के विरोधियों ने पार्टी आलाकमान तक संदेश पहुंचाया कि चावड़ा के कमजोर नेतृत्व के कारण ही पार्टी के सात विधायक अलग हो गए। जीत के बावजूद 11 जिला पंचायतों में कांग्रेस अपना प्रमुख नियुक्त नहीं कर सकी और भाजपा ने उन पर कब्जा जमा लिया। 16 नगरपालिका व वडोदरा महानगरपालिका में भी कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ।

प्रचार अभियान

शाह के हरियाणा दौरे से मिलेगी भाजपा के मिशन-75 पार को गति

कैथल, लोहारू और महम में आज भाजपा अध्यक्ष की रैलियां, सोनिया और राहुल के दौरे तय नहीं, हुड्डा व सैलजा पर कांग्रेस की जिम्मेदारी

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

हरियाणा के चुनावी रण में अब घमासान मचने के आसार हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह बुधवार को जहां पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे, वहीं शाह के दौरे के साथ ही राष्ट्रीय नेताओं की हरियाणा में आवाजाही तेज हो जाएगी। भाजपा ने पूरे हरियाणा को चार हिस्सों में बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम तय किए हैं, जबकि शाह एक दर्जन जनसभाएं करेंगे।

कांग्रेस अभी तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के हरियाणा में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय नहीं कर पाई है। कांग्रेस के प्रचार की पूरी बागडोर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष कु. सैलजा के कंधों पर है। इनेलो के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला प्रचार कर चुके हैं, जबकि अभय सिंह चौटाला ने भी मोर्चा संभाल रखा है। जजपा के लिए दुष्यंत चौटाला व नैना चौटाला स्टार प्रचारक हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए पंडित नवीन जयहिंद प्रचार करेंगे। उन्होंने प्रचार की गुप्त रणनीति तैयार की है।

भाजपा ने मई में लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसका असर मौजूदा समय में साफ नजर आ रहा है। पीएम मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने छह महीने पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से फीडबैक लेकर होमवर्क शुरू कर दिया था। मोदी-शाह की जोड़ी ने ग्राउंड रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई।

जिताऊ चेहरों के लिए भाजपा ने दो कैबिनेट मंत्रियों सहित 12 विधायकों के टिकट काटने से भी परहेज नहीं किया। पार्टी के कई बड़े नेताओं को टिकट नहीं मिलने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी डैमेज कंट्रोल में भी जुटी है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल रूठे हुए नेताओं को मनाने में जुटे हैं। शाह और मोदी के दौरे के बाद यह नाराजगी पूरी तरह से खत्म होने के आसार हैं। भाजपा ने चुनावी रण में 40 स्टार प्रचारक उतारे हैं, जिनमें 18 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा शासित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं।

आज शाह की तीन रैलियां

शाह बुधवार से धुआंधार प्रचार अभियान शुरू करेंगे। पहले दिन उनकी कैथल, लोहारू और महम में रैलियां रखी गई हैं। कैबिनेट की बैठक के चलते बरवाला रैली स्थगित करनी पड़ी है। शाह 14 अक्टूबर को मोदी के साथ फिर हरियाणा आएंगे। इस दिन वह बल्लभगढ़ में दक्षिण हरियाणा की रैली करेंगे तो शाह टोहाना, पंचकूला, करनाल और गुरुग्राम के बादशाहपुर में रैलियां कर पार्टी उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाएंगे।

अशोक तंवर पहुंचा रहे कांग्रेस को नुकसान

सोनिया-राहुल के दौरे तय नहीं होने से कांग्रेस का चुनाव अभियान गति नहीं पकड़ पा रहा है। पार्टी के पूर्व प्रधान अशोक तंवर कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए फील्ड में निकल पड़े हैं। हालांकि जब वह छह साल प्रधान रहे, तब भी कांग्रेस को खड़ा नहीं कर पाए। तंवर को अब हुड्डा और सैलजा ने भी गंभीरता से लेना छोड़ दिया है।

हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी हवा तेज करेंगे योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को धार देने में जुटे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनावी हवा तेज करेंगे। नवरात्र की वजह से योगी गोरखपुर प्रवास पर हैं, लेकिन बुधवार को उनकी वापसी होगी। गुरुवार से उक्त राज्यों में उनका दौरा शुरू हो जाएगा। नाथ संप्रदाय की सुप्रसिद्ध गोरक्षपीठ के महंत योगी के देशभर में अनुयायी हैं।

धर्म और हिंदुत्व पर सीधी और सधी जुबान से दो टूक बोलने की वजह से योगी की सभी राज्यों में मांग रहती है। खासकर चुनाव के समय वह स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे को विस्तार देते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के चुनाव में योगी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस समय हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। इन राज्यों में योगी स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं से सीधे मुखातिब होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नामांकन में भी योगी गए थे, जबकि महाराष्ट्र में उनके कई कार्यक्रम हो चुके हैं। अब गुरुवार को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जाएंगे। वहां उनके कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की बड़ी तादाद है। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग। उनके बीच योगी की लोकप्रियता है। गुरुवार की शाम योगी की वापसी होगी और वह लखनऊ में स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम द्वारा रेजिंग डे में शामिल होंगे। शुक्रवार को वह हरियाणा जाएंगे। योगी शनिवार को भी हरियाणा भ्रमण पर रहेंगे। रविवार और सोमवार को योगी का महाराष्ट्र दौरा प्रस्तावित है। सोमवार तक उनकी कई सभाएं आयोजित होंगी।

योगी आदित्यनाथ फाइल

उप्र में तीन दिन में 11 चुनावी जनसभाएं : योगी न केवल महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में माहौल बनाएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की 11 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। योगी तीन दिन में 11 चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। वह 15 अक्टूबर को कानपुर के गोविंदनगर, चित्रकूट के मानिकपुर, लखनऊ कैंट और प्रतापगढ़ की सभा को संबोधित करेंगे।

17 अरब लीटर जल संरक्षण के लिए पेप्सिको इंडिया को अमेरिका के विदेश मंत्रालय का 2019 का कारपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। 31 अक्टूबर को एक समारोह में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

जमीन से लेकर आकाश तक फिर 'अभिनंदन'

वायु सेना दिवस ▶ एयर–शो में शामिल हुए पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर

एयरफोर्स ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के पराक्रम को दिखाया, लोगों ने की जमकर सराहना

सौरभ पांडेय, गाजियाबाद

वायु सेना दिवस के अवसर पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (मध्य में) ने मिग बाइसन में उड़ान भरी। इस दौरान अभिनंदन के नेतृत्व में 'मिग फॉर्मेशन' में विमानों ने अपनी क्षमता का अद्वितीय प्रदर्शन किया। अभिनंदन ने पाकिस्तान का एफ–16 लड़ाकू विमान मार गिराया था। अनिल बराल

वायु सेना दिवस के अवसर पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर आयोजित समारोह में मानद ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर का स्वागत करते एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। एएफपी

वायुसेना की स्थापना की 87वीं वर्षगांठ पर मंगलवार को लोगों के जेहन में बालाकोट एयरस्ट्राइक और विंग कमांडर अभिनंदन के 'ऑपरेशन पराक्रम' की वीरता की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित वायुसेना दिवस समारोह के दौरान पाकिस्तान के लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन ने एयर-शो में जैसे ही मिग-21 बायसन विमान से उड़ान भरी हर देशवासी का सेना गर्व से चौड़ा हो गया।

विंग कमांडर ने एक बार फिर दुनिया को देश की ताकत से रूबरू करवाया तो लोगों ने भी शूरवीर का जोरदार अभिनंदन किया। अभिनंदन की अगुवाई में मिग-21 बायसन आकाश में गरजा तो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन का परेड ग्राउंड 'भारत माता की जय' के नारों से गूंजायमान हो गया। इस दौरान एयरफोर्स ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के पराक्रम को दिखाया तो लोगों ने जमकर सराहना की। अन्य पायलटों ने भी एयर-शो में उड़ान भरकर अपना शौर्य दिखाया। आयोजन में वायु सेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया, नौसेना प्रमुख कर्मवीर सिंह, थल सेना प्रमुख बिपिन रावत और पूर्व क्रिकेटर व वायुसेना के ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे।

वायुसेना ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्क्वाड्रन-51 को वायुसेना दिवस पर कश्मीर में हुए ऑपरेशन पराक्रम के लिए सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अभिनंदन ने पाकिस्तान के एफ-16 विमान को मार गिराया था। यही वजह रही कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में पहुंचे हर व्यक्ति को उम्मीद थी कि अब देश के हीरो अभिनंदन की एक झलक उन्हें देखने को मिलेगी। लोगों को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में तो अभिनंदन नहीं मिले, लेकिन एयर-शो शुरू होते ही उनका मनोबल उस समय सातवें आसमान पर पहुंच गया, जब पता चला कि अभिनंदन एयर-शो में हिस्सा ले रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद घोषणा हुई कि अभिनंदन की अगुवाई में मिग-21 बायसन विक्ट्री फॉर्मेशन (विजयी मुद्रा) बनाएंगे। इसके बाद दर्शक दीर्घा में अभिनंदन-अभिनंदन और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। इसके बाद मिग-21 बायसन विमान की दहाड़ सुन लोग रोमांचित हो उठे।

एयरस्ट्राइक के नाम पर जयघोष : समारोह में वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने भाषण में जिक्र किया कि बालाकोट एयरस्ट्राइक भारत का आतंकवाद के खिलाफ ऐतिहासिक एक्शन था। यह सुनते ही लोगों ने 'अभिनंदन जय हो' और 'जय हिंद' के जयघोष शुरू कर दिए।

स्क्वाड्रन 51 सम्मानित : बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्क्वाड्रन 51 को वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने सम्मानित किया। इस दौरान स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन सतीश पवार और मास्टर वॉरंट ऑफिसर बीपी रावत ने यूनिट साइटेशन अवॉर्ड ग्रहण किया। दरअसल अभिनंदन एयर-शो में मिग-21 बायसन विमान से पठानकोट से हिंडन एयरबेस पहुंचे थे और यहां करतब दिखाकर वापस पठानकोट लौट गए। इसलिए यहां सम्मान कार्यक्रम में वह शामिल नहीं हो सके।

वायुसेना प्रमुख बोले–बदल गया राजनीतिक माहौल, एयरस्ट्राइक है उदाहरण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

▶ **वायुसेना दिवस समारोह में राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा–आतंकवाद का देंगे मुंहतोड़ जवाब**

वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि वायुसेना भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार है। देश का राजनीतिक माहौल भी पूरी तरह बदल गया है। बालाकोट एयरस्ट्राइक इसी बदले माहौल का उदाहरण है। पुलवामा के बाद सेना के ठिकानों पर हमले का खतरा बढ़ा है, लेकिन वायुसेना इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वायुसेना भविष्य को देखते हुए बायो फ्यूल एयरक्राफ्ट और मेक इन इंडिया के तहत देश में ही हल्ले विमान, हेलीकॉप्टर व मिसाइलों को विकसित करने की तैयारियों में जुटी है। वह गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में मंगलवार को आयोजित वायुसेना दिवस समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

इस दौरान उन्होंने कहा कि बीता एक साल वायुसेना के लिए चुनौती भरा होने के साथ गौरवशाली भी रहा है। पुलवामा हमले के बाद की गई बालाकोट एयरस्ट्राइक ने दुनिया को भारतीय वायुसेना की ताकत से रूबरू कराया है। रक्षा प्रतिष्ठानों पर अब भी खतरा है, लेकिन हम किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार हैं। एयरस्ट्राइक राजनीतिक और सामरिक शक्ति के सामंजस्य का एक उदाहरण है। देश की राजनीतिक सोच अब बदल चुकी है। भविष्य में भी इस तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो वायुसेना पीछे नहीं हटेगी। समारोह के एयर-शो में बालाकोट एयरस्ट्राइक में शामिल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 बायसन और विंग कमांडर भुजाडे ने मिराज-2000 उड़ाया। दोनों की उड़ान आकर्षण का केंद्र रहीं। साथ ही चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की उड़ान देखकर लोग रोमांचित हुए। मिग-21 बायसन विमानों की 51वीं स्क्वाड्रन और मिराज-2000 विमान की नौवीं स्क्वाड्रन को वायुसेना प्रमुख ने सम्मानित किया। वायुसेना प्रमुख र ने कहा कि अब समय है भविष्य की ओर देखने का। भविष्य की तैयारी करने का। रोहिणी राडार, स्पाइडर राडार सिस्टम व तेजस भारतीय तकनीक का नायाब उदाहरण हैं।

राजनाथ व मैक्रों ने रक्षा संबंध और मजबूत बनाने की बात की

▶ **रक्षा मंत्री सिंह ने कहा–गर्मजोशी के माहौल में लाभकारी बातचीत हुई**

▶ **फ्रांस को भारत का 'महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार' बताया**

पेरिस, एएनआइ : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रों से मुलाकात की और दोनों देशों के रक्षा एवं रणनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाने के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि गर्मजोशी के माहौल में हुई बातचीत बेहद लाभकारी रही।

फ्रांस के पहले राफेल युद्धक विमान को भारत को आधिकारिक रूप से सौंपने के कार्यक्रम के लिए सोमवार को पेरिस पहुंचे राजनाथ ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एलिसी पैलेस में उनसे मुलाकात की। इस दौरान सिंह ने फ्रांस को भारत का 'महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार' बताया।

रक्षा मंत्रालय ने इस मुलाकात को 'बहुत गर्मजोशी से भरी और फलदायी' बताया। बैठक करीब 35 मिनट चली। इसके बाद मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया, 'यह बैठक दर्शाती है कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय साझेदारी कितनी गहरी है, खासकर रक्षा क्षेत्र में और हाल के वर्षों में यह उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ हुई है। दोनों नेताओं ने इन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया।' इसमें कहा गया, 'दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने और मेक इन इंडिया पहल को समर्थन देने के लिए सिंह ने राष्ट्रपति मैक्रों का आभार व्यक्त किया।'

उन्होंने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जाक शिराक के निधन पर भारत सरकार की ओर से शोक व्यक्त किया। फ्रांस आए मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा, 'फ्रांस के साथ हमारे बहुआयामी संबंध हैं और संबंध सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे हैं। आज की बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा चर्चा का हिस्सा है।' मैक्रों से मुलाकात से पहले सिंह ने फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ बैठक की। इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति के रक्षा सलाहकार एडमिरल बरनर्ड रोजेल भी मौजूद थे।

रक्षा मंत्री ने राफेल में भरी उड़ान

विजयादशमी के पावन अवसर पर मंगलवार को फ्रांस में जब भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान सौंपा गया तो इस मौके पर मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल में उड़ान भी भरी। एपी

जम्मू–कश्मीर में वायुसेना ने बुलंद हौसले से मनाया स्थापना दिवस

राज्य ब्यूरो, जम्मू : पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी कैंपों पर सटीक प्रहार करने वाली भारतीय वायुसेना, जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों के मंसूबों को हर कीमत पर नाकाम बनाएगी। भारतीय वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को राज्य के एयरफोर्स स्टेशनों पर हुए कार्यक्रमों में हवाई योद्धाओं ने प्रण लिया कि वे समय आने पर जान की बाजी लगाकर दुश्मन को करारी शिकस्त देंगे। इस दौरान सभी एयरफोर्स स्टेशनों पर विशेष परेड के आयोजन के साथ शहीदी स्थलों पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर कमाडोर अजय सिंह पठानिया ने स्टेशन वार मेमोरियल में वायुसेना के शहीदों को सलामी दी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में सप्ताह भर कार्यक्रम चले। इस दौरान वायु सैनिकों, उनके परिजनों और स्कूली बच्चों के लिए आठ किलोमीटर, तीन किलोमीटर और 1.6 किमी की दौड़ का भी आयोजन किया गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन समेत राज्य के सभी छह एयरफोर्स स्टेशनों पर कार्यक्रम हुए। वायुसेना का गठन आठ अक्टूबर 1932 को चार विमानों, छह अधिकारियों और 19 हवाई योद्धाओं के साथ हुआ था। इस समय भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है।

एयर–शो के दौरान दुनिया को दिखाई देश की ताकत

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

पाकिस्तान पर एयरस्ट्राइक कर पूरे विश्व को अपना पराक्रम दिखा चुकी भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना की 87वीं वर्षगांठ पर हिंडन एयरबेस में जमीन से आकाश तक हैरतअंगेज करतब दिखाकर सबको चकित कर दिया। समारोह में हजारों लोग जमीन पर कदम-से-कदम मिलाते जवानों के सामंजस्य के साक्षी बने तो आकाश में गड़गड़ाते विमानों ने भी ताकत का अहसास कराया।

वायुसेना दिवस समारोह की शुरुआत में वायुसेना की पैराजंपर्स टीम आकाशगंगा ने आठ हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर की। इसके बाद जवानों ने कदमताल किया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी राजावत की अगुवाई में निशान टोली पहुंचीं तो सभी ने वायुसेना में महिला शक्ति की सहभागिता का नमूना देखा।

एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने साढ़े पांच किलो की राइफल के साथ ऐसे करतब दिखाए, जिससे लोग रोमांचित हो उठे। वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने इस मौके पर कहा कि वायुसेना का यह वर्ष शहीदों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि अब प्रयास है कि वायुसेना में दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके।

इन्हें किया गया सम्मानित

वायुसेना मेडल गैलेंट्री : विंग कमांडर अभिषेक शर्मा, भुवनेंद्रन नायर, स्क्वॉड्रन लीडर देशमंड, सार्जेंट अमित कुमार झा, शशिधर पी. प्रसाद।

वायुसेना मेडल : ग्रुप कैप्टन अंजन भद्रा, वीरेंद्र सिंह महिदा, समीर प्रधान, माधव, एस. रमेश, देबाजन मंडल, अरुण महादेवन, अनुभव त्रिपाठी, उदयन कुमार, हरदीप सिंह, प्रेम आनंद, विंग कमांडर जेपी राजू, नितिन कुमार, स्क्वॉड्रन लीडर हिमाद्री।

विशिष्ट सेवा मेडल : एयर वाइस मार्शल अविनाश, केएस रेड्डी, अरुण भास्कर, एयर कमोडोर संजीवा सिन्हा, महेश भास्कर, राजेश वैद्य, अनुपम अग्रवाल, ललित कुमार चावला, ग्रुप कैप्टन राजीव शर्मा, मनीष श्रीवास्तव, देवेंद्र शेखावत, एसके नाथ, वर्धराजन, शंकर बी. अरुण, अरुण मित्तू, मनीष सभरवाल, देबज्योति, अनीश अग्रवाल, कमलेश सिंह, अरविंद ठाकुर, रमन केवल, यशपाल नेगी, बीपी सबुत, विजय राव, गौरव मनी त्रिपाठी, रिषभ मित्तल, विंग कमांडर अखेतो जखालू और मास्टर वॉरंट ऑफिसर के सुरंद्रन के साथ स्क्वॉड्रन नौ और 51 को भी सम्मानित किया गया।

राफेल के आगे सब हैं फेल

बोरडेक्स, एएनआइ : 36 राफेल विमानों के लिए 60,000 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे ने मंगलवार को अहम चरण पूरा किया है। भारत को पहला राफेल मिलने के साथ ही भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में बेतहाशा इजाफा होगा। राफेल की खूबियों पर एक नजर डालें।

इन खूबियों से लैस है विमान

- रफाल विमान परमाणु मिसाइल डिलीवर करने में सक्षम, दुश्मन के इलाके में जाए बगैर भी वार करने में अचूक।
- हथियारों का सबसे सुविधाजनक इस्तेमाल, बहुआयामी भूमिका के चलते निचले अक्षांशों में भी हवा से हवा में मार कर सकता है।
- इसमें दो तरह की मिसाइलें हैं–मीटियोर और हैमर। एक की रेंज डेढ़ सौ किलोमीटर है तो दूसरी की तीन सौ किलोमीटर है।
- परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है।
- राफेल जैसा विमान चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं है।
- फ्रांसीसी कंपनी दासौ एविएशन के मुताबिक, राफेल की स्पीड मैक 1.8 है। यानी करीब 2020 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार।
- ऊंचाई 5.30 मीटर, लंबाई 15.30 मीटर, विमान में हवा में ईंधन भरा जा सकता है।
- खाली राफेल विमान अपने ही वजन जितने घातक हथियारों का भार उठा सकता है। विमान में नौ टन से अधिक का बाहरी भार उठाने की क्षमता है।
- राफेल ऊपर–नीचे, अगल–बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। मतलब इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री होगी।
- राफेल युद्धक विमानों का अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया जैसे देशों में हुई लड़ाइयों में इस्तेमाल हुआ है।

पहले चार विमान अंबाला एयरबेस पर तैनात होंगे

▶ **प्रथम पृष्ठ से आगे**

भारत को मिलने वाले 36 विमानों की डील में से पहले चार अंबाला एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। पहले 16 राफेल को वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया जाएगा। साल 1999 के करगिल युद्ध के दौरान हीरो बनकर उभरी इस स्क्वाड्रन को हाल ही में सेवानिवृत हुए एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कमांड किया था। अप्रैल 2022 में आने वाले अगले 16 विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस में तैनात किया जाएगा। **हवाई क्षेत्र में गेमचेंजर साबित होगा** : राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ा देगा। यह हवाई क्षेत्र में गेमचेंजर साबित होगा। राफेल पाकिस्तान और चीन से होने वाले हवाई हमलों के खतरे को रोकने और उसे काउंटर करने में काफी मददगार साबित होगा। सॉफ्टवेयर प्रामाणिकता की वजह से सभी 36 जेट अक्टूबर 2022 तक ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो पाएंगे।

बुद्धिजीवियों के खिलाफ देशद्रोह मामले के लिए मोदी सरकार को दोष देना गलत

▶ **जावडेकर ने कहा, निहित स्वार्थ में सरकार के खिलाफ फैलाया जा रहा झूठ**

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बुद्धिजीवियों और कलाकारों के खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले के लिए मोदी सरकार को दोषी बताए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थ के चलते सरकार और भाजपा के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले से पार्टी या केंद्र सरकार का कुछ लेना-देना नहीं है।

जावडेकर ने कहा कि एक याचिका पर बिहार की अदालत के आदेश के बाद इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई थी। लेकिन सरकार को बदनाम करने के लिए हमेशा इस तरह का झूठ फैलाया जाता है। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रही है।

बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सीजेआइ के आदेश पर अपर्णा सेन, अडूर गोपालकृष्णन, रामचंद्र गुहा समेत 49 बुद्धिजीवियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों ने उन्मादी भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा था।

प्रकाश जावडेकर। फाइल

बुद्धिजीवियों पर केस की निंदा : अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, इतिहासकार रोमिला थापर, कार्यकर्ता हर्ष मंदर समेत 180 कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों ने बुद्धिजीवियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की निंदा की है। सात अक्टूबर को जारी नए पत्र में इन लोगों ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री को खुला पत्र लिखना कैसे देशद्रोह का मामला हो सकता है।

थरूर और गौड़ा ने पीएम को लिखा पत्र

बुद्धिजीवियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने पर केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री से सार्वजनिक रूप से विरोध के स्वर का स्वागत करने की अपील की है। थरूर ने उन्मादी भीड़ की हिंसा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केस दर्ज होने के लिए प्रधानमंत्री को कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है। लेकिन देश में माहौल परेशान करने वाला बन गया है। लोकतंत्र में लोगों को सरकार, प्रधानमंत्री और उसकी नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वहीं गौड़ा ने कहा कि क्या सरकार की आलोचना करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज करना ही नया भारत है।

अदालत के प्रति सम्मान न होने के कारण खारिज हुई भट्ट की याचिका

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में सत्र न्यायालय की तरफ से सुनाई गई सजा को चुनौती देने वाली आरोपित पूर्व आइपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका को उनके चाल-चलन व खराब बर्ताव के कारण खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने पाया कि भट्ट अदालत व सत्य का समुचित सम्मान नहीं करते। हिरासत में मौत का मामला 30 साल पुराना है। इसमें सत्र न्यायालय ने भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने जस्टिस बेला त्रिवेदी द्वारा 25 सितंबर को पारित आदेश को सोमवार को अपनी वेबसाइट पर डाला है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि भट्ट को आइपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उनके निर्दोष होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अदालत ने सरकारी वकील मितेश अमीन की दलीलों के साथ-साथ कार्यवाही के दौरान भट्ट के कोर्ट के प्रति रवैये पर भी गौर किया। कोर्ट ने माना कि संजीव भट्ट अदालतों के प्रति सम्मान भाव नहीं रखते हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में गंभीर टिप्पणियां भी कीं।

पहल

कई बुराइयों के अंत तक सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष का एलान, पीड़िताओं ने सुनाई आपबीती, कहा–बस अब और बर्दाश्त नहीं

तत्काल तीन तलाक पीड़िताओं ने दस बुराइयों का किया दहन

जागरण संवाददाता, बरेली

जिस वक्त विजयादशमी पर पूरा देश रावण के अहंकारी रूप का दहन कर रहा था, उसी वक्त बरेली में तत्काल तीन तलाक पीड़िताओं ने मुस्लिम समाज की दस बुराइयों का दहन किया। यह भी एलान किया कि मुस्लिम समाज की उन तमाम कुरीतियों के अंत के लिए महिलाएं सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेंगी। सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगी। इस दौरान पीड़िताओं ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि बस अब और बर्दाश्त नहीं।

मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी की अगुवाई में बरेली के अय्यूब खां चौराहे पर मंगलवार देर शाम 70 से अधिक महिलाएं जुटीं। इनमें कई तत्काल तीन तलाक पीड़िताएं थीं तो कई हलाला और पति के उत्पीड़न का शिकार हुई थीं। सभी के चेहरे पर गुस्सा और नई उम्मीद की किरण साफ झलक रही थी। महिलाओं के सामने था तत्काल तीन तलाक, हलाला, बहुविवाह सहित समाज की दस बुराइयों को समेटे रावण का पुतला।

बरेली में दस बुराइयों का पुतला दहन करतीं मेरा हक फाउंडेशन की फरहत नकवी। जागरण

सभी ने एक स्वर में, 'कमजोर है नारी, भूल है तुम्हारी'... बस अब और नहीं... जैसे कई नारे बुलंद किए।

इस मौके पर फरहत नकवी ने कहा कि जिस तरह विजयादशमी पर श्रीराम ने रावण का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी, उसी तरह आज इन दस बुराइयों का दहन करके पूरी दुनिया को संदेश दिया गया है। अब मुस्लिम महिलाएं अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। उसका मुकाबला करेंगी।

बहुविवाह समेत दस बुराइयों का पुतला फूंकने पर भड़के उलमा : विजयादशमी पर बरेली में मुस्लिम महिलाओं द्वारा तत्काल तीन तलाक व बहुविवाह समेत दस बुराइयों का पुतला दहन किए जाने पर सहारनपुर में उलमा भड़क गए। उनका कहना है कि कुछ महिलाओं द्वारा सस्ती लोकप्रियता पाने को इस तरह के इस्लाम विरोधी काम किए जा रहे हैं। ऐसी महिलाओं को इस्लाम की सही जानकारी नहीं है। तंजीम अब्ना-ए-दारुल उलूम के अध्यक्ष मुफ्ती यादे इलाही कासमी ने कहा कि जो महिलाएं तलाक और बहुविवाह को कुप्रथा बताकर उनका दहन करने की कोशिश कर रही हैं, शायद उन्हें इस्लाम के बारे में सही जानकारी नहीं है।

जमीयत दावतुल मुसलिमीन के संरक्षक कारी इसहाक गोरा ने कहा कि इस्लाम मजहब को जब कोई अच्छे से समझ नहीं पाता तो इसमें खामियां निकालता है। बुराई के रूप में इनका दहन करने वाली महिलाएं मानसिक दिवालिया प्रतीत होती हैं। इसीलिए पुतला दहन जैसे गैरइस्लामी कृत्य में भी शामिल हो रही हैं।

इन दस बुराइयों का किया दहन

1. तत्काल तीन तलाक
2. बेवजह पाबंदियां, कैद
3. बहुविवाह (पहली बीवी की रजामंदी के बगैर दूसरी शादी करना)
4. हलाला प्रथा
5. भ्रूण हत्या
6. एसिड अटैक
7. औलाद न होने पर होने वाली प्रताड़ना
7. नौकरी, व्यवसाय के लिए मुस्लिम महिलाओं पर रोक–टोक
8. बेटियों को पढ़ाई से रोकना।
9. मुस्लिम महिलाओं पर बेवजह फतवे जारी करना
10. महिलाओं का मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न करना

मानहानि मामले में सूरत कोर्ट में कल पेश होंगे राहुल

सूरत, प्रेट्र : कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के सूरत स्थित एक कोर्ट में गुरुवार को पेश होंगे। वह खुद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि के मुकदमे में अपना पक्ष रखेंगे। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी- 'सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?'

राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने मंगलवार को स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अक्टूबर को यहां कोर्ट में उपस्थित होंगे। पार्टी कार्यकर्ता उनका पूरे रास्ते जोरदार स्वागत करेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीएच कपाड़िया ने मई में गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ आइपीसी की धारा 499 व 500 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने राहुल की टिप्पणी को मोदी समाज को अपमानित करने वाला बताया था।

18,173 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है ईडी ने 2019 में सितंबर तक। 2018 में 15,673 करोड़ रुपये तो 2017 में 5,467 करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई थी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 9 अक्टूबर 2019

जारी है प्रकोप ▸ राज्य में 1009 डेंगू और 90 चिकनगुनिया के रोगियों की हुई पहचान

बिहार में बाढ़ के बाद महामारी की तरह फैल रहा डेंगू और चिकनगुनिया

स्वास्थ्य विभाग का दावा, बीमारी से अभी तक किसी की नहीं हुई मौत

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी महामारी की तरह तेजी से फैल रही है। पिछले दिनों दो दिन लगातार बारिश और इसके बाद बाढ़ और जलजमाव की वजह से मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। पिछले चार दिनों में एक हज़ार से अधिक लोग डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी के शिकार हुए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने आज जारी बुलेटिन में बताया कि दो दिन में डेंगू के करीब 30 और चिकनगुनिया के 10 नए रोगियों की पहचान गई है। इसके बाद राज्य में डेंगू पीड़ितों की संख्या 109 और चिकनगुनिया रोगियों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। सिर्फ पटना में डेंगू के 662 और चिकनगुनिया के 76 रोगियों का सरकारी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। निजी अस्पतालों में भर्ती डेंगू चिकनगुनिया के रोगी इसमें शामिल नही हैं।

बाढ़ के बाद फैले डेंगू और चिकनगुनिया की चपेट में आकर पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज। प्रेट्र

पटना के बाद भागलपुर में डेंगू के सर्वाधिक रोगी मिले हैं। भागलपुर में डेंगू के 95, नालंदा में 25, औरंगाबाद व पूर्णिया में 13-13, मुजफ्फरपुर और नवादा में 12-12, मधुबनी में 11, बेगूसराय में 9 और शेष प्रभावित जिलों में इनकी संख्या 7 से 2 के बीच है।

स्वास्थ्य विभाग ने पटना में पीएमसीएच, एनएमसीएच के साथ ही 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू और चिकनगुनिया की जांच और इलाज की सुविधा दिए जाने का दावा किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि सरकार डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठा रही है। जिन क्षेत्रों से पानी निकल चुका है वहां लगातार फॉगिंग कराई जा रही है। ब्लीचिंग पाउडर और चूने के मिश्रण का छिड़काव कराया जा रहा है। उन्होंने कहा स्वास्थ्य विभाग और बिहार स्वास्थ्य समिति संयुक्त रूप से बीमारी के खिलाफ युद्धस्तर पर लगे हुए हैं। प्रधान सचिव ने डेंगू और चिकनगुनिया पीड़ितों की जांच के लिए 10, 11 और 12 अक्टूबर को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल में कैंप लगाया जा रहा है। पीड़ित यहां आकर मुफ्त जांच और इलाज करा सकेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग घर के आसपास सफाई रखें। चुना और ब्लीचिंग का छिड़काव करें। पानी उबाल कर पीएं।

प्रधान सचिव ने कहा कि पटना और राज्य के दूसरे सरकारी अस्पतालों में डेंगू व चिकनगुनिया के रोगियों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बीमारी से अब तक किसी की मौत नही हुई है।

मौत के दो साल बाद हाई कोर्ट ने दिलाए सेवानिवृत्ति लाभ

कमल जोशी, चंडीगढ़

- चंडीगढ़ का मामला, 1982 में शुरू की थी नौकरी, 2005 में किया गया था नियमित
- पेंशन निर्धारण में 20 साल का सेवाकाल नहीं किया गया था शामिल

गुरदासपुर की बटाला नगर परिषद में वर्ष 2005 में नियमित किए गए एक कर्मचारी के परिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता बलबीर कुमार के निधन के दो साल बाद उसके अस्थायी सेवाकाल को भी उनके सेवानिवृत्ति लाभ में शामिल किए जाने के आदेश दिए हैं। उन्हें साल 2004 से पहले मिलने वाली पेंशन योजना में शामिल किए जाने के आदेश दिए हैं।

बलबीर सिंह ने याचिका में कहा था कि पंजाब सरकार ने उनके सेवानिवृत्ति लाभ निर्धारित करने में अस्थायी कर्मचारी के तौर पर उनके दशकों के कार्यकाल को शामिल नहीं किया। याचिकाकर्ता ने साल 1982 में पहली बार अस्थायी कर्मचारी के तौर पर बटाला नगर परिषद में सेवा शुरू की थी। साल 1982 व 1983 में दो बार सेवा से हटाए जाने के बाद उन्हें फिर प्लंबर के तौर पर अस्थायी सेवा में रख लिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से सेवा के लिए निधार्रित शर्तें पूरी न कर पाने के चलते उनकी सेवाओं को 20 साल से भी अधिक समय तक नियमित नहीं किया गया।

वर्ष 2005 में बटाला नगर परिषद ने अपने ही एक प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता की सेवा को पहले ही नियमित कर दिया जाना चाहिए था। इसके बाद उनकी सेवाओं को मई, 2005 में नियमित कर दिया गया, लेकिन सेवानिवृत्ति के समय उनकी पेंशन निर्धारित करते हुए उनके लगभग 20 साल के सेवाकाल को उनकी सेवा में शामिल नहीं किया। इस वजह से उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की बजाय 1 जनवरी, 2004 से लागू की गई नई पेंशन योजना में शामिल किया गया। जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि लंबे समय तक याचिकाकर्ता की सेवा नियमित न किए जाने के चलते उसे पुरानी पेंशन योजना से वंचित करने के बटाला नगर परिषद के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पूरे कार्यकाल को उनके सेवाकाल में शामिल करने के आदेश दिए।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

जस्टिस मोंगा ने कहा कि याचिकाकर्ता के कानूनी वारिसों को उनके बकाया सेवानिवृत्ति लाभ छह फीसद ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं।

पिकनिक मनाने देहरादून गए दो छात्र नदी में डूबे

जागरण संवाददाता, देहरादून: राजपुर क्षेत्र के चंद्रौटी में दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए दो छात्र टौंस नदी में बह गए और चंद मिनट में ही नजरों से ओझल हो गए। यह सब देख रहे दोस्तों ने शोर मचाना शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस व एसडीआरएफ ने करीब तीन घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों छात्रों के शव बरामद किए। एक छात्र गोंडा (उत्तर प्रदेश), जबकि दूसरा देहरादून के सहसपुर का रहने वाला था।

मृत छात्रों की पहचान अंशुमान शुक्ला पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम खड़फपुर, गोंडा (उत्तर प्रदेश) व सचिन पुंडीर पुत्र सुभाष निवासी ग्राम तिपरपुर, सभावाला, सहसपुर, देहरादून के रूप में हुई है। दोनों राजपुर रोड स्थित जाखन क्षेत्र में रहमान हास्टल में रहते थे और एनडीए की तैयारी कर रहे थे। मंगलवार को अंशुमान और सचिन हास्टल में रहने वाले दोस्तों सनी, तुषार, अमन, अबू बकर, विवेक सिंह, आयुष, शिवम व रुद्राक्ष के साथ चंद्रौटी में पिकनिक मनाने गए थे। दोस्तों ने पुलिस को बताया कि टौंस नदी में अंशुमान, सचिन और सनी नहाने की जिद करने लगे। तीनों ने कहा कि वह नदी में ऊंचाई से छलांग लगाकर नदी पार कर लेंगे। अंशुमान और सचिन ने छलांग लगा दी, लेकिन सनी रुक गया। अंशुमान और उसके बाद सचिन ने नदी में जिस जगह पर छलांग लगाई, वहां गहराई अधिक थी और पानी का बहाव भी तेज था। लिहाजा दोनों डूबने-उतराने लगे। दोनों ने हाथ-पांव मार कर नदी के पार जाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान नजरों से ओझल हो गए। पुलिस ने मृतक छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी है।

एसटीएफ ने नोएडा से दो सुपारी किलर समेत तीन बदमाश दबोचे

जागरण सं, बुलंदशहर

खुर्जा नगर और एसटीएफ नोएडा ने संयुक्त रूप से दबिश देकर दो सुपारी किलर समेत तीन बदमाशों को रविवार रात दबोच लिया। 15 लाख में दो सुपारी किलर ने खुर्जा निवासी युवक की हत्या की सुपारी ली थी। पकड़े बदमाशों में सुपारी देने वाला आरोपित बदमाश भी शामिल है। इनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। हत्या दशहरा के दिन होनी थी।

खुर्जा नगर थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि खुर्जा नगर स्थित एक मकान में तीन शूटर किसी की हत्या के इरादे से एकत्र हैं। इस पर पुलिस और नोएडा एसटीएफ ने खुर्जा नगर निवासी सूर्य प्रताप सिंह के मकान पर दबिश दी। पुलिस ने वहां से सूर्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की, सचिन कुमार निवासी व राजू को दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद में सूर्य प्रताप सिंह ने सचिन व राजू को उस्मानपुर गांव निवासी युवक अर्जुन की हत्या के लिए 15 लाख की सुपारी दी थी। हत्या में सूर्य प्रताप को भी शामिल होना था। पुलिस के मुताबिक सूर्य प्रताप सिंह उर्फ विक्की पर गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर और गाजियाबाद में करीब 10 मुकदमे, सचिन पर तीन मुकदमे और राजू पर पांच मुकदमे दर्ज हैं।

> अर्जुन की हत्या के लिए 15 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। पुलिस की सजगता से एक युवक की जान बच गई। नोएडा एसटीएफ को भी बदमाशों की लोकेशन खुर्जा नगर में मिली थी।
> –आरके मिश्रा, सीओ एसटीएफ, नोएडा

जेल में लिखी गई थी हत्या की पटकथा : पुलिस के मुताबिक 1993 में सूर्यप्रताप के पिता सुरेंद्र पाल सिंह निवासी मुरारीनगर द्वितीय, खुर्जा ने कृष्णा देवी पत्नी शंकर लाल निवासी कानपुर से जमीन की वसीयत कराई थी। जबकि उस्मानपुर निवासी शिवकुमार व अर्जुन ने इसी जमीन की कृष्णा देवी से पॉवर ऑफ अटारनी करा ली थी। शिवकुमार और अर्जुन कोर्ट से मुकदमा जीत गए। इसके बाद दोनों ने उक्त जमीन पर बने सूर्य प्रताप के सीसीटीवी कैमरे का कार्यालय तोड़कर सामान अपने पास रख लिया था। इससे सूर्य प्रताप, अर्जुन से रंजिश रखने लगा। जेल में सूर्य प्रताप की मुलाकात सचिन कुमार से हुई और दोनों ने अर्जुन की हत्या की योजना बनाई। इस योजना में सचिन ने अपने गांव निठारी निवासी राजू को शामिल कर लिया। किसी को उन पर शक न हो, इस लिए सूर्यप्रताप के भाई हेमंत को छह अक्टूबर को किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाना था।

मप्र कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सिंधिया विरोधी खेमे से बढ़ा रहे नजदीकी

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब राज्य में नया सियासी दांव चला है। परस्पर विरोधी माने जाने वाले अपनी ही पार्टी के नेताओं के समर्थकों से वह नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। किसी के घर पहुंचकर भोजन (लंच-डिनर) कर रहे हैं तो किसी से दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने खुद को सभी गुटों में सर्वमान्य बनाने के लिए कमलनाथ सरकार के फैसलों में सहमति देने की रणनीति पर अमल शुरू किया है।

मुख्यमंत्री कमलनाथ कई बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से मुक्त करने की पेशकश कर चुके हैं। इससे कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सिंधिया गुट के चर्चित चेहरों के नाम भी सामने आने लगे हैं। सरकार के मंत्रियों बाला बच्चन, जीतू पटवारी व उमंग सिंघार, अजय सिंह, रामनिवास रावत जैसे नेताओं के नाम चर्चा में भी आए। वहीं, समर्थकों ने सिंधिया को ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग खुलकर की। उनके समर्थक मंत्रियों इमरती देवी, प्रद्युम्नसिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो सार्वजनिक रूप से बयान भी दिए।

ज्योतिरादित्य सिंधिया। फाइल

- किसी के घर पहुंचकर कर रहे भोजन तो किसी की नियुक्ति पर दे रहे सहमति
- प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में अपनी तरफ से नहीं कर रहे कोई भी दावा

डॉ. गोविंद सिंह से किए रिश्ते बेहतर : सिंधिया ने स्वयं कभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी नहीं की, लेकिन कुछ समय से उन्होंने सियासी दांव बदला है। एक समय उनके घोर विरोधी रहे मंत्री डॉ. गोविंद सिंह से अब उनके रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। पिछले दिनों जब डॉ. सिंह के खिलाफ सिंधिया समर्थक विधायकों ने बयानबाजी की थी तो सिंधिया ने विधायकों को समझाइश देकर डॉ. सिंह के खिलाफ बयानबाजी बंद करवाई। जल्द ही वे भिंड प्रवास पर जाने वाले हैं।

अशोक सिंह के नाम पर सहमति

दिग्विजय सिंह समर्थक ग्वालियर के अशोक सिंह की अपेक्स बैंक में प्रशासक के रूप नियुक्ति पर भी सिंधिया ने सहमति देने में देरी नहीं की। हालांकि, इसके पहले अशोक सिंह को लोकसभा टिकट देने में भी नेतृत्व की ओर से सिंधिया से राय-मशविरा किया गया था और सिंधिया ने सहमति दी थी।

हर गुट के नेता की ओर झुकाव

सिंधिया के नए सियासी दांव में देखने में आया है कि उनके हाल के दौरों में हर गुट के नेता से वह मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वह ध्यान रखते हैं कि एक बार अपने समर्थक से न मिलें, लेकिन दूसरे खेमे के नेताओं से जरूर भेंट करें। इंदौर में मप्र क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के पहले वह अपने समर्थक नेताओं के बजाय विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, विनय बाकलीवाल, पंकज संघवी के घर गए। किसी के यहां सिंधिया ने सुबह का खाना खाया तो किसी के घर नाश्ता किया।

आवाज का मिलान होने से बढ़ेंगी आरोपितों की मुश्किलें

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

विशेष जांच दल (एसआइटी) बुधवार को चिन्मयानंद, छात्रा व उसके दोस्त संजय सिंह, विक्रम सिंह और सचिन सेंगर को आवाज के सैंपल लेने के लिए लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जा सकता है। इसके लिए एसआइटी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से पांचों का रिमांड भी ले चुकी है, लेकिन दशहरा के अवकाश के चलते सुरक्षा कारणों से नहीं ले जा सकी। यदि वॉयस सैंपल व वायरल वीडियो में रिकार्ड आवाज का मिलान हो जाता है तो आरोपितों की मुश्किलें बढ़ना तय है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर छात्रा ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। वहीं, चिन्मयानंद की ओर से छात्रा, उसके दोस्त संजय, विक्रम और सचिन पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में 10 सितंबर को चिन्मयानंद के आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए थे। उसी दिन रंगदारी प्रकरण से जुड़ा हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं, रंगदारी से जुड़ा दूसरा वीडियो 26 सितंबर को वायरल हुआ था। इसके अलावा छात्रा की ओर से पेन ड्राइव में भी 43 क्लिप एसआइटी को सौंपी गई है। एसआइटी दोनों प्रकरण की जांच में अब तक कई अहम साक्ष्य जुटा चुकी है। वायरल हो रहे वीडियो की भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई थी। जिसमें वीडियो सही होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके आधार पर ही पांचों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब एसआइटी पांचों आरोपितों का वॉयस सैंपल लेकर उनका मिलान वीडियो में रिकार्ड आवाज से कराने की तैयारी में है। आवाज का मिलान होने पर आरोपितों पर एसआइटी अपना शिकंजा और कस सकती है। साथ ही 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट में इसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है।

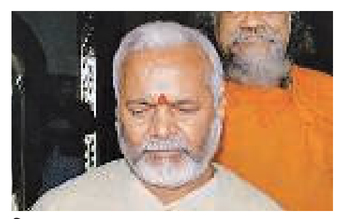

चिन्मयानंद। फाइल

चिन्मयानंद प्रकरण

- लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लिया जाएगा वॉयस सैंपल
- वायरल वीडियो व छात्रा द्वारा पेन ड्राइव में सौंपी गई क्लिप से होगा मिलान

हिमाचल में बारालाचा व रोहतांग दर्रा बहाल, जोखिम अभी भी बरकरार

जागरण संवाददाता, मनाली

बर्फबारी से बंद हुआ बारालाचा व रोहतांग दर्रा वाहनों के लिए बहाल हो गया। बारालाचा में आठ इंच जबकि रोहतांग दर्रे में आधा फीट से बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। बारालाचा दर्रे के बहाल हो जाने से मनाली-लेह मार्ग पर एक बार फिर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। शिंकुला दर्रे के बहाल न होने से जांस्कर घाटी का लाहुल से संपर्क कटा हुआ है। कुंजम दर्रे के बहाल हो जाने से मनाली काजा मार्ग पर भी वाहन सरपट दौड़ने लगे हैं।

रोहतांग दर्रे में राहनीनाला की अपेक्षा राक्षी ढांक की ओर बर्फबारी अधिक हुई है। हालांकि मनाली प्रशासन ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और स्थानीय युवाओं के सहयोग से रोहतांग दर्रे में फंसे 150 वाहनों को सोमवार को ही निकाल लिया था, जिससे सड़क भी बहाल हो गई थी। अधिकतर लोगों ने मनाली और कोकसर में ही शरण ले रखी थी। मंगलवार सुबह मौसम साफ होता देख दोनों ओर से 100 से अधिक वाहनों सहित एचआरटीसी की बसों ने रोहतांग दर्रे को आर पार किया। मंगलवार होने के चलते रोहतांग दर्रा सैलानियों के लिए बंद है लेकिन 100 से अधिक छोटे व बड़े वाहनों ने दर्रा आर पार किया है। हालांकि मनाली से लाहुल जाने वाले लोगों की संख्या कम है लेकिन लाहुल से मनाली आने वाले लोग ज्यादा हैं। कुल्लू में दशहरे का आगाज होने से लाहुल की ओर से लोगों का कुल्लू आने का दौर लगातार जारी है। मनाली से लाहुल गए अशोक, राजू और दीपक ने बताया कि सड़क तो बहाल हो गई है लेकिन इसके किनारे बर्फ जमने से जोखिम बढ़ गया है। धूप लगने के बाद कि सफर सुरक्षित है। सुबह व शाम को वाहन स्किड हो रहे हैं। बीआरओ कमांडर कर्नल उमा शंकर ने बताया कि बीआरओ ने सड़क बहाल कर ली है। मनाली दारचा के बीच बीआरओ का सड़क निर्माण कार्य जारी है। मनाली एसडीएम रमन घरसंगी ने कहा कि मंगलवार को बीआरओ का मेटिनेश डे है। इस कारण सैलानियों के लिए रोहतांग दर्रा बंद रहा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि मौसम देख ही दर्रे को आर-पार करें।

सोमवार को रोहतांग दर्रे में बर्फबारी होने के कारण फंस गए थे कई वाहन। फाइल

जौड़ा फाटक हादसे के पीड़ितों ने मांगा इंसाफ

जागरण संवाददाता, अमृतसर

19 अक्टूबर 2018 को दशहरे के दिन जौड़ा फाटक रेलवे ट्रैक रक्तरंजित हो गया था। यहां रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर दशहरा देख रहे 59 लोग के ऊपर से पठानकोट से आई डीएमयू गुजर गई थी। मंगलवार को हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों के लोग इंसाफ के लिए सड़क पर उतरे तो एक बार फिर साल बाद दशहरे का जख्म ताजा हो गया। जौड़ा फाटक हादसे के पीड़ित परिवारों ने पंजाब सरकार एवं स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये परिवार उसी ट्रैक पर धरना लगाने जा रहे थे, जहां हादसा हुआ था। लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इसके बाद गुस्साए लोग जौड़ा फाटक के समीप ही धरना लगाकर बैठ गए। लोग कह रहे थे कि हमें ट्रैक पर जाने दो, हम भी रेल के नीचे कटकर अपनी जान दे देंगे।

सुबह तकरीबन सवा नौ बजे जौड़ा फाटक के समीप पहुंचे पीड़ित परिवारों की आंखों में जहां सरकार के प्रति आक्रोश था, वहीं हादसे का दर्द भी। इस हादसे में अपने पिता व चाचा को खो चुके दीपक कुमार ने कहा कि सरकार ने सरकारी नौकरी देने का वायदा पूरा नहीं किया। लोगों के घरों का चूल्हा तक ठंडा पड़ा है। लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। इस हादसे के कसूरवार नवजोत कौर सिद्धू को ठहराते हुए दीपक ने कहा कि यदि वह उस दिन निर्धारित समय पर आ जातीं तो 59 लोगों की जान न जाती। उनके पति नवजोत सिद्धू ने तो इन परिवारों को अडाप्ट करने की बात कही थी, पर सिद्धू दंपती ने परिजनों की कभी सुध तक नहीं ली। राजेश कुमार नामक शख्स ने बताया कि उनके पिता बलदेव कुमार हादसे में गंभीर जख्मी हुए थे। पांच माह बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज तक उनका नाम मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया गया।

नेताओं ने सेकीं सियासी रोटियां : धरना के बीच नेता भी सियासी सियासी रोटियां सेकनें पहुंचे। कांग्रेस के पूर्व महासचिव मनदीप सिंह मन्ना ने कहा कि इन लोगों की यह गलती है कि इन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव जितवाया। उधर, पंजाब एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि यह हादसा सरकार की लापरवाही का प्रमाण है। सरकार अपने नेताओं व अधिकारियों को बचाती रही है।

पीड़ित परिवारों ने 22 अक्टूबर का अल्टीमेटम दिया : तकरीबन ढाई बजे जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम विकास हीरा धरनाकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने उन्हें धरना उठाने की अपील की। लोगों से साफ कहा कि उन्हें इंसाफ चाहिए। लोगों ने कहा कि वह सरकार को 22 अक्टूबर तक का समय दे रहे हैं।

19 अक्टूबर 2018 को दशहरे के दिन जौड़ा फाटक रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को रेल ट्रैक धरना देने जाने से रोकते पुलिस कर्मी। हादसे में 59 लोगों की मौत हुई थी। जागरण

बीस वर्ष से होता रहा है आयोजन इस वर्ष नहीं जला रावण

जौड़ा फाटक में बीस वर्षों से रावण दहन किया जाता रहा है। पिछले वर्ष हुए हादसे के बाद इस बार यहां दशहरा नहीं मनाया गया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने जौड़ा फाटक के दोनों गेट बंद कर दिए थे। लोगों को लिंक रास्तों से भेजा गया।

अनुष्ठान

विशेष पूजा के लिए खास वेशभूषा में दिखे उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, परंपरा के अनुसार योगी चार दिन बाद नाथजी के विशेष अनुष्ठान के लिए मठ से नीचे उतरे

धर्म और राजनीति के संगम का साक्षी बना गोरखनाथ मंदिर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। इनको अलग-अलग देखने वाला न धर्म को जानता है, न राजनीति को। विजयादशमी के दिन मंगलवार को गोरक्षपीठ इसी धर्म और राजनीति के संगम का साक्षी बना। गोरक्षपीठाधीश्वर व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विजयादशमी पर शिवावतारी श्रीनाथ जी (गुरु गोरक्षनाथ) की श्रद्धा के साथ विशेष पूजा एवं अनुष्ठान किया। गोरक्षपीठाधीश्वर की भव्य शोभायात्रा मंदिर परिसर में निकली, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में कड़ी सुरक्षा के बाद भी डटी रही।

नवरात्रि के परंपरागत अनुष्ठान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकाज और परंपरा के निवर्हन के संकल्प के साथ चार दिन से मठ में ही हैं। परंपरा के मुताबिक मंगलवार को वह चार दिन बाद नाथजी के विशेष अनुष्ठान के लिए मठ से नीचे उतरे। खास पूजा के लिए उनकी वेशभूषा भी खास थी। साथ में मंदिर के पुजारी और अन्य लोग भी थे। करीब 100 की संख्या में वेद पाठी बालक शस्त्र त्रिशूल, तलवार लिए सैनिक के रूप में उनके साथ सुरक्षा में चल रहे थे।

गोरक्षपीठाधीश्वर के साथ प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ एवं योगी सूरजनाथ, योगी प्रेमनाथ समेत बड़ी संख्या में योगी श्रद्धाभाव से साथ चल रहे थे। घंटे और घड़ियाल की धुन और गुरु गोरक्षनाथ के जयकारे के बीच वह मुख्य मंदिर के गर्भगृह में गये और नाथजी की पूजा की। एक घंटे तक चले इस अनुष्ठान में ढोल नगाड़े के बीच भव्य आरती हुई। इस दौरान गोरक्षपीठाधीश्वर के साथ सिर्फ उनके साथी कमलनाथ एवं सूरजनाथ मौजूद रहे।

श्रीनाथ की पूजा के बाद गोरक्षपीठाधीश्वर ने भैरव मंदिर, दुर्गा मंदिर, रामदरबार, अखण्ड धूनी, हनुमान मंदिर, श्रीकृष्ण दरबार समेत सभी प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं का दर्शन कर पूजन किया। उसके बाद उनका काफिला भगवान भीम की प्रतिमा के समक्ष पहुंचा, जहां उन्होंने पूजन किया। उसके बाद भीम सरोवर पर पहुंच कर पूजन किया। यहां उन्होंने सरोवर की मछलियों को भोजन कराया। इसके बाद गोरक्षपीठाधीश्वर, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं ब्रह्मलीन महंत अपने गुरु अवेद्यनाथ की समाधि पर माथा टेक कर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद पुनः मंदिर में पहुंच कर वहां गुरु गोरक्षनाथ समेत स्थापित सभी देव प्रतिमाओं का पूजन किया। इसके बाद वे गोशाला पहुंचे जहां उन्होंने 20 मिनट तक वक्त विताया। गायों को गुड़ व चना खिलाकर आशीर्वाद लिया।

गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में योगी...: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मंगलवार को विजयादशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में नजर आये। इस अवसर पर पारंपरिक शोभायात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ। संगम दूबे

एनटीसीए ने कार्बेट के ढिकाला में बाघ पकड़ने की अनुमति नहीं दी

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- अब शासन की ओर से इस बारे में एनटीसीए के समक्ष रखा जाएगा पक्ष
- ढिकाला क्षेत्र में बाघ ने जुलाई और नवंबर में एक-एक व्यक्ति को बनाया था निशाना

कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढिकाला क्षेत्र में सक्रिय बाघ के आदमखोर होने की आशंका को देखते हुए परीक्षण के लिए इसे पकड़ने की अनुमति देने की वन्यजीव महकमे की मांग राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने ठुकरा दी है। इसे देखते हुए अब शासन की ओर से राज्य के पक्ष को एनटीसीए के समक्ष रखा जाएगा।

ढिकाला क्षेत्र में बाघ ने बीते वर्ष नवंबर और इस साल जुलाई में एक-एक व्यक्ति को मार डाला था। इसे देखते हुए वन्यजीव महकमे ने बाघ को परीक्षण के लिए ट्रेंकुलाइज कर पकड़ने की एनटीसीए से अनुमति मांगी थी। महकमे का कहना था कि बाघ को पकड़ उसे रेडियो कॉलर पहनाकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा।

एनटीसीए ने महकमे की इस मांग को ठुकरा दिया है। उसका कहना है कि ढिकाला क्षेत्र बाघों के वासस्थल की दृष्टि से संवेदनशील है। फिर वहां जिन दो लोगों की मौत हुई है, उसमें काफी लंबा अंतराल है। लिहाजा, बाघ को ट्रेंकुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है।

गौरतलब है कि एनटीसीए ने हाल में सभी राज्यों को आदेश जारी किए हैं कि बाघों को ट्रेंकुलाइज करने के संबंध में पहले उससे अनुमति ली जाए। इसी कड़ी में राज्य के वन्यजीव महकमे ने ढिकाला में सक्रिय बाघ को लेकर अनुमति मांगी थी। अब एनटीसीए के इनकार से यह सवाल खड़ा हो गया है कि यदि बाघ के हमले में कोई जनहानि होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सूत्रों ने बताया कि इस मसले को देखते हुए अब राज्य के पक्ष को पूरे तथ्यों के साथ शासन की ओर से एनटीसीए को भेजा जाएगा।

167 बार इंटरनेट बंद किया गया जम्मू और कश्मीर में 2015-2019 तक। 2019 में अब तक 55 बार, 2018 में 65 बार नेट बंद किया गया था। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) इंडिया ने यह जानकारी दी है।

कश्मीर में लश्कर का एरिया कमांडर साथी सहित ढेर

आतंक पर प्रहार ▸ पांच अगस्त के बाद दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में हुई पहली मुठभेड़, अभियान जारी

व्यापारियों को धमकाता था और कई जगह जलाई थी फसल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

सुरक्षाबलों ने कश्मीर में अपने आतंकरोधी अभियान को जारी रखते हुए मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात एरिया कमांडर उफैद फारूक उर्फ अबु मुस्लिम समेत दो आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल, उसके अन्य साथियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षाबलों ने अपना अभियान जारी रखा हुआ है। मारा गया उफैद कई आतंकी वारदात में शामिल था। वह व्यापारियों और दुकानदारों को भी दुकानें बंद रखने और माल मंडियों में न भेजने के लिए धमकाता था।

पांच अगस्त के बाद दक्षिण कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच यह पहली मुठभेड़ है। बीते दो माह के दौरान कश्मीर में अब तक सिर्फ चार मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें छह आतंकी मारे गए हैं। इनमें दो मुठभेड़ उत्तरी कश्मीर के बारामुला व सोपोर, एक जिला गांदरबल और एक आज सुबह अवंतीपोरा में हुई।

जानकारी के अनुसार, तड़के सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के एक संयुक्त कार्यदल ने जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर कैवान गांव के पास आतंकियों के एक दल को देखे जाने की सूचना पर तलाशी अभियान चलाया। जवानों को अपने ठिकाने की तरफ आते देख आतंकियों ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में कुछ देर बाद एक आतंकी मारा गया। जबकि दूसरा आतंकी शाम को मारा गया। फिलहाल सुरक्षाबलों ने एहतियातन अभियान जारी रखा हुआ है। मारे गए आतंकियों की पहचान उफैद फारूक लोन और अब्बास के रूप में हुई है। दोनों अवंतीपोर के रहने वाले हैं। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि पांच अगस्त के बाद उफैद अक्सर अवंतीपोरा, पडगामपोरा और उसके साथ सटे इलाकों में लोगों को जबरन बंद के लिए धमकाता था। इसके अलावा उसने कई पंच-सरपंचों के घरों में जाकर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट भी की। वह स्थानीय व्यापारियों और सेब उत्पादकों को भी अपना माल मंडियों में भेजने से जबरन रोक रहा था और फरमान न मानने वाले कई व्यापारियों के सामान को भी उसने जलाया था।

हमलों के लिए ग्रेनेड उपलब्ध करवाता था उफैद : जानकारी के अनुसार उफैद करीब एक साल पहले चार जुलाई 2018 को लश्कर में सक्रिय हुआ था। उफैद पांपोर, त्राल, रेशीपोरा, अवंतीपोरा और मलंगपोरा स्थित एयरफोर्स के एयरबेस के आसपास की स्थित बस्तियों में ज्यादा सक्रिय रहा है।

आतंकी बनने से पहले भी वह कई बार पत्थरबाजी के आरोप में पकड़ा गया था। वह लश्कर का ओवरग्राउंड वर्कर भी रह चुका है। करीब एक साल से उफैद ने त्राल, अवंतीपोरा, पुलवामा, पंथाचौक और पांपोर में सुरक्षाबलों पर हुए लगभग सभी ग्रेनेड हमलों के लिए ग्रेनेड उपलब्ध कराए हैं।

अवंतीपोर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मोर्चा संभाले जवान। एएनआइ

पाक ने नियंत्रण रेखा पर सक्रिय किए 20 आतंकी शिविर

नई दिल्ली, प्रेट्र : सर्दियों की शुरुआत से पहले जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कराने के इरादे से पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर कम से कम 20 आतंकी शिविर और 20 लांच पैड को सक्रिय कर दिया है। यहां सक्रिय हर प्रशिक्षण शिविर और लांच पैड में कम से कम 50 आतंकवादी हैं। गौरतलब है कि बालाकोट पर हवाई हमले के बाद पड़ोसी देश ने इस तरह के आतंकी शिविरों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, लेकिन अब यह फिर से सक्रिय हो गए हैं। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 370 को खत्म करने के बाद पाक एजेंसियां जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमला करने की साजिश कर रही थीं, लेकिन इसमें विफल रहने पर अब वे जम्मू-कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी भेजने की ताक में हैं। अधिकारी ने बताया, 'हमारे पास खुफिया जानकारी है कि पाकिस्तान ने कम से कम 20 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर और 20 लांच पैड को सक्रिय किया है। प्रत्येक में कम से कम 50 आतंकी हैं। ये आतंकी नियंत्रण रेखा के जरिये मौका मिलते ही घुसपैठ करने की फिराक में हैं।' सुरक्षा बलों की सतर्कता के बावजूद हाल के सप्ताह में कई आतंकी घुसपैठ करने में सफल रहे हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि ऐसी खुफिया जानकारी भी मिली है कि जम्मू-कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मुहम्मद से जुड़े शीर्ष आतंकियों ने हाल ही में एक बैठक की है और सुरक्षा बलों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर हमले तेज करने का निर्णय लिया है।

स्थानीय युवकों को आतंकी संगठनों में करता था भर्ती

उफैद स्थानीय युवकों को भी आतंकी संगठनों में भर्ती करता था। उसने दक्षिण कश्मीर में कम से कम छह युवकों को आतंकी बनाया और उनमें से बराबंदिना का रहने वाला आकिब भी है। आकिब इसी साल जून माह के दौरान लश्कर का सक्रिय आतंकी बना है।

28 साल पहले सम्भल से पाकिस्तान चला गया था उमर

राघवेंद्र शुक्ल, सम्भल : अफगान- अमेरिकी सेना के संयुक्त ऑपरेशन में मारे गए आतंकी शना उल हक उर्फ उमर गलत संगत में पड़कर बिगड़ गया था। करीब 28 साल पहले 1991 में उसने सम्भल छोड़ा था तो किसी को नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पाकिस्तान के संपर्क में आना और वहां से आतंकी संगठनों के जुड़ाव ने उसको एक ऐसी राह पर धकेल दिया था, जिसका अंत उसकी मौत के साथ हो गया। परिवार वालों ने भी उससे रिश्ता-नाता तोड़ लिया था।

1996 में इंटेलीजेंस रिपोर्ट के बाद दिल्ली की खुफिया टीम सम्भल में उमर के घर पहुंची थी। खुफिया अधिकारियों ने परिजनों को बताया था कि उमर पाकिस्तान चला गया है और आतंकी संगठनों के साथ है। इस पर परिजनों ने भी सीधे कह दिया था कि अब उस बेटे से उनका कोई रिश्ता नहीं है। उस समय जीवित पिता ने बेटे से सारे भावनात्मक संबंध खत्म कर लिए थे। कुछ दिन पहले ही उस पिता का भी इंतकाल हो गया, जबकि पिता के अच्छे अनुशासन और बेहतर शिक्षा ने एक बेटे को इंजीनियर बनाया है तो दूसरे को शिक्षक।

अमेरिकी और अफगानी सेना की संयुक्त कार्रवाई में मारा गया तालिबानी आतंकी उमर भारत में अलकायदा का चीफ था और समय के साथ वह आतंकी संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका था। उस पर यह कार्रवाई सितंबर माह के शुरुआती दिनों में ही की गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि अफगानी सेना ने अब की है।

सरहदी गांवों में रात में दिखा ड्रोन, बीएसएफ ने चलाया सर्च अभियान

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर: हुसैनीवाला बॉर्डर के नजदीक लगते गांवों में सोमवार देर रात पाकिस्तान से आए ड्रोन के उड़ने की खबर ने बीएसएफ व पुलिस की नींद उड़ा दी। मंगलवार को दिन चढ़ते ही बीएसएफ ने पुलिस के साथ संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। जवानों ने तारबंदी के नजदीक खेतों का कोना-कोना खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा।

सरहदी गांवों गट्टी राजोके, हजारा सिंह वाला, चांदी वाला आदि के लोगों ने बताया कि देर रात उन्होंने तार के पास ड्रोन जैसी चीज उड़ती देखी। पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन गांव के अन्य लोगों ने भी यही बात बताई। सुबह बीएसएफ व पुलिस ने सरहदी इलाकों में तलाशी अभियान के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की। जांच के दौरान खेतों में भी सर्च की गई। देर शाम तक जवानों के हाथ कुछ नहीं लगा।

बता दें कि कुछ दिन पहले तरनतारन में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भारत भेजे जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में कुछ आतंकियों को भी गिरफ्तार किया था। उसी के बाद से यह सतर्कता बरती जा रही है।

बीएसएफ ने सरहदी क्षेत्र से पकड़ी दो किलो हेरोइन: बीएसएफ ने बॉर्डर आउट पोस्ट दल के नजदीक बीती रात पाकिस्तान से आई दो किलो हेरोइन बरामद की। दरअसल, देर रात जवानों ने उस इलाके में कुछ हरकत होती देखी। जवानों ने तस्करों को ललकारा, लेकिन वे भाग निकले। जवानों ने मौके पर जाकर देखा तो दो पैकेट हेरोइन बरामद हुई।

न्यूज गैलरी

बालाकोट व कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलाबारी

पुंछ : पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को नियंत्रण रेखा पर पुंछ के बालाकोट व कृष्णा घाटी सेक्टर में भारी गोलाबारी की। देर शाम तक जारी रही इस गोलाबारी से कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय सेना ने भी पाक सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। जानकारी के अनुसार, शाम को पाक सेना ने पहले बालाकोट फिर कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर गोलाबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई पर पाक ने दोनों सेक्टरों में रिहायशी क्षेत्रों पर मोर्टार दागने शुरू कर दिए। देर शाम तक दोनों तरफ से रुक रुककर गोलाबारी जारी रही। इससे पूर्व सोमवार रात भी पाकिस्तानी रेंजरों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर के पानसर और मन्यारी के बीच भारी गोलीबारी की। बीएसएफ के जवानों ने रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया। क्षेत्र के निवासी प्रमोद कुमार, देवेन्द्र, बलबंत राज ने कहा, रेंजर आग लगाने वाली ट्रेसर राउंड भी दाग रहे हैं, ताकि ग्रामीणों को अधिक से अधिक नुकसान हो। दो दिन पहले मन्यारी में ऐसे ही दो घरों में आग लग गई थी। (जान्यू)

सहारनपुर में भाजपा नेता की गोलियों से भूनकर हत्या

सहारनपुर : सहारनपुर में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और मिरगपुर प्रधान के बड़े भाई चौधरी यशपाल सिंह की मंगलवार को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया। घटना को प्रधानी की रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पूछताछ के लिए पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। यशपाल के बेटे की ओर से गांव के ही छह लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई है। जानकारी के अनुसार, चौ. यशपाल सिंह दोपहर बाद करीब एक बजे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाइक से निकले थे। रास्ते में हमलवारों ने घेर लिया और आधा दर्जन गोलियां मार कर हत्या कर दी। (जासं)

लखनऊ में एटीएस कमांडो ने खुद को गोली से उड़ाया

लखनऊ : सरोजनीनगर स्थित आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) मुख्यालय में कमांडो बृजेश कुमार यादव ने कनपटी पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बिस्तर पर उनका शव लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। मौके से लाइसेंसी पिस्टल, शराब की बोतल और एक खोखा बरामद हुआ है। मूलरूप से गोरखपुर के गांव चिउटहा निवासी बृजेश की पत्नी से फोन पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। आशंका है कि इसी बात से नाराज होकर बृजेश ने आत्महत्या कर ली। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। (जासं)

दंतेवाड़ा में आठ लाख का इनामी नक्सली मारा गया

नईदुनिया, दंतेवाड़ा

▸ हार्ट अटैक से डीआरजी जवान की मौत, एक जवान घायल

▸ पुलिस पर हमले की वारदात में शामिल रहा था मारा गया नक्सली

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार को कटेकल्याण थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में जवानों ने आठ लाख रुपये के इनामी नक्सली को मार गिराया। इस दौरान डिस्ट्रिक रिजर्व गार्ड के जवान कैलाश नेताम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जबकि जवान कवासी उरसुराम घायल हो गए हैं। मुठभेड़ स्थल से पिस्टल, कारतूस सहित बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है।

एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि कटेकल्याण थाना क्षेत्र के तुमकपाल और डब्बा इलाके में मंगलवार सुबह करीब आठ बजे सर्चिंग पर निकले डीआरजी के जवानों पर घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ चालू हो गई। इस दौरान एख वर्दीधारी नक्सली को मार गिराया गया, जबकि अन्य भाग निकले। मारे गए नक्सली की शिनाख्त नक्सलियों के कटेकल्याण एरिया कमेटी प्लाटून नंबर 26 के डिप्टी कमांडर देवा कवासी के रूप में हुई है, जो पुलिस पर हमले की कई वारदातों में शामिल रहा।

सुकमा में भी हुई मुठभेड़

सुकमा जिले के बुर्कापाल कैंप के पास भी सोमवार की शाम को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कुछ देर बाद नक्सली भाग गए। मंगलवार की सुबह मौके से नक्सलियों की दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई है।

बड़ी वारदात की फिराक में थे नक्सली: एसपी डॉ.पल्लव के अनुसार नक्सली बड़ी वारदात की फिराक में कटेकल्याण के जंगल से होकर दरभा-झीरम की ओर जा रहे थे। इस इनपुट के आधार पर सोमवार रात ही 25-30 जवानों की 20 टीमें जंगल में घुसी थीं। डीजारजी ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। डीआरजी में महिलाएं भी थीं।

बच्चा चोरी और हत्या के शक में महिला को जिंदा जलाया

जागरण, संवाददाता, अररिया : बिहार के अररिया जिला स्थित भोडहा पंचायत वार्ड नंबर एक बेलगाछी में सोमवार देर नौ महीने का एक बच्चा लापता हो गया।

काफी खोजबीन के बाद मंगलवार सुबह पांच बजे उसका शव पुआल के ढेर में मिला। इससे आक्रोशित परिजनों ने एक महिला को शक के आधार पर जिंदा जला दिया। पुलिस ने मृत बालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात बेलगाछी गांव में सुबोध चौहान का 9 महीने का बेटा प्रभात कुमार लापता हो गया। काफी खोजबीन करने के बाद मंगलवार सुबह पांच बजे धान के पुआल के ढेर में बच्चे का शव मिला। इसकी सूचना मिलने पर मृत बच्चे के परिजनों ने मिलकर संजीत चौहान की पत्नी सजनी देवी को बच्चा चोरी कर मारने के शक में सुबह छह बजे जिंदा जला दिया।

बताया जाता है कि मृत महिला और मृत बालक के पिता सुबोध चौहान में अवैध संबंध था। इसकी कई बार सामाजिक पंचायत भी हुई थी। वहीं, मामले को लेकर रानीगंज पुलिस छानबीन में जुट गई है।

जम्मू-कश्मीर में मोबाइल सेवा बहाली व नजरबंद नेताओं की रिहाई पर विचार

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▸ हालात और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर होगा फैसला

▸ इस महीने के अंत से शुरू हो सकती है नेताओं की रिहाई

कश्मीर में पर्यटकों के लिए जारी एडवाइजरी वापस लेने के बाद राज्य सरकार ने मोबाइल फोन सेवा बहाल करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही एहतियातन हिरासत में लिए गए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की रिहाई भी चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। कुछ नेताओं की रिहाई की प्रक्रिया इसी माह के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। यह कदम हालात में सुधार और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर उठाए जाएंगे।

राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पर्यटकों के लिए एडवाइजरी हटाने का फैसला सुरक्षा एजेंसियों के फीडबैक के आधार पर लिया गया है। एडवाइजरी हटाने के फैसले से पूर्व प्रशासन की टूरिस्ट एंड ट्रैवल ट्रेड से संबंधित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुई है। बैठक में मोबाइल सेवा को बहाल करने का मुद्दा भी उठा था। राज्य प्रशासन के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोबाइल सेवाओं की बहाली के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। हिरासत में लिए गए राजनीतिक दलों के नेताओं की चरणबद्ध रिहाई की योजना भी विचाराधीन है। राज्य सरकार और नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ रणनीतिकारों का मानना है कि वादी में जनजीवन को पूरी तरह बहाल करने के लिए राजनीतिक गतिविधियों का जमीनी स्तर पर नजर आना जरूरी है।

फील्ड एजेंसियों ने तलब की नेताओं की रिपोर्ट : अधिकारी ने बताया कि सभी नेताओं के अलावा विभिन्न शहरों और कस्बों में सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रोफाइलिंग पर आधारित रिपोर्ट फील्ड एजेंसियों से तलब की गई है। इसके आधार पर राजनीतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को उनके संगठन और प्रभाव के आधार पर अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत कर उनकी रिहाई होगी। निचले स्तर के कई कार्यकर्ताओं को कुछ दिनों में रिहा कर दिया जाएगा।

एक महीने बाद होगा बड़े नेताओं की रिहाई पर फैसला : डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती व सज्जाद गनी लोन जैसे नेताओं की रिहाई पर कोई भी फैसला लगभग एक माह बाद ही लिया जाएगा। जुनैद अजीम मटटु, शेख इमरान, डॉ. शाह फैसल, नईम अख्तर, अली मोहम्मद सागर, सलमान सागर, सरताज मदनी व गुलाम नबी हंजूरा जैसे नेताओं की रिहाई की प्रक्रिया इसी माह के अंत में शुरू होने की उम्मीद है।

घर बात नहीं होगी तो क्यों रुकेंगे पर्यटक : राज्यपाल के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि हालात में सुधार के आधार पर जनजीवन को बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लैंडलाइन सेवाओं को बीते माह ही बहाल कर दिया गया था। अब ट्रैवल एडवाइजरी हटाई गई है। मोबाइल सेवाओं पर भी पाबंदी को जल्द हटाया जाएगा। कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शेख आशिक अहमद ने कहा कि अगर पर्यटक अपने परिवार से संवाद नहीं कर पाएंगे तो यहां क्यों रुकेंगे। ऐसे में एडवाइजरी वापस लेने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

कश्मीर में आज खुलेंगे सभी शिक्षण संस्थान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▸ मंडलायुक्त ने कहा, बीते सप्ताह कुछ कॉलेज खुले हैं, जो बचे हैं वह आज खुलेंगे

▸ विजयादशमी के मौके पर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहे

कश्मीर में बुधवार को सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया जाएगा। वहीं, मंगलवार को श्रीनगर के अलावा अन्य सभी शहरों और कस्बों में सुबह-शाम दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर दिनभर वाहनों की आवाजाही रही, लेकिन सार्वजनिक वाहन नदारद रहे। सरकारी कार्यालय, बैंक और प्राइमरी से दसवीं कक्षा तक सभी स्कूल सरकारी अवकाश के चलते बंद रहे।

मंडलायुक्त बशीर अहमद खान ने बताया कि वादी में हालात पहले से ज्यादा बेहतर हैं। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। इसलिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निर्देशानुसार कश्मीर में पर्यटकों के लिए एडवाइजरी को वापस लिया गया है। बुधवार को सभी शिक्षण संस्थान चाहे वह कॉलेज हों या विश्वविद्यालय, अगर नहीं खुले हैं तो उन्हें भी सामान्य अकादमिक गतिविधियों के लिए खोल दिया जाएगा। बीते सप्ताह कुछ कॉलेज खुले हैं। इसलिए जो बचे हैं, वह खुल जाएंगे।

इस बीच मंगलवार को श्रीनगर समेत पूरी वादी में दिनभर सभी प्रमुख बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। यह सिर्फ सुबह साढ़े सात बजे से 11 बजे और फिर शाम चार बजे के बाद खुले। हालांकि रेहड़ी-फड़ी और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले दिनभर विभिन्न इलाकों में नजर आए। विजयादशमी के मौके पर आतंकियों द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। कुछ जगहों पर शरारती तत्वों ने हंगामा करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति पर काबू पा लिया। कुल मिलाकर वादी में स्थिति शांत रही।

कश्मीर में सेब की न्यूनतम दरों में बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर में सेब उत्पादकों के आग्रह पर राज्य सरकार ने मंगलवार को सेब के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी कर दी है। डलिशियस किस्म के ए-ग्रेड के सेब का न्यूनतम मूल्य 60 और अमेरिकन सी ग्रेड सेब का न्यूनतम मूल्य 17 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। इस बीच, राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फेडरेशन (नैफेड) के अध्यक्ष डॉ. बिजेंद्र सिंह ने मंगलवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले से हताश आतंकियों ने सेब उत्पादकों को अपनी फसल देश की विभिन्न मंडियों में भेजने से मना किया हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय गृहमंत्रालय के निर्देशानुसार नैफेड ने कश्मीर में सेब खरीद की प्रक्रिया शुरू की। यह पहला मौका है जब नैफेड सेब खरीद रहा है। नैफेड ने राज्य बागवानी विभाग और अन्य फील्ड एजेंसियों के जरिए वादी में सेब उत्पादन और पिछले सालों में किसानों को मिली कीमत का आकलन करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया। 12 सितंबर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने नैफेड की सेब खरीद मंडियों को शुरू किया था। स्थानीय सेब उत्पादकों और व्यापारियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्यों को कम बताते हुए इनमें बढ़ोतरी का आग्रह किया था।

अमेरिकी संसदीय समिति ने किया कश्मीर में संचार प्रतिबंध हटाने का आग्रह

वाशिंगटन, प्रेट्र : कश्मीर में संचार प्रतिबंध के चलते वहां रहने वाले लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह बात एक शक्तिशाली अमेरिकी संसदीय समिति ने कही है। समिति ने भारत से प्रतिबंधों को हटाने का आग्रह किया है। बता दें कि पांच अगस्त को अनुच्छेद-370 खत्म करने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने की घोषणा के बाद कश्मीर में सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। प्रतिबंधों को दो महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा और कुपवाड़ा क्षेत्रों को छोड़कर कश्मीर में मोबाइल सेवाएं ठप हैं, वहीं घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं।

संसद की विदेश मामलों की समिति ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा, 'कश्मीर में भारत द्वारा संचार प्रतिबंध से कश्मीरियों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है।' समिति ने भारत से आग्रह किया है कि वह इन प्रतिबंधों को खत्म करें और किसी अन्य भारतीय नागरिक के समान कश्मीरियों को अधिकार प्रदान करे। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल सहित 13 सांसदों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कश्मीर में संचार प्रतिबंध खत्म करने का आग्रह किया है।

शाह ने जम्मू-कश्मीर के भाजपा नेताओं से ली हालात की जानकारी

▸ बीडीसी चुनावों के तैयारियों की समीक्षा भी की

नई दिल्ली, एएनआइ : मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर प्रदेश के जमीनी हालात की जानकारी ली। अनुच्छेद-370 को खत्म करने की घोषणा के दो महीने से अधिक समय बाद होने वाली इस बैठक का आयोजन घाटी में जमीनी हालात का जायजा लेने और 24 अक्टूबर को होने वाले बीडीसी चुनाव से पहले की तैयारियों पर चर्चा के लिए किया गया था। बैठक में जम्मू-कश्मीर इकाई के कई प्रमुख नेता उपस्थित थे।

बैठक में शाह ने प्रदेश भाजपा नेताओं को घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक शाह ने नेताओं से क्षेत्र में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के लिए प्रशासन का सहयोग करने के लिए कहा है।

शाह का कहना था कि सरकारी कर्मचारियों को तुरंत काम पर वापस लाया जाना चाहिए। 90 फीसद बीडीसी सीट पर जीत की उम्मीद के साथ शाह ने पार्टी नेताओं को पंच और सरपंच को चुनावों में अधिक महत्व देने के लिए कहा है।

अमित शाह। फाइल

नेताओं को मौलवी, व्यापारियों से संपर्क करने को कहा: कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली के प्रयास के तहत अमित शाह ने भाजपा नेताओं को घाटी के प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं को मौलवी, व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों से संपर्क स्थापित करने को कहा गया है। इसके तहत, नेता घाटी के सिविल सोसाइटी के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों, धार्मिक और सामाजिक से जुड़ी हस्तियों से संपर्क करेंगे।

समझ रहे हकीकत

अनुच्छेद 370 के समाप्त होते ही खत्म हो गई ऑटोनामी व सेल्फ रूल की सियासत

370 पर नेशनल कांफ्रेंस चुप, नरम रुख का संकेत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के साथ बदली राजनीतिक परिस्थितियों में नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) को भी शायद ऑटोनामी के नारे के आप्रसंगिक होने की हकीकत समझ आ गई है। इसके अलावा 370 पर पार्टी की चुप्पी उनके नरम रुख का संकेत दे रही है। हालांकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) का शीर्ष नेतृत्व अभी भी हकीकत को समझने को तैयार नजर नहीं आता। यही वजह है कि पीडीपी अभी भी सियासी तौर पर निष्क्रिय है।

अनुच्छेद 370 से आजादी के साथ ही राज्य में ऑटोनामी और सेल्फ रूल जैसे नारों की सियासत खत्म हो गई। तब से नेकां, पीडीपी, कांग्रेस, पीपुल्स कांफ्रेंस समेत कई दलों के प्रमुख नेता व कार्यकर्ता हिरासत या नजरबंदी में हैं। राज्य के तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी हिरासत में हैं।

कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र के फैसले पर नेकां और पीडीपी की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया होगी, लेकिन बीते दो माह के दौरान ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। यह बात अलग है कि नेकां के सांसदों ने केंद्र के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर की, लेकिन वह भी लोगों को इस मुद्दे पर कहीं खड़ा नहीं कर पाए। यही कारण है कि नेकां ने मौजूदा परिस्थितियों में अपना रवैया बदलने का संकेत देना शुरू कर दिया है।

नेकां की रणनीति में बदलाव का अंदाजा गत रविवार को पार्टी नेताओं की डॉ. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात से हो जाता है। इस मुलाकात के बाद नेकां नेताओं ने कहीं भी अनुच्छेद 370 को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि नेकां नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन चलाने का जरूरत संकेत दिया। यह पहला मौका नहीं है जब नेकां ने ऑटोनामी के नारे को छोड़ने का संकेत दिया है। इससे पूर्व अगस्त माह के दौरान भी नेकां के एक वरिष्ठ नेता जो सेंट्रल में बंद हैं, ने दावा किया था कि फारूक अब्दुल्ला फिलहाल सभी को स्टेटहुड के लिए आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा है।

कश्मीर में छह अक्टूबर को जब नेशनल कांफ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और फारूक अब्दुल्ला की पत्नी मौली अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंची तो कुछ इस तरह नजर आए थे फारूक। फाइल

पीडीपी के सियासी एजेंडे में बदलाव नहीं

पीडीपी की तरफ से अपने सियासी एजेंडे में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने पार्टी नेताओं के एक दल के साथ मुलाकात को टाल दिया। पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि महबूबा मुफ्ती केंद्र के फैसले से परेशान व रुष्ट हैं। वह नहीं चाहती कि पार्टी नेताओं से मुलाकात को लेकर केंद्र को किसी तरह की बयानबाजी का मौका मिले।

कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार आसिफ कुरैशी ने कहा कि नेकां ने ऑटोनामी का नारा छोड़ा है या कुछ दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाला है। यह अभी तय नहीं है, लेकिन वह कश्मीर में पहले हालात सामान्य बनाने के लिए जरूर अपने रवैये में नरमी ला सकती है। इसलिए वह स्टेटहुड के लिए बात कर रही है। पहले वह बदले हालात में अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाएगी और उसके बाद ही अगला कदम उठाएगी।

बीडीसी चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की आज अंतिम तिथि

राज्य ब्यूरो, जम्मू : ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल (बीडीसी) चुनाव के चलते बुधवार को नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन खंड विकास कार्यालयों में गहमागहमी रहेगी। चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस व पैंथर्स पार्टी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कश्मीर केंद्रित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी व नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व के श्रीनगर में नजरबंद होने के कारण इन पार्टियों का बीडीसी चुनाव का बहिष्कार करना लगभग तय है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में 73वां संशोधन प्रभावी बनाए बिना बीडीसी चुनाव करवाने के फैसले से नाराज जम्मू कश्मीर पंचायत कांफ्रेंस ने भी चुनाव में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।

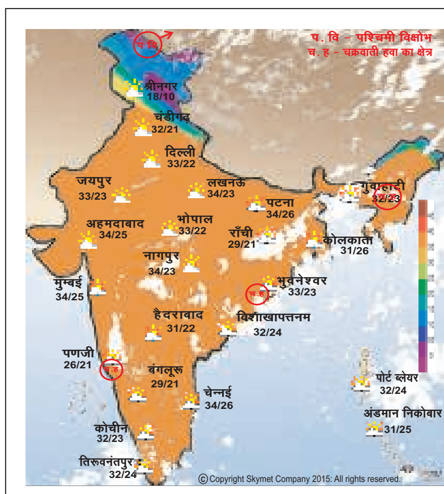

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में सुबह शीतल व सुहावनी रहेगी। आंशिक बादलों के साथ दिन हल्का गर्म व आरामदायक रहेगा। एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में सुहावनी सुबह में धुंध रहेगी। छिटपुट बादलों के व हल्की हवाओं के साथ दिन गर्म बना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	33/25/व	अहमदाबाद	35/26/व
कोलकाता	32/25/आंबा	बड़ौदा	34/26/आंबा
चेन्नई	34/25/आंबा	नागपुर	35/24/आंबा
हैदराबाद	29/21/आंबा	इन्दौर	31/22/आंबा
बंगलूरु	28/20/आंबा	राँची	29/21/व
त्रिवेन्द्रम	33/25/आंबा	पटना	32/24/आंबा
गुवाहाटी	29/21/आंबा	जमशेदपुर	31/23/आंबा
गंगटोक	14/01/व	पुणे	29/22/व

दैनिक जागरण

अवसर कई बार चुनौती के रूप में भी दस्तक देता है

चीन की चाहत

चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के ठीक पहले चीन की ओर से यह कहा जाना उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद को कश्मीर मसले का समाधान आपसी बातचीत के जरिये करना चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह वही चीन है जो कुछ समय पहले तक इस मामले में पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर चीन ने न केवल आपत्ति जताई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसके लिए बाध्य किया कि वह इसका संज्ञान ले। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर मसले पर चीन की ओर से पाकिस्तान की जैसी खुली तरफदारी की गई उससे भारत में खटास ही पैदा हुई। यह कहना कठिन है कि चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा इस खटास को कम करने का काम कर सकेगी, क्योंकि चीन अपने प्रति जैसे व्यवहार की अपेक्षा रख रहा है वैसे व्यवहार का परिचय देने से इन्कार कर रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपनी निराधार आपत्तियों से तो भारत को परेशान करता ही है, इस सवाल का जवाब देने से भी इन्कार करता है कि आखिर उसकी ओर से गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत भारतीय भू-भाग में आर्थिक गलियारे का निर्माण किस हैसियत से कर रहा है?

चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ मसलों पर सहमति कायम हो सकती है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। जरूरत इस बात की है कि सहमति के इस दायरे को बढ़ाया जाए। इसी के साथ आपसी भरोसे की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की भी जरूरत है। भरोसे की इस कमी को दूर करने में एक बड़ी बाधा सीमा विवाद पर न के बराबर प्रगति होना है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बातचीत का सिलसिला जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचने के कारण यह लगने लगा है कि चीन इस विवाद के समाधान का इच्छुक ही नहीं। सच्चाई जो भी हो, चीन को यह समझना होगा कि भारतीय हितों की अनदेखी करके आपसी संबंधों को मजबूती नहीं दी जा सकती। यह सही है कि भारत और चीन के बीच असहमति वाले विभिन्न मसलों का समाधान रातोंरात नहीं हो सकता, लेकिन अगर बीजिंग इस्लामाबाद को भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा तो फिर नई दिल्ली को दूसरे समीकरणों पर विचार करना ही होगा। चीन एशिया में अपनी ही चलाना चाहेगा तो मुश्किल होगी ही। यदि चीनी नेतृत्व सचमुच भारत से संबंधों में सुधार चाहता है तो उसे भारतीय हितों की अनदेखी करने वाले अपने रवैये का परित्याग करना ही होगा। उसे यह समझ आए तो बेहतर कि दोनों देश मिलकर साथ-साथ तरक्की कर सकते हैं।

कुम्हलाती उम्मीद

लंबे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आए उत्तराखंड में उम्मीद थी कि अपनों के राज में वे समस्याएं हल हो जाएंगी, जिनके लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश में एड़ियां रगड़नी पड़ती थीं। अलग प्रदेश के रूप में 19 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन ये उम्मीदें अब कुम्हलाने लगी हैं। इसका एक प्रमुख कारण है सिस्टम की संवेदनहीनता। आलम यह है कि जिस प्रदेश में नौकरशाही को लेकर सरकार के मंत्री तक परेशान हों, वहां आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी समझा जा सकता है। सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, हर दौर में नौकरशाही के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। विधायक से लेकर मंत्री तक यह कहते सुने जा सकते हैं कि अफसर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही एक प्रकरण है सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन में संशोधन का। दरअसल जो लोग एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन सातवें वेतनमान के अनुरूप संशोधित होनी है। प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या करीब एक लाख है। इनको एक जनवरी 2016 से बढ़ी हुई पेंशन मिलनी है। इसके तहत नवंबर 2018 से संशोधित पेंशन का एरियर दिया जाना है। हालत यह है कि एरियर की छोड़िए, अभी 35 फीसद कार्मिकों की पेंशन सातवें वेतनमान के अनुसार संशोधित तक नहीं की जा सकी है। इनमें से कई लोग उम्र के अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं और बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में भी असमर्थ हैं। अब जरा सिस्टम की बात करते हैं। आलम यह है कि इस मामले की जिम्मेदारी न तो संबंधित विभाग ही लेने को तैयार हैं और न ही कोषागार कार्यालय। इन बुजुर्गों का कहना है कि जब वे अपने उस विभाग में जाते हैं, जहां उन्होंने सेवा में अपनी जिंदगी के बहुमूल्य वर्ष बिताए, वहां से उन्हें जवाब मिलता है कि फाइल कोषागार को भेज दी गई है। वहीं कोषागार में कहा जा रहा है कि अपने विभाग से संपर्क करो। यह हाल तब है जबकि पेंशन संशोधन के संबंध में जारी शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख कि पेंशन पुनरीक्षण की कार्रवाई के लिए पेंशनरों से किसी प्रकार संपर्क नहीं किया जाएगा। यानी उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। साफ है कि अफसरों को शासनादेश की भी परवाह नहीं है। सवाल यह भी है कि कर्मचारी संगठन तो सरकार और शासन पर दबाव बनाकर अपनी मांगें मनवा ही लेते हैं, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिस्टम की खामियों का दंश रिटायर्ड कर्मचारियों को क्यों झेलना पड़ रहा है?

आर्थिक सुस्ती तोड़ने का सही उपाय

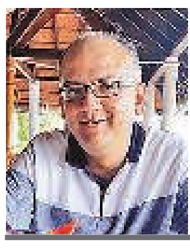

विवेक कौल

अगर सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर में कटौती के बजाय व्यक्तिगत आयकर में कटौती की होती तो बचत सीधे उपभोक्ता के हाथ में आती और अर्थव्यवस्था को ज्यादा लाभ मिलता

अब यह मानने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि देश आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने पिछले महीने कहा था कि निवेश आर्थिक विकास और उपभोग का प्रमुख संचालक है। यहां तर्क सीधा है। निवेश से रोजगार सृजित होते हैं। ये नौकरियां लोगों को आय प्रदान करती हैं। लोग इस पैसे को खर्च करते हैं और यह उपभोग को बढ़ावा देता है। इससे अन्य लोगों को भी आय अर्जित करने में मदद मिलती है। ये लोग भी पैसा खर्च करके खपत के लिए एक और विकल्प प्रदान करते हैं। इस तरह से यह पूरा चक्र काम करते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। समस्या यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम निवेश हो रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा बताता है कि अप्रैल से जून 2019 की अवधि के दौरान घोषित नई परियोजनाओं का स्तर 15 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया। अगर जुलाई से सितंबर 2019 के बीच के आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति में थोड़ा सा सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन यह न के बराबर यानी नाकाफी ही कहा जाएगा।

वर्ष 2007-2008 में 35.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, पिछले चार वर्षों से निवेश एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात (निवेश-जीडीपी अनुपात) 28-29 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। निवेश में ऐसी सुस्ती को देखते हुए आय पहले की तरह नहीं बढ़ रही है। यदि हम 2004 और 2014 के बीच प्रति व्यक्ति आय देखें तो यह प्रत्येक वर्ष में दो अंकों में बढ़ी थी। वर्ष 2016-2017 को छोड़कर इसकी वृद्धि एकल अंक में सिमट गई है। इस दौरान केवल 2016-2017 में ही प्रति व्यक्ति आय 10.2 प्रतिशत बढ़ी थी। यदि हम पुरुषों के लिए ग्रामीण मजदूरी के बढ़ने की दर को देखें तो यह 2008-2009 और 2014-2015 के बीच बड़े पैमाने पर उछली थी। 2013-2014 में मजदूरी दर में तकरीबन 28 फीसद तेजी आई। तब से इसमें बढ़ोतरी एकल अंक में रह गई है। वर्ष 2018-19 में यह केवल 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह दर केवल निवेश की कमी से ही नहीं गिरी है। जब महिला श्रमिकों की बात आती है तो 2008-2009 और 2014-2015 के बीच ग्रामीण मजदूरी में भारी वृद्धि हुई। 2013-2014 में मजदूरी 25.3 प्रतिशत बढ़ी थी। तब से 2018-2019 के दौरान मजदूरी दर में बढ़ोतरी एकल अंक में हुई है। वर्ष 2018-2019 में मजदूरी में वृद्धि महज छह प्रतिशत रही थी। यह कम खाद्य मुद्रास्फीति का दूसरा पक्ष है। आखिर इस स्थिति से बाहर निकलने का क्या तरीका है?

इसमें संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक निवेश की आवश्यकता है, मगर समस्या यह है कारोबारी तभी निवेश करते हैं जब उन्हें मुनाफे की उम्मीद दिखती है। फिलहाल पस्त पड़ी उपभोक्ता मांग के चलते कारोबारियों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इसके अलावा भारतीय कारोबारी अभी भी अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस परिदृश्य में उनके निवेश और विस्तार करने की संभावना कम है। कई कारोबारी कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए और अधिक कर्ज लेकर निवेश और विस्तार करना फिलहाल उनके बस की बात नहीं दिखती। निवेश को प्रोत्साहित करना जरूरी है, मगर हाल-फिलहाल यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता मांग को कैसे पटरी पर लाया जाए? जब तक उपभोक्ता मांग में वृद्धि नहीं होगी तब तक अधिकांश निजी कंपनियां निवेश करने से हिचकती रहेंगी। इसलिए अगर सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर में कटौती के बजाय व्यक्तिगत आयकर में कटौती की होती तो जरूर कुछ बात बनती।

कॉरपोरेट करों में कटौती के समर्थन में एक तर्क यह दिया गया कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां कीमतों में कटौती करेंगी। चलिए इस विकल्प की तुलना व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प से करते हैं। यदि व्यक्तिगत आयकर में कटौती होती तो बचत सीधे उपभोक्ता के हाथों में जाती और फिर वे यह तय कर सकते कि इसके साथ क्या करना है? मसलन इसे खर्च करना है या बचाना है? कॉरपोरेट कर कटौती के मामले में यह तय नहीं है कि कंपनियां अपने सामान या सेवाओं की कीमत में कटौती करेंगी या नहीं? चूंकि उपभोक्ता अपने खर्च का निर्णय करने के लिए कंपनियों के अगले कदम पर निर्भर हैं, इसलिए यह देखना होगा कि उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है।

अवधेश राजपूत

निःसंदेह वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सरलीकरण भी उपभोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे खासतौर से छोटे कारोबारियों को भी बहुत मदद मिलेगी। यह भी मशविरा दिया जा रहा है कि सरकार को ही अपना खर्च बढ़ाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में फिलहाल यह सलाह कैसे लागू हो सकती है, इस पर भी गौर करते हैं। 2017-2018 और 2018-2019 में कुल सरकारी व्यय क्रमशः 15 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत रहा। यह आंकड़ा मुद्रास्फीति समायोजन के साथ है। इसी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी। यदि हम अप्रैल और जून 2019 के बीच देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई, निजी उपभोग व्यय में केवल 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सरकारी व्यय में 8.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ। स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी व्यय ने ही विकास को गति दी है यानी आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार पहले ही बहुत पैसा खर्च कर रही है।

अगर सरकार और भी ज्यादा खर्च करती है तो उसे और अधिक उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि कर संग्रह के मोर्चे पर तस्वीर बहुत अच्छी नहीं लग रही है। अप्रैल और अगस्त 2019 के बीच सकल कर राजस्व में केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने बजट में जितने खर्च के लिए प्रावधान किया है उसकी पूर्ति के लिए राजस्व में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अगर सरकार ज्यादा उधार लेगी तो ब्याज दरें भी ऊपर जा सकती हैं। यहां एक तरीका यह हो सकता है कि सरकारी कंपनियों और उनकी जमीनों को तेजी से बेचा जाए और उस पैसे को राष्ट्रीय निवेश कोष में डाला जाए। फिर इसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विस्तार में लगाया जाए। यह सब कहना आसान है, लेकिन इसे मूर्त रूप देना उतना ही मुश्किल। सरकारी कंपनियों के जल्द विनिवेश का अर्थ यथास्थिति को बदलना होगा और इतिहास गवाह है कि सरकारें ऐसा करने से बचती रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी का पहिया इसी गड्ढे में अटका हुआ है। इससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा।

(स्तंभकार अर्थशास्त्री एवं इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक हैं)

response@jagran.com

कृषि संकट के कारण समझें किसान

रामसरन वर्मा

कम पानी वाले इलाकों में यह जरूरी है कि अधिक पानी की मांग करने वाली फसलों से बचा जाए

एक अर्से से फसलों को प्राकृतिक आपदा से बचाने, कृषि लागत घटाकर अधिक उत्पादन करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की बातें हो रही है। इसी क्रम में किसानों को खेती के साथ पशुपालन एवं अन्य स्वरोजगार की सलाह भी दी जा रही है। इस दिशा में सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि खेती की समस्या का निदान किसानों के खेत में ही है। समय आ गया है कि किसान जलवायु विविधिता पर ध्यान दें और पानी की उपलब्धता एवं उसके बचाव को ध्यान में रखकर खेती करें। भारत की जलवायु में जैसी विविधिता है वैसी दुनिया के कुछ ही हिस्सों में देखने को मिलती है। यहां सर्दी, गर्मी और बरसात में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की फसलें होती हैं। बुंदेलखंड जैसे इलाकों को छोड़कर पूरे देश में भू-गर्भ जल स्तर अच्छा है। जहां जमीन ऊंची-नीची है वहां खेतों को समतल करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करके 25 फीसद पानी बचाया जा सकता है। देश के जिन इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है वहां अधिक पानी की मांग करने वाली फसलें उगाना बंद करने की जरूरत है। हरित क्रांति में अग्रणी रहे पंजाब और हरियाणा के किसान लंबे समय से धान की खेती कर रहे हैं। धान को पानी की अधिक जरूरत होती है। अब पंजाब में पानी की कमी होने लगी है। इसलिए पंजाब के किसानों को चाहिए कि वे धान के बजाय मक्का, सोयाबीन उगाएं और बागवानी में पपीता और सब्जी उत्पादन करें। इससे पानी की भी बचत होगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी।

धान के बाद गन्ने की फसल को पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है। पश्चिमी यूपी के किसानों को चाहिए कि वे गन्ने के बजाय फलों और सब्जियों का उत्पादन करें। वे केला, संतरा, किन्नू, आम, अमरूद, तरबूज आदि की भी खेती कर सकते हैं। गन्ने की फसल में भुगतान मिलों में अटक जाता है, मगर केला, टमाटर, आलू सहित अन्य सब्जी एवं बागवानी की फसलों में तुरंत भुगतान मिलता है। सब्जी एवं बागवानी फसलें एक एकड़ में डेढ़ से दो लाख रुपये तक आमदनी कराती हैं। उत्तर भारत के अनेक इलाकों में केले की खेती की जा रही है, फिर भी यहां केले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात से आ रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जलस्तर करीब तीन से चार सौ फिट नीचे है। महाराष्ट्र के जलगांव, सोलापुर एवं नासिक और आंध्र प्रदेश के पुलवेंद्रा, कड़पा, बंग्लौर एवं अनंतपुर से केले के साथ टमाटर की

खेती की जा रही है। बेहतर होगा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के किसान केले की खेती कम करके अनार, पपीता, तरबूज, अंगूर आदि की फसलों का रकबा बढ़ाएं।

खेती में पानी की उपलब्धता के साथ तापमान के स्तर पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। बागवानी एवं सब्जी की फसलों के लिए 10 से 40 डिग्री तापमान बेहतर होता है। बिहार में सब्जी और फल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। इसीलिए यहां केला और लीची का उत्पादन होता है। बंगाल की जलवायु भी सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है। बंगाल के किसान मक्का और दलहनी फसलों की खेती को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में भी पानी कम है इसलिए वहां के किसान मक्का, कपास, अनार, अंगूर और दलहनी फसलों की खेती कर पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं।

किसानों के लिए यह भी जरूरी हो गया है कि वे बदल-बदल कर फसलें उगाएं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और फसलों का उत्पादन भी। यदि किसी किसान के पास चार एकड़ जमीन है तो वह एक एकड़ में गेहूं एवं धान, एक एकड़ में बागवानी की फसल एवं एक एकड़ में सब्जी की खेती करे और शेष एक एकड़ में पशुओं के चारे वाली फसलें उगाए। धान एवं गेहूं से एक एकड़ में 35 हजार, बागवानी से एक लाख, सब्जी की खेती से 80 हजार रुपये तक की आमदनी हो सकती है। पशुपालन करने पर दूध के साथ ही खेत के लिए गोबर की खाद भी मिलेगी। गोबर की खाद से 20 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे न सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी, बल्कि किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी।

बड़े किसान एक से दो एकड़ में जंगल भी लगा सकते हैं। जंगल से आशय इमारती लकड़ी के पौधे लगाने से है। इससे पर्यावरण संरक्षण होगा और हर 15-20 साल में एकमुश्त मोटी रकम भी मिलती रहेगी। फल एवं सब्जी की खेती से गांव में रोजगार देकर पलायन रोका जा सकता है। टमाटर, सेब, केला, अंगूर की खेती में गांवों के खेतिहर मजूदरों को भरपूर काम मिलता है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एक अच्छी योजना है। यदि किसान इसका उपयोग कृषि बागवानी एवं पशुपालन में करें तो बेहतर। छह हजार रुपये में एक किसान एक एकड़ के आठवें भाग में सब्जी की खेती कर सकता है। इससे वह कम से कम 20 हजार रुपये की सब्जी का उत्पादन कर सकता है। यदि वह छह हजार रुपये की बकरी एवं मुर्गी खरीदता है तो एक साल बाद 10 से 15 हजार रुपये तक लाभ कमा सकता है। यह उसके लिए स्वरोजगार का जरिया भी हो जाएगा।

चूंकि खेती में पानी बचाने की चुनौती है इसलिए किसानों को चाहिए कि यदि ऊंची-नीची जमीन समतल न हो सके तो फौव्वारे एवं ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। वर्षा के औसत को देखकर ही फसलों का चुनाव किया जाना चाहिए। जिनके पास ज्यादा जमीन है वे किसान खेत में तालाब खोदकर भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने के साथ ही मछली पालन कर अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। मक्का की फसल पानी बचाने का बेहतर विकल्प है। यह फसल कम पानी एवं कम समय में तैयार होती है। आजकल तो इसका उपयोग पौष्टिक आहार के रूप में भी हो रहा है। दुनिया भर में मक्का की मांग है, क्योंकि मछली एवं मुर्गी का दाना और पशुआहार मक्का से ही बनाए जाते हैं। अमेरिका और चीन में मक्का सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है। धान की फसल बोने वाले किसान मक्का उगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ ही भू-गर्भ जलस्तर को और गिरने से बचा सकते हैं।

(लेखक उन्नत खेती के लिए पद्मश्री से सम्मानित कृषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मंजिल की पहचान

हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉलिंग का संघर्ष पाठकों को जीवन में लाख मुसीबतों के बावजूद सफलता की राह पर डटे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रायः 73 भाषाओं में अनूदित होने वाली विश्वप्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर को प्रिंट रूप में देखने के लिए उनको 12 प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था? अंततः लंदन के एक पब्लिशिंग हाउस द्वारा यह प्रकाशित हुई और 20 अरब डॉलर से भी अधिक राशि की कमाई की।

रॉलिंग का यह कथन काफी प्रेरणादायी है, 'मैं जो नहीं हूं वैसा होना सोचना बंद कर दिया और खुद में विश्वास करना शुरू कर दिया। मैंने केवल अपने जीवन के उन कार्यों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना शुरू कर दिया है जो मेरे लिए मायने रखते हैं।' परंतु दुर्भाग्यवश हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं और यह भी नहीं जान पाते हैं कि हमें जाना कहां है। बिना मंजिल के इल्म के ताउम्र सफर पर चलते रहने में जीवन की कामयाबी की तलाश महज एक मृगमरीचिका है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है, लेकिन उस पहले कदम को रखने के पूर्व अपने गंतव्य को जानना सबसे अहम होता है। इसके अभाव में तमाम जिंदगी सफर में गुजर जाती है, पर मंजिल नहीं मिल पाती है, किंतु सफल होने की कहानी का यही अंतिम पड़ाव नहीं है।

इस सत्य से इन्कार करना आसान नहीं है कि खुद की प्रतिभा को पहचानना जीवन में देखे गए सपनों को साकार करने की दिशा में आधारशिला के निर्माण सरीखा होता है, किंतु महज इससे ही सफलता के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता है। इसके लिए कड़ी मेहनत और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण की सख्त दरकार होती है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जीवन में सफलता एक प्रतिशत प्रेरणा और 99 प्रतिशत पसीने का नतीजा है। अपने जीवन में देखे गए सपनों के साथ जीना-मरना, सोना और जागना सीख लेने वाला शख्स ही बेशुमार उपलब्धियों और सफलता का इतिहास रच पाता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

संचार क्रांति के दौर में सिमटतीं चिट्ठियां

देवेंद्रराज सुथार

डाक का चलन कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है

दुनियाभर में नौ अक्टूबर को डाक सेवाओं की उपयोगिता और संभावनाओं को देखते हुए वैश्विक डाक संघ की ओर से विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों को डाक विभाग के बारे में जानकारी देना है, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच तालमेल बनाना है। आज डाक की उपयोगिता केवल चिट्ठियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके जरिये बैंकिंग, बीमा और निवेश जैसी जरूरी सेवाएं भी आम आदमी को मिल रही हैं। भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सदस्यता लेने वाला प्रथम एशियाई देश था।

भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना एक अक्टूबर, 1854 को लार्ड डलहौजी के काल में हुई। भारतीय डाक सेवा पिछले 165 साल से हिंदुस्तान को दुनियाभर से जोड़े हुए है। एक जुलाई, 1876 को भारत वैश्विक डाक संघ का सदस्य बना। भारत में 1766 में लार्ड क्लाइव ने पहली बार डाक व्यवस्था शुरू की थी। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने तब के कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया था। चिट्ठियों को पोस्ट करते समय उन पर लगाए जाने वाले स्टैंप्स की शुरुआत भी वर्ष 1852 में हुई थी। भारत में वर्तमान डाक पिनकोड नंबर की शुरुआत 15 अगस्त, 1972 को हुई थी। इसके बाद हर गांव और शहर में पोस्ट ऑफिस बनाए गए। बाद में पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों को संभालने के साथ-साथ लोगों के पैसों को जमा करने का काम भी किया जाने लगा। यानी अपनों की चिट्ठियों का अहसास कम हुआ तो डाक विभाग ने लोगों से जुड़ने के लिए कई सुविधाएं ग्राहकों को देनी शुरू कर दी। वह डाकिया जिसका इंतजार कभी महीनों तक हुआ करता था, आज भी वह डाकिया उतनी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। लेकिन आज उसको देखकर खुशी से झूमने वाले कई गुम हो गए हैं।

बदलते दौर में तकनीक के विकास के कारण अब शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपना निजी और महत्वपूर्ण संदेश डाक के माध्यम से पहुंचाना चाहेगा। इसलिए डाक के माध्यम से बधाई, शुभ-कामनाएं पहुंचाने एवं सगे-संबंधियों के हालचाल जानने के लिए लिखी जाने वाली व्यक्तिगत चिट्ठियों का चलन बंद हो गया है। जब मोबाइल से कुछ ही सेकेंड में अपने परिजनों का हाल पता किया जा सकता है तो भला कौन हफ्तों का इंतजार करना चाहेगा। हालांकि भले डाक के माध्यम से निजी पत्रों को भेजने की रुचि कम हुई हो, लेकिन अब भी डाक विभाग पर काम का बोझ कम नहीं हुआ है। रोजाना डाकघरों में सरकारी एवं निजी संस्थाओं की भारी संख्या में डाक पहुंचती है।

निःसंदेह बदलाव सृष्टि का नियम है। नई चीजें आती हैं और पुरानी चीजें चलन से बाहर हो जाती हैं। डाक का चलन कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आवश्यकता है कि डाक विभाग समय-समय पर कुछ सुधारवादी कदम उठाकर अपनी व्यवस्था में फेरबदल करता रहे जिससे कि डाक के प्रति लोगों में विश्वास बना रहे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मर्यादित जीवन का संदेश

परिचय दास ने अपने लेख 'विजयादशमी का विजय-पाठ' के जरिये रामायण और श्रीरामचरितमानस में समाहित कथ्य को मानव-मन के उस संघर्ष से जोड़ा है जो सत्य-असत्य के बीच सतत संघर्षशील रहता है। वस्तुतः श्रीराम का चरित्र जितना वैविध्यपूर्ण है उतना ही विरोधाभासी भी, लेकिन श्रीराम के पावन चरित्र का यह विरोधाभास सात्विकी है। श्रीराम एक भाई का वध करते हैं तो दूसरे को गले लगाते हैं। जिस सीता के लिए रावण जैसी महाशक्ति से टकराते हैं, राजधर्म के लिए उसी का परित्याग कर देते हैं। माता कैकेयी के कपट से अवगत होते हुए भी उनकी इच्छानुरूप चौदह वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार लेते हैं। श्रीराम के जीवन का यह विरोधाभास मनुष्य जीवन के लिए तब भी संदेशप्रद था और आज भी प्रासंगिक है। यदि मनुष्य अपने जीवन के विरोधाभास को सात्विक बनाकर श्रीराम जैसा आचरण करने लगे तो वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है। त्रेता के श्रीराम और द्वापर के श्रीकृष्ण प्रतीक थे मनुष्य जीवन की उस कर्ममयी मर्यादा के जिसमें विरोधाभास तो हैं, लेकिन उनकी प्रकृति सात्विकी है। हर युग में मानवता की रक्षा के लिए रावण, कंस और दुर्योधन जैसी अन्यायी और अहंकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु कोई न कोई राम और कृष्ण बनकर अवतरित होता रहा है। सत्य और असत्य के विरुद्ध यह संघर्ष आज भी जारी है। बाह्य जगत में अमानवीय शक्तियों के साथ और मनुष्य के अंतर्मन में अनियंत्रित इच्छाओं और वासनाओं के साथ। मनुष्य जीवन के अंदर और बाहर के इस संघर्ष में विजयादशमी का विजय-पर्व उस संकल्प शक्ति को जागृत करने वाला है, जिसके लिए श्रीराम ने भी शक्ति की आराधना की थी। श्रीकृष्ण का कर्मयोग और श्रीराम की मर्यादा मनुष्य जीवन को संतुलित बनाती हैं। मर्यादित कर्म जहां जीवन को सुवासित कर दूसरों के लिए सुखदायी बन जाता है वहीं अन्यायी और अनाचारी प्रवृत्तियां अपनी अमानवीयता से दूसरों को दुख देने में आनंद का अनुभव करती हैं। अब मनुष्य जीवन के लिए क्या सार्थक है, यही विजयादशमी का विचारणीय पाठ है।

pandeyvp1960@gmail.com

अच्छाई की होगी जीत

जीवन की अहमियत समझनी हो तो रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और मंदिर-मस्जिद के आसपास भीख मांगते छोटे नौनिहालों को देख सकते हैं। जिन हाथों में स्कूल बैग होने चाहिए उन हाथों में वे भीख का कटोरा लिए घूमते दिख जाएंगे। लाखों की संख्या में ये बच्चे भुखमरी, बीमारी, लाचारी व लोगों की कुदृष्टि का शिकार होते रहते हैं। अनगिनत लड़कियां यौन शोषण का शिकार होती हैं। कौन जिम्मेदार है उनके इस हालात का। क्या सरकार उनके लिए कोई काम नहीं करती। क्या हम सब इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? यक्ष प्रश्न यह है कि कैसे इन्हें इस हालात से बाहर निकाला जाए! समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि इस भीख के धंधे को हतोत्साहित करे। कोई न कोई इसका भी ठेकेदार होगा। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि भीख में इन्हें पैसे देने के बजाय इनकी समस्याओं का समाधान करें। हम इन्हें भोजन दें। इनको शिक्षा का अधिकार दिलाएं। इनको इस हालात से मुक्त कराने का प्रयास करें। भीख मांगना अब मजबूरी नहीं, बल्कि एक व्यवसाय बन चुका है। इसे हम सबको मिलकर बंद कराना होगा। यदि इस व्यवसाय को समाप्त किया जाता है तो अच्छाई की एक जीत यह भी होगी।

अर्पित शुक्ला, नई दिल्ली

रावण जलता क्यों नहीं?

हम हर साल बुराई के प्रतीक हजारों रावण को जलाकर अच्छाई की जीत का जश्न दशहरा खूब धूमधाम से मनाते हैं तो फिर अगले साल ये रावण क्यों और कहां से पैदा हो जाते हैं? यक्ष सवाल बना हुआ है। आखिर इन्हें हर साल फिर से जलाने की जरूरत क्यों आ पड़ती है। हजारों सालों से बुराई का प्रतीक रावण जलकर नष्ट क्यों नहीं होता? बुराई रूपी लाखों रावण अच्छाई से भी बड़े क्यों हो जाते हैं? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए। हर साल ये व्यर्थ के रावण जलाने से हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। जब तक समाज का हर एक व्यक्ति इस बारे में विचार नहीं करेगा, जब तक हम अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र और ईमानदार नहीं होंगे तब तक समाज से रावण रूपी बुराई का संहार संभव नहीं है।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

सोशल मीडिया पर लगाम कितनी जरूरी

बेशक भारत में अब इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की तादाद 40-50 करोड़ तक हो चुकी है, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी काफी शुरुआती स्तर पर ही है। अभी भी लोग इसके इस्तेमाल का तरीका सीख रहे हैं। ऐसे में धर्म, समाज, जाति-समुदाय के कई स्तरों को देखते हुए विभिन्न तबकों के हितों और उनकी संवेदनशीलताओं के बीच होने वाले टकरावों का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया पर नियंत्रण का वह तरीका अपनाना होगा जिसमें सभी की सहमति हो

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था-एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

कानूनन सोशल मीडिया पर कई प्रकार की टीका-टिप्पणियों को साइबर अपराध माना जाता है। ऐसे विचार जो कंप्यूटर-मोबाइल आदि के जरिये इंटरनेट के माध्यम से समाज की समरसता को भंग करें, परस्पर द्वेष पैदा करें, चाइल्ड-पोर्न को बढ़ावा दें, धोखाधड़ी-गबन या किसी की निजता का उल्लंघन करते हों, कानून की परिधि में आते हैं। इसके मद्देनजर गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब सोशल मीडिया जैसे तमाम ऑनलाइन खतरों से बचने के उपाय किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग (दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास), चरित्र हनन, झूठी एवं फर्जी खबरें फैलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई और ऐसा करने वालों की पहचान करने की तकनीक विकसित करने पर जोर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां यह पता नहीं लगा पा रहीं कि किसी ऑनलाइन संदेश (मैसेज) या सामग्री (कंटेंट) का स्रोत क्या है। इसलिए अदालत का विचार है कि सरकार इसमें दखल दे। सुप्रीम कोर्ट ने यह नाराजगी भी प्रकट की कि आखिर सरकार यह क्यों नहीं पूछ सकती कि इंटरनेट पर किसी आपत्तिजनक सामग्री को फैलाने की शुरुआत किसने की।

अदालत का कहना था कि अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी यह कहकर बचने की कोशिश करे कि ऐसी सामग्री की रोकथाम की तकनीक नहीं है तो यह उसका गलत तर्क होगा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सरकार इस मामले में दिशा-निर्देश जारी करे। हालांकि इसमें यह सावधानी बरतने की जरूरत है कि इन इंतजामों से लोगों की निजता के अधिकार, उनका मान-सम्मान और देश की संप्रभुता पर कोई आंच न आने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा, ट्रोलिंग, आतंकवाद, फेक न्यूज, बाल शोषण आदि से जुड़ा है, इसलिए केंद्र सरकार इसकी जल्द व्यवस्था करे जिससे कि फेसबुक, वाट्सएप आदि सोशल मीडिया के मंचों को उन पर मौजूद किसी भी आपत्तिनजक सामग्री के स्रोत की जानकारी देने के लिए बाध्य किया जा सके। अदालत ने ऐसा करने के संदर्भ में सरकार से पूछा है कि वह इस बारे में कब तक दिशा निर्देश बनाएगी। अदालत की चिंता अपनी जगह सही है, पर यहां एक पेचीदा सवाल यह है कि सरकार इस बारे में आखिर कैसी व्यवस्था बना सकती है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया की निगरानी के उद्देश्य से सोशल मीडिया हब बनाने का एक फैसला किया था और कहा था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में जेल एवं जुर्माने आदि की सजाएं होंगी। बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति के लिखे कमेंट या कंटेट से अन्य शख्स को ठेस पहुंचेगी, दंगा-अफवाह या प्रतिकूल हालात की आशंका होगी तो फिर उस कमेंट या कंटेट लिखने वाले को अधिकतम तीन साल की जेल हो सकती है। ऐसी ऑनलाइन सामग्री शेयर, फॉरवर्ड या रीट्वीट करने वालों को भी यही सजा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने अलग से कानून बनाने के बजाय मौजूदा भारतीय दंड संहिता और आइटी एक्ट 2000 की धारा में ही बदलाव का प्रस्ताव दिया था, जो 10 विशेषज्ञों की कमेटी से सरकार को मिली रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। प्रस्ताव था कि आइपीसी 153सी के तहत ही ऑनलाइन हेट या अफवाह फैलाने वाले कंटेंट पर कार्रवाई की जाए। इस धारा के तहत जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी को धमकी या गलत संदेश दिया जाता है तो 3 साल तक जेल हो सकती है। इसी तरह आइपीसी 505ए के तहत अगर किसी आधार पर हिंसा फैलाने वाला कमेंट करने या कंटेंट लिखने पर एक साल जेल या 5 हजार का आर्थिक दंड मिल सकता है। इसके लिए हर राज्य में आइजी स्तर का एक अधिकारी साइबर पुलिस टीम का मुखिया होगा। इस प्रस्ताव पर सवाल उठा और पूछा गया कि इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट धारा 66ए को असंवैधानिक करार दे चुका है तो उन्हीं प्रावधानों को नया जामा पहनाकर दोबारा सामने क्यों लाया गया है। आमजन ही नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी तब टिप्पणी की थी कि ऐसी व्यवस्थाएं देश में 'निगरानी राज' बनाने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और लोगों की प्रतिक्रिया के मद्देनजर पिछले साल ही सरकार ने सोशल मीडिया हब बनाने के प्रस्ताव वाली अधिसूचना वापस ले ली और कहा कि सरकार अपनी सोशल मीडिया नीति की गहन समीक्षा करेगी। लेकिन इधर तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन खतरों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जता दी है।

असल में पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया और मोबाइल इंटरनेट को लेकर पूरा देश और समाज दुविधा में है। लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि इन आधुनिक तकनीकों का कैसे इस्तेमाल करें और किस तरह इन पर नियंत्रण पाया जाए। इसे लेकर दुविधा दो वजहों से है। एक तरफ हमें इंटरनेट और सोशल मीडिया के वाजिब उपयोग नजर आते हैं तो दूसरी तरफ यह भी दिखाई पड़ता है कि कुछ असामाजिक तत्व इन चीजों का गलत इस्तेमाल यानी दुरुपयोग करते हैं। इसकी मिसालें बार-बार मिलती हैं। उपयोग और बेजा इस्तेमाल के ये दो छोर ही इंटरनेट और सोशल मीडिया के नियंत्रण की सरकारी व्यवस्थाओं की मांग उठाते हैं और यह दुविधा पैदा करते हैं कि कहीं ऐसा नियंत्रण अभिव्यक्ति की आजादी के हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन न करने लग जाए तथा ये माध्यम सिर्फ सरकारी भोंपू बनकर न रह जाएं।

यह तो सही है कि हमारा लोकतंत्र इस समय जिस मुकाम पर है, वहां सख्त सरकारी नियंत्रण वाली ऐसी व्यवस्था का पक्ष नहीं लिया जा सकता जो आम नागरिकों के हितों और संवैधानिक शक्तियों का हनन करती हो। ऐसे में उन रास्तों की खोज होती रही है, जिन्हें लेकर दोनों ही पक्षों को कोई आपत्ति न हो। ऐसा एक रास्ता यह है कि सोशल मीडिया कंपनियां खुद ही इससे संबंधित इंतजाम करें और जनता को जागरूक करें। यदि लोग भूलें न हों तो उन्हें याद होगा कि फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी वाट्सएप ने पिछले साथ यह व्यवस्था बनाई थी कि भारत में इसके उपयोगकर्ता (यूजर्स) किसी संदेश, फोटो या वीडियो को एक बार में अधिकतम पांच लोगों को फारवर्ड कर सकते हैं। पांच लोगों को भेजे जाने के बाद उस संदेश से फारवर्ड का विकल्प हट जाएगा। अफवाह आदि रोकने के मामले में इसी किस्म के कुछ और तकनीकी इंतजाम किए जा सकते हैं। जैसे इधर फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में व्यवस्था की है कि फेसबुक पर कोई फोटो या वीडियो पोस्ट करने के बाद उस पर दूसरे लोगों को लाइक्स या रिएक्शन नहीं दिखेंगे। फेसबुक के मुताबिक वह ऐसी व्यवस्था इसलिए कर रहा, ताकि सोशल मीडिया का यह मंच झूठी प्रतियोगिता का मैदान बनने से बच सके।

बेशक भारत में अब मोबाइल इंटरनेट के प्रचार-प्रसार के कारण इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की तादाद 40-50 करोड़ तक हो चुकी है, लेकिन लोगों की शिक्षा और जागरूकता के स्तर को देखते हुए इसके मामले में काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। यह भी समझना होगा कि हमारे देश में सोशल मीडिया जैसी तकनीकों का इस्तेमाल अभी भी काफी शुरुआती स्तर पर है जिसके इस्तेमाल का तरीका लोगों को सीखने की जरूरत है। साथ ही धर्म, समाज, जाति-समुदाय के कई स्तरों को देखते हुए विभिन्न तबकों के हितों और उनकी संवेदनशीलताओं के बीच होने वाले टकरावों का ध्यान रखते हुए सोशल मीडिया के नियंत्रण का वह तरीका बनाना होगा जिसमें सभी की सहमति हो।

अंकुश के लिए इंटरनेट शटडाउन

सवाल है कि आज की तारीख में क्या कोई सरकार आम जनता के लिए इंटरनेट सेवाएं स्थगित रख सकती है, जबकि मौजूदा वक्त में प्राय: हर चीज के लिए हमारा जीवन इंटरनेट पर आश्रित हो गया है। गौरतलब है कि इंटरनेट पर अफवाहों के प्रसार को देखते हुए अगस्त, 2017 में केंद्र सरकार ने टेलीग्राफ एक्ट में एक अध्यादेश से संशोधन कर राज्य और केंद्र सरकार को यह हक प्रदान किया था कि किसी आपात स्थिति में जनता की सुरक्षा के उद्देश्य के साथ अस्थायी तौर पर इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। इससे पहले सरकारें धारा-144 के तहत ही इंटरनेट शटडाउन को जायज ठहराती रहीं। हालांकि आरोप है कि इसका अधिकार मिलने के बाद सरकारों ने इसे राजनीतिक प्रतिरोध का जरिया भी बना लिया है, जिससे हिंसा और तनाव बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है। सही सूचनाएं नहीं मिलने और तानाशाही का रवैया अपनाने से हिंसा और अस्थिरता आदि में और इजाफा हो जाता है। इंटरनेट की बंदिशें सिर्फ आम जनता के लिए नहीं, बल्कि सरकारी विभागों पर भी लागू की जाती रही हैं। कुछ साल पहले पुदुचेरी में मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके सरकारी कामकाज में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और वाट्सएप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया था कि चूंकि इन सभी सोशल मीडिया कंपनियों के सर्वर विदेशों में स्थित हैं, जिससे विदेशी ताकतें कभी भी सरकारी गोपनीय सूचनाओं को भी देख सकती हैं। ऐसे में यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। हालांकि पुदुचेरी की राज्यपाल किरण बेदी ने इसे मुख्यमंत्री का ढोंग बताया था और फैसला निरस्त करते हुए कहा था कि यह निर्णय हमें गैर-तकनीकी युग में ले जाएगा जो आज की जरूरतों के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सरकारी काम में भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर इतनी पाबंदियां उचित हैं। इन सवालों के जवाब मुश्किल हैं, पर ध्यान रखना होगा कि सरकारों का पहला दायित्व देश और जनता के विकास के साथ एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना भी है। ऐसे में यदि कोई कानूनी रास्ता बनाते हुए सोशल मीडिया पर बंदिशें लगाई जाती हैं या पूरी तरह इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो उस कदम का विरोध करने से पहले सोचना होगा कि आखिर इसमें हित किसका है, जनता का या सरकार का।

सोशल मीडिया बनाम 'डिजिटल गुंडा'

सोशल मीडिया को लेकर बेचैनी का माहौल सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया ही इससे परेशान है। इसकी एक मिसाल फरवरी में तब मिली थी, जब ब्रिटिश सांसदों ने 18 महीने की जांच-पड़ताल के बाद सोशल मीडिया पर 'फर्जी खबरें और भ्रामक जानकारियां' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की था। इस रिपोर्ट में सांसदों ने खास तौर से फेसबुक को निशाने पर लेते हुए उस पर ब्रिटेन में जानबूझकर निजता के नियमों और प्रतिस्पर्धा-रोधी कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था और उसे 'डिजिटल गुंडा' तक कहा था। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की संसद में सोशल मीडिया कंपनियों पर ज्यादा निगरानी रखने का आह्वान किया गया था। रिपोर्ट तैयार करने वाली संसदीय समिति ने कहा था कि सोशल मीडिया वेबसाइटों को अनिवार्य रूप से आचार संहिता का पालन करना चाहिए और हानिकारक या अवैध सामग्री को बेहतर तरह से नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक को इनकी निगरानी करनी चाहिए। फेसबुक को लेकर खासतौर पर कहा गया कि ऐसा लगता है कि साइट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खास निर्णयों के लिए ज्ञान और जिम्मेदारी को छिपाया जा सके। कहा गया कि फेसबुक ने जानबूझकर आंकड़ों की निजता (डेटा प्राइवेसी) और प्रतिस्पर्धा-रोधी कानूनों को तोड़ा है। यह उदाहरण साबित करता है कि सोशल मीडिया के नियमन और उस पर अंकुश की कितनी ज्यादा जरूरत है। साफ है कि इसके खतरे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इन्हें संचालित करने वाली कंपनियां अब तक तकनीकी बाध्यताओं का हवाला देकर इनके नियमन से बचती रही हैं।

खरी-खरी

जब घर पर ही आ गया रावण

मनोज लिमये

हमारी कॉलोनी के अघोषित नेता बाटू भिया का ये व्यस्ततम दौर चल रहा है। गणपति स्थापना से इनकी व्यस्तता का शुभारंभ होता है, जो 31 दिसंबर की पाल्टी मनाने के साथ समाप्त होता है। कल भिया की आंख ठीक से लगी भी नहीं थी कि द्वार पर हुई दस्तक से वे उठ बैठे। दरवाजा खोला तो बाहर खड़ी विशाल काया देख वे सहम गए। भय और कौतुहल का कॉकटेल बनाकर भिया ने पूछा-आप कौन? द्वार पर खड़ी रौबदार काया ने भिया को परे हटाते हुए भीतर प्रवेश करते हुए कहा-'मैं रावण हूं।'

रावण! मतलब वो मुरलीधरन और जयसूर्या की लंका वाला या रामलीला की नौटंकी वाला? एक सांस में पूछ बैठे थे भिया। 'अरे मूरख, मैं ओरिजनल वाला हूं। लंका वाला।' आगंतुक ने जोर देकर कहा। भिया ने सहमते हुए पूछा-महाराज आपके आने का कोई विशेष प्रयोजन? रावण बोले पूछने आया हूं कि हर साल मुझे ही क्यों जलाते हो तुम लोग? भिया समुचित नम्रता का प्रदर्शन करते हुए बोले-बुराई का अंत हो इसलिए जलाते हैं। रावण महाराज बोले-जब एक बार दहन कर दिया तो फिर बारंबार क्यों? क्या मेरे अलावा किसी ने कोई पाप नहीं किया? कंस भी तो कम नहीं था। उसे तो सिर्फ मथुरा और शाजापुर में ही प्रतिवर्ष मारते हैं, पर मुझे हर गली, हर प्रदेश में, वह भी प्रति वर्ष! आखिर क्यों?

भिया सोच के सागर में डूबे थे और रावण उवाच जारी था। गांव-शहर सब जगह भ्रष्टाचार, घोटाले, जाति-भाषा के झगड़े और दंगा-फसाद! क्या ये सब राक्षसीय काज नहीं हैं? भिया रावण की भारी भरकम गदा को हाथ लगाते हुए बोले-महाराज सुना और देखा था कि आपके दस सिर होते हैं, लेकिन अभी तो एक ही! रावण तनिक क्रोधित होते हुए बोले-'निपट मूरख, मेरे दस सिर तो मेरी विद्वता हेतु थे। आज तुम्हारे समाज में तो लोग दस से भी अधिक मुखौटे लगाकर विचरण कर रहे हैं। मुखौटे के पीछे कितने खोटे लोग हैं, क्या तुम्हें नहीं पता?'

बाटू भिया ऐसे स्तब्ध थे, जैसे उनका चुनाव टिकट ऐन वक्त पर कट गया हो। उनका सिर रावण के समक्ष झुक गया। रावण ने भिया की विनम्रता देखकर क्षमा कर दिया। इत्ता हुआ ही था कि बाटू भिया की नींद खुल गई। मगर उनको सपने और सच में अंतर नहीं मिल रहा था।

ट्वीट-ट्वीट

पाकिस्तानी मित्रों क्या आप कुछ शांत रहोगे? राफेल एक लड़ाकू विमान है। यह सामान्य खरीद है। और यह जंग की शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश के लिए है कि कभी किसी जंग की जरूरत ही न हो। आपको भी नए लड़ाकू विमान मिलेंगे। शांति रखें।
शिव अरूर@ShivAroor

नुसरत जहां को दुर्गा पूजा पर अपना ज्ञान देने वाले उलेमा कुछ दिन दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया में रहकर आएं। धर्म और संस्कृति को कैसे साथ लेकर चलते हैं, रामलीला का मंचन करते मुसलमान इन कट्टरपंथियों को समझाएंगे।
रूबिका लियाकत@RubikaLiyaquat

आरे में पेड़ कटाई रोकने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको खुश रखने जैसा है। जितने जरूरी थे उतने पेड़ काटे जा चुके हैं और प्रदर्शनकारी भी जानते हैं कि मेट्रो से प्रदूषण कम होगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद यह मुद्दा भी वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे आम चुनाव के बाद तथाकथित राफेल घोटाला।
प्रदीप भंडारी@pradip103

राजनीति का रुख गांवों की ओर

कुशल कोठियाल
राज्य संपादक, उत्तराखंड

उत्तराखंड डायरी

उत्तराखंड एक बार फिर चुनावी रंगत में है। पंचायत चुनाव होने के कारण सियासी अड्डे शहरों से फौरी तौर पर चौपालों और खलिहानों में शिफ्ट हो गए हैं। बड़े आका और मंत्री-विधायक भी अपने-अपने प्रभाव वाले ग्रामीण क्षेत्रों में अपनों को जिताने में लगे हैं। भाजपा जहां जीत का सिलसिला कायम रखने को प्रयासरत है, वहीं कांग्रेस अपनी मौजूदगी के निशान दर्ज कराने को हाथपांव मार रही है। भाजपा इस चुनाव में भी बागियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस ओर से रणनीति के तहत आंख फेरी हुई है। कुल मिलाकर यह कि अधिकृत प्रत्याशी जीते या हारे, जाएगा तो कांग्रेस के ही खाते में। जो जीता वही अपना, कांग्रेसी की इस चाल को मात देने के लिए सत्ताधारी भाजपा भी जाल बिछाए हुए है। क्षेत्रीय विकास चाहने वाले हर प्रत्याशी का भाजपा में स्वागत होगा, यह चारा अभी से पंचायत क्षेत्रों में फेंका जाने लगा है। राजनीतिक परंपरा के अनुसार भी उत्तराखंड में स्वतंत्र रूप से जीतने वाले पंचायत के प्रतिनिधियों का रुख स्वाभाविक रूप से सत्ताधारी दल की ओर रहा है। कांग्रेस के नेताओं का तो यह भी कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का चार दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के निहितार्थ भी पंचायत चुनाव में छिपे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय रहे भगतदा की सक्रियता भी कांग्रेस को बेचैन किए हुए है। भाजपा पंचायत चुनावों में भी मोदी फैक्टर भुनाने की कोशिश में है। उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव पंचायत चुनाव में भाजपा को कितना लाभ दिलाएगा यह तो परिणाम ही बताएंगे, लेकिन पार्टी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि यह भी स्थापित तथ्य है कि पंचायत चुनावों में व्यक्ति की अहमियत पार्टी से ज्यादा रहती है एवं प्रत्याशियों के चयन में भाजपा में कई जगह असंतोष दिखाई दे रहा है।

भाजपा संस्कृति में नहीं हो पाए दीक्षित : कभी सत्ता की सीढ़ी बनते-बनते रह गए कांग्रेस के विधायक अब भाजपा के लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं। सत्तर सदस्यों की विधानसभा में 57 के सुविधाजनक बहुमत में से दस विधायक कांग्रेसी गोत्र के हैं। राज्य के राजनीतिक गलियारों में भाजपा के इस खेमे को कांग्रेस बी टीम भी कहा जाता है। करीब तीन माह पहले इसी जमात में से लक्सर (हरिद्वार) के विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा था। पहले तो भाजपा ने उन्हें आत्मसात करने की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन जब उनके हरकतें तमंचें पर डिस्को तक पहुंच गईं तब पार्टी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस खेमे से देहरादून से निर्वाचित विधायक उमेश शर्मा काऊ भाजपा के लिए राजनीतिक समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। निकाय चुनाव में भी उन्होंने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के बजाय विरोध में उतरे उम्मीदवारों को समर्थन देकर पार्टी संगठन के अंदर माहौल गर्मा दिया था।

अब पंचायत चुनाव में भी वह पार्टी प्रत्याशियों के बजाय अपनों को जिताने में लग गए हैं। संगठन में विरोध के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें भी नोटिस थमा दिया है। विधायक ही नहीं कांग्रेस से टूट कर आए जिन विधायकों को मंत्री बनाया गया है उनमें से तीन मंत्री गाहे-बगाहे अपनी ही सरकार को कठघरे में खड़ा करने से नहीं चूक रहे हैं। अब राजनीति के जानकार भाजपाइयों को समझा रहे हैं कि कांग्रेसियों को तोड़ना आसान है, लेकिन पचाना मुश्किल। भाजपा नेता इसके लिए कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति को जिम्मेदार मान रहे हैं, साथ ही विश्वास भी जता रहे हैं कि कुछ समय में सभी भाजपा की संस्कृति में दीक्षित हो जाएंगे।

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या टेस्ट में रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को एक भरोसेमंद ओपनर मिल गया है?

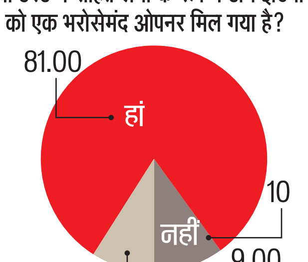

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या स्विस खातों की जानकारी मिलने से काले धन के खिलाफ मुहिम तेज होगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

पूजन कर राफेल का भारत हुआ निहाल,
बंधु दशहरा इस तरह काश मने हर साल।
काश मने हर साल प्राप्त हो शक्ति अपरिमित,
रहे चीन या पाक युद्ध में हों सारे चित।
है भारत कमजोर न रखिए यह कन्फ्यूजन,
हम करते हर साल शक्ति का मन से पूजन!
- ओमप्रकाश तिवारी

मुद्दा

विश्व बाजार में धमक बढ़ाए भारत

हमें ऐसी नीतियां एवं परिदृश्य तैयार करना होगा, जिससे हमारे निर्यातों को बढ़ावा मिले और वैश्विक बाजार में हमारी हिस्सेदारी बढ़े

सुषमा रामचंद्रन
आर्थिक मामलों की जानकार

आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी महज दो फीसद है। यदि भारत अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है तो उसे अपना यह स्तर बढ़ाना ही होगा। गौरतलब है कि ऐसे ज्यादातर देश जिनकी वैश्विक व्यापार में बड़ी भूमिका है, उनकी विकास दर भी उच्च है और वे अपने नागरिकों के लिए रहन-सहन का बेहतर स्तर भी सुनिश्चित करते हैं। चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इसकी मिसाल हैं कि वैश्विक व्यापार में आपकी भूमिका बढ़ने से कैसे आपके समग्र आर्थिक विकास को भी गति मिलती है। चीन की बात करें तो निर्यात इसकी अर्थव्यवस्था का एक अहम घटक है, लेकिन यह अपने इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारी मात्रा में विभिन्न तरह की सामग्रियां आयात भी करता है। वहीं दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की अगर बात की जाए तो उन्होंने न सिर्फ संरक्षणवाद से परहेज किया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी ताकत बनने के लिए क्षेत्रीय व्यापार सहभागिता के जरिये आपसी जुड़ाव भी कायम किया।

यह अच्छी बात है कि भारत में भी यह अहसास बढ़ रहा है कि निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कमर कस लेना चाहिए। हाल ही में निर्यातकों के लिए जो प्रोत्साहक घोषणाएं की गईं और जिस तरह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी 19-20 फीसद निर्यात वृद्धि को पुनः हासिल करने पर जोर दिया, उससे यह संकेत मिलता है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालिया दौर में वैश्विक मंचों पर व्यापार के मसले जिस तरह छाए रहे, उससे भी यही रेखांकित हुआ कि दुनिया के बाजारों में हमें ज्यादा प्रतिस्पर्धी होने की जरूरत है। जहां तक भारत-अमेरिका कारोबार की बात है तो इसमें व्यापार अधिशेष की स्थिति भारत के पक्ष में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिलों पर उच्च आयात शुल्क का हवाला देते हुए इस मुद्दे को उठाया जो बहुत कम संख्या में अमेरिका से आयात की जाती हैं। इसके बाद जब अमेरिका द्वारा भारत समेत कुछ विकासशील देशों को आयात शुल्क में रियायत प्रदान करने वाली जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस (जीएसपी) की सूची से बाहर कर दिया तो बात और बिगड़ गई। इससे भारत भी अनेक अमेरिकी सामानों पर उच्च आयात शुल्क लगाने को प्रेरित हुआ।

लेकिन मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे के बीच ऐसे भी संकेत मिले कि दोनों देशों में व्यापारिक मुद्दों पर मतभेद सुलझाने के लिए सकारात्मक बातचीत जारी है। अब इंतजार इसी बात का है कि दोनों के बीच ये मतभेद कब तक सुलझते हैं। वैसे यदि अमेरिका अपनी जीएसपी प्रणाली के तहत भारत को कुछ फायदा देने के लिए राजी हो जाता है तो बदले में भारत को भी उसे कुछ रियायतें देनी ही होंगी। बहरहाल भले ही भारत-अमेरिका के कारोबारी संबंध उलझे हुए हों, लेकिन भारत एक व्यापक क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) जैसे समूह की ओर कदम बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि आरसीईपी आसियान देशों के साथ-साथ जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों का व्यापारिक समूह है। लेकिन इस समूह के साथ जुड़ने में भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं हमारे बाजार में सस्ते आयातित माल (मुख्यतः चीन के) की बाढ़ न आ जाए। यदि हम इसमें शामिल होते हैं तो आयात शुल्क तो घटाने होंगे, लेकिन ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि यह विभिन्न चरणों में किया जाए, ताकि हमारे घरेलू उद्योग इस प्रतिस्पर्धा के लिहाज से तैयार हो सकें। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वह इस क्षेत्रीय व्यापारिक समूह का सदस्य बने। इससे वह इनके अहम बाजारों तक पहुंच सकता है। यह सही है कि हमारे उद्योग सस्ते आयातित माल के परिदृश्य से जूझ रहे हैं, लेकिन यहां पर यह भी देखना होगा कि भारत अब तक ऐसे किसी बड़े व्यापारिक साझेदारी समूह का हिस्सा नहीं बना है। लिहाजा इसके लिए आरसीईपी में शामिल होना श्रेयस्कर होगा।

कुछ अध्ययन बताते हैं कि भारत जिन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हुआ, उनके साथ भले ही हमारा व्यापार घाटा बढ़ा, लेकिन ऐसे समझौते के बगैर तो आयात और भी महंगे होते। इसके अलावा जब हमारे उद्योग नए बाजारों में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं तो यह भारत के लिए नुकसानदेह होगा कि वह खुद को आरसीईपी जैसे क्षेत्रीय समूहों से दूर रखे। जहां तक भारतीय उद्योग-धंधों के संरक्षण की बात है तो इसके लिए आयातित सामग्रियों पर शुल्क बढ़ाने के बजाय अपने उद्योगों को वैश्विक बाजार के हिसाब से प्रतिस्पर्धी बनने में मदद करना कहीं ज्यादा उत्पादक होगा। हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने और एक्सपोर्ट क्रेडिट बढ़ाने समेत कुछ और उपायों के साथ इस दिशा में सुधारों की शुरुआत हुई है। उद्यमियों की राह आसान करने के लिए अन्य सुधार यह हो सकते हैं कि सरकारी तंत्र की लालफीताशाही को रोका जाए और शासकीय सेवाओं के डिजिटलीकरण में तेजी लाई जाए।

भूमंडलीकरण के इस दौर में इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि हम ज्यादा वैश्विक बनें। वैश्विक स्तर पर कृषि और उद्योग, इन दोनों सेक्टर्स को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनना होगा। यदि ऐसी नीतियां बनाई जाएं, जिनसे कृषि प्रसंस्करित उत्पादों के निर्यातों में मदद मिले तो ये हमारी अर्थव्यवस्था का अहम आधार बन सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रीज को समुचित इफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना होगा, जिससे वे विदेशों के विनिर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के लायक बन सकें, जिन्हें कि अपने यहां सस्ता कर्ज मिल जाता है, आसान विद्युत आपूर्ति मिलती है तथा जिनके कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप न के बराबर होता है। सभी सरकारी विभागों के जरिये निर्यात के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिशन मोड पर विकसित करने की जरूरत है। हमें ऐसी नीतियां तैयार करनी होंगी, जिनमें व्यापार को प्राथमिकता मिले, अन्यथा भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर अपनी क्षमताओं को कभी हासिल नहीं कर सकेगा।

इस वर्ष बिकी सिर्फ एक टाटा नैनो

नई दिल्ली : टाटा मोटर्स ने इस वर्ष अब तक सिर्फ एक यूनिट नैनो की बिक्री की है। यह बिक्री फरवरी में हुई थी। वहीं, कंपनी ने इस वर्ष अब तक नैनो का उत्पादन नहीं किया है। कंपनी ने अब तक इसे बाजार से हटा लेने की औपचारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन कंपनी की तरफ से यह संकेत दिया जा चुका है कि ईंधन के बीएस-6 और सुरक्षा के नए मानकों को देखते हुए मौजूदा रूप में नैनो की बिक्री जारी रखना संभव नहीं है। (प्रेट्र)

अभी हमारे सामने रेपो रेट की कोई निचली सीमा नहीं है। बाजार की जरूरतों के हिसाब से हम रेपो रेट में कटौती का फैसला लेते रहेंगे।
— शक्तिकांत दास
गवर्नर, आरबीआइ

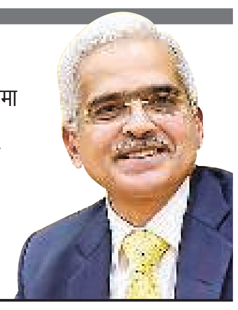

फेस्टिव सीजन ने मंदी के दावों को दिखाया ठेंगा

नई दिल्ली, आइएएनएस : अर्थव्यवस्था में मंदी के शोरगुल के बीच इन दावों को झुठलाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। नवरात्र के साथ फेस्टिव सीजन शुरू होते ही हर ओर जबर्दस्त बिक्री देखने को मिली है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों की अगुआई में शुरुआती छह दिन (29 सितंबर से चार अक्टूबर) में ई-कॉमर्स कंपनियों ने रिकॉर्ड तीन अरब डॉलर (करीब 21 हजार करोड़ रुपये) का कारोबार किया है। वालमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट और अमेजन की इसमें 90 फीसद हिस्सेदारी रही। बेंगलुरु की रिसर्च फर्म रेडसीयर कंसल्टेंसी ने यह जानकारी दी है। इससे पहले, चार अक्टूबर को प्री-बुकिंग खुलते ही सैमसंग के 1.65 लाख रुपये की कीमत वाले गैलेक्सी फोल्ड मॉडल के 1600 फोन मात्र 30 मिनट में बिक गए थे।

रिसर्च फर्म का कहना है कि फेस्टिव सीजन की जैसी शुरुआत हुई है, उसे देखते हुए अक्टूबर में कुल ऑनलाइन बिक्री का आंकड़ा छह अरब डॉलर (करीब 42,000 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है। रेडसीयर के संस्थापक व सीईओ अनिल कुमार का कहना है कि बिक्री के ये आंकड़े दिखाते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ग्राहकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है। सालभर पहले के मुकाबले इस फेस्टिव सीजन में 30 फीसद की तेजी देखी गई। इसमें टीयर-2 और टीयर-3 शहरों की अच्छी-खासी भागीदारी देखने को मिली। बिक्री के मामले में मोबाइल सेगमेंट सबसे ऊपर रहा। बिके कुल मूल्य (जीएमवी) में 55 फीसद हिस्सा मोबाइल का रहा। ज्यादातर ग्राहकों ने मोबाइल फोन खरीदने की अपनी योजना को त्योहारी सीजन के लिए टाल रखा था। यह दिखाता है कि फेस्टिव सीजन में वैल्यू शॉपिंग करने पर जोर दे रहे हैं।

फ्लिपकार्ट ने मारी बाजी : फेस्टिव सीजन की शुरुआती सेल में ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट का दबदबा रहा। कुल कारोबार में से 60 से 62 फीसद फ्लिपकार्ट के हिस्से में गया। इसकी सहयोगी इकाइयों मिंत्रा और जबोंग को भी जोड़ा जाए तो इसकी हिस्सेदारी 63 फीसद रही। फ्लिपकार्ट ने यह बाजी मोबाइल बिक्री के दम पर अपने नाम की। ग्राहकों ने अच्छी डील को देखते हुए किस्तों में खरीदने का विकल्प भी खूब आजमाया। अमेजन के कारोबार में मूल्य के आधार पर पिछले साल के मुकाबले 22 फीसद की वृद्धि दिखी।

- छह दिनों में ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 21 हजार करोड़ रुपये का कारोबार
- टीयर-2 और 3 शहरों के ग्राहकों का बढ़ रहा ऑनलाइन खरीद की ओर रुझान

प्रतीकात्मक

चार गुना तक बढ़ गई फ्लिपकार्ट सेलर्स की बिक्री : फ्लिपकार्ट ने बताया कि इस फेस्टिव सेल में पिछले साल के मुकाबले नए ग्राहकों की संख्या में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। छह दिन चली सेल में वेबसाइट पर 70 अरब व्यू मिले। टीयर-2 और अन्य छोटे शहरों से खरीदारों की संख्या में 50 फीसद की वृद्धि हुई। वहीं टीयर-3 शहरों से बिक्री दोगुनी हो गई। फ्लिपकार्ट के करीब 50 फीसद टॉप सेलर्स की बिक्री चार गुना तक हो गई। इस सेल में 40 फीसद से ज्यादा विक्रेता टीयर-2 शहरों व अन्य कस्बों से रहे।

मर्सीडीज ने एक दिन में डिलिवर कीं 200 से ज्यादा कारें

मुंबई, प्रेट्र : जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता मर्सीडीज बेंज ने फेस्टिव सीजन सेल के एक दिन में मुंबई, गुजरात और अन्य शहरों में अपने अलग-अलग मॉडल की 200 से ज्यादा कारें डिलिवर की हैं। कंपनी ने मंगलवार को दशहरा एवं नवरात्र की कारों की डिलिवरी की। कंपनी ने 125 कारों की डिलिवरी मुंबई में 74 कारों की डिलिवरी गुजरात में की।

अमेजन ने कहा, 45 फीसद रही हिस्सेदारी : इस रिपोर्ट से इतर अमेजन का दावा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर पांच दिन की सेल में जितने ग्राहक आए, वह भारत के पूरे मार्केटप्लेस के 51 फीसद के बराबर रहा। मूल्य के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 45 फीसद रही।

उन्होंने बताया कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान उसे देश के करीब 99.4 फीसद पिनकोड से ऑर्डर मिले। इस दौरान 500 से ज्यादा शहरों में 65,000 से ज्यादा सेलर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचा। करीब 15,000 सेलर्स ऐसे रहे, जिनकी बिक्री दोगुनी हो गई। इस सेल के दौरान 21,000 सेलर्स ने लाखों और करोड़ों में बिक्री।

खूब जुड़े नए ग्राहक : फेस्टिव सीजन की शुरुआती सेल में फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों के प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में नए ग्राहक जुड़े। इनमें टीयर-2 और टीयर-3 शहरों की अहम भागीदारी रही। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, फैशन और बड़े घरेलू सामानों की छोटे शहरों व कस्बों में सबसे ज्यादा मांग देखने को मिली।

फॉर्च्यून '40 अंडर 40' में भारतीय मूल के दो पेशेवर

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : फॉर्च्यून '40 अंडर 40' की इस वर्ष की सूची में भारतीय मूल के दो युवा पेशेवरों को भी जगह दी गई है। इनमें दिग्गज अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी इंटेल में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सॉफ्टवेयर व एआइ लैब के वाइस प्रेसिडेंट अर्जुन बंसल तथा फैशन प्लेटफॉर्म जिलिंगो की सह-संस्थापक और सीईओ अंकिति बोस शामिल हैं। अमेरिका की दिग्गज बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून की सालाना '40 अंडर 40' की सूची में चालीस वर्ष से कम उम्र के उन चालीस सबसे प्रभावशाली युवा पेशेवरों को स्थान दिया जाता है, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

बंसल की टीम में करीब 100 सदस्य हैं। ये सभी अमेरिका, इजरायल व पोलैंड की कई लोकेशंस पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए उपयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी शामिल हैं। 35 वर्षीय बंसल इन क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाई गई एक स्टार्ट-अप कंपनी निर्वाणा के सह संस्थापक रहे हैं। वर्ष 2016 में इंटेल ने निर्वाणा का अधिग्रहण कर लिया था। इस वक्त यह सौदा 35 करोड़ डॉलर (करीब 2,350 करोड़ रुपये) में हुआ था।

- अर्जुन बंसल इंटेल में संभाल रहे एआइ वर्टिकल की कमान
- अंकिति बोस आठ देशों में चला रहीं अपना ऑनलाइन कारोबार

अंकिति बोस (27) ने चार वर्ष पहले सिंगापुर-स्थित एक स्टार्ट-अप कंपनी की स्थापना की थी। फॉर्च्यून के मुताबिक बैंकॉक के एक बाजार में घूमते वक्त उन्हें पता चला कि वहां के स्थानीय कारोबारियों को अपना सामान ऑनलाइन माध्यम से बेचने में बहुत सी दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने फैशन रिटेलरों के साथ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो देखते-देखते बड़ा बन गया। उनकी कंपनी में हाल ही में सिक्वोया कैपिटल और टेमासेक होल्डिंग्स ने 22.6 करोड़ डॉलर (करीब 1,580 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। इस निवेश से बोस की कंपनी का मूल्य 97 करोड़ डॉलर (करीब 6,800 करोड़ रुपये) हो गया है। उनकी कंपनी में इस वक्त आठ देशों में करीब 600 कर्मचारी काम कर रहे हैं।

विज्ञापन खर्च में एफएमसीजी कंपनियां आगे

लेखाजोखा ▸ 2018-19 में विज्ञापन पर खर्च उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 12 परसेंट बढ़ा

हाउसहोल्ड व पर्सनल प्रोडक्ट श्रेणी पर विज्ञापन में हुआ सर्वाधिक खर्च

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

अन्य प्रोडक्ट श्रेणियों के मुकाबले बिक्री में काफी पीछे रहने वाली एफएमसीजी कंपनियां विज्ञापन पर खर्च के मामले में सबसे आगे रही हैं। हालांकि सभी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2018-19 में अपने विज्ञापन खर्च में पिछले वर्षों के मुकाबले वृद्धि की। लेकिन उनका यह खर्च बिक्री में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ा। सभी इंडस्ट्री वर्गों के कुल विज्ञापन खर्च में इस अवधि में 12 परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है। सभी इंडस्ट्री समूहों की बिक्री और उनके विज्ञापन खर्च का बीते पांच साल का एक अध्ययन बताता है कि कंपनियों का कंपाउंड एन्युअल ग्रोथ रेट इस अवधि में 5.4 परसेंट रहा है। केयर रेटिंग्स की इस रिपोर्ट मुताबिक विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन पर सबसे अधिक खर्च करने वाले इंडस्ट्री समूहों में बीते वित्त वर्ष एफएमसीजी कंपनियों को 1,67,819 करोड़ रुपये की बिक्री की। उससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 में यह आंकड़ा 1,55,703 करोड़ रुपये थी। इन कंपनियों की बिक्री में 7.78 परसेंट की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इन कंपनियों ने विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन पर 2018-19 में 10,347 करोड़ रुपये की राशि खर्च की। यह इसके पिछले वर्ष इस मद में खर्च की गई 9,419 करोड़ रुपये की राशि से 9.8 परसेंट अधिक है।

रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल एंड एंसीलियरीज सेक्टर ने इस अवधि में 4,98,560 करोड़ रुपये की बिक्री की। जबकि इस सेक्टर की कंपनियों ने 2018-19 में विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन पर 7,203 करोड़ रुपये की राशि खर्च की। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन सभी सेक्टर की कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले अपने विज्ञापन खर्च में तो 2018-19 में वृद्धि की। लेकिन जिस अनुपात में बिक्री में वृद्धि हुई, विज्ञापन पर खर्च उतना नहीं बढ़ा। मसलन केमिकल सेक्टर की बिक्री में तो 17 परसेंट की वृद्धि हुई, लेकिन विज्ञापन खर्च केवल सात परसेंट ही बढ़ा।

रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञापन के क्षेत्र में टीवी और प्रिंट सबसे बड़े सेग्मेंट रहे। विज्ञापन पर खर्च करने वाली इंडस्ट्री में शीर्ष पांच में एफएमसीजी के अतिरिक्त ऑटोमोबाइल एंड एंसीलियरीज, हेल्थकेयर, बैंक और केमिकल सेक्टर शामिल हैं। जबकि प्रोडक्ट केटेगरी के लिहाज से शीर्ष तीन में हाउसहोल्ड व पर्सनल प्रोडक्ट के बाद एम्यूजमेंट पार्क व रिक्रिएशन क्लब और टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन शामिल हैं। भारतीय कंपनियों ने वित्त वर्ष 2018-19 में 42,194 करोड़ रुपये की राशि विज्ञापन व सेल्स प्रमोशन पर खर्च की। यह बीते साल खर्च की गई 37,737 करोड़ रुपये की राशि से 12 परसेंट अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में विज्ञापन पर खर्च होने वाली राशि की वृद्धि दर दो-दो परसेंट रही थी। घरेलू विज्ञापन उद्योग को एशिया में सबसे तेजी से वृद्धि करने के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रखा जाता है।

प्रोडक्ट कैटेगरी में ये दिग्गज

प्रोडक्ट कैटेगरी के लिहाज से विज्ञापन और सेल्स प्रमोशन पर बिक्री के अनुपात में सर्वाधिक खर्च हाउसहोल्ड व पर्सनल प्रोडक्ट्स पर हुआ। इस श्रेणी में कंपनियों ने कुल बिक्री का 12 परसेंट विज्ञापन पर खर्च किया। सबसे कम खर्च कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट्स श्रेणी में हुआ। इसमें कंपनियों ने कुल बिक्री का केवल चार परसेंट विज्ञापन व सेल्स प्रमोशन पर खर्च किया।

तीन वर्षों में कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना तक पहुंचाने का लक्ष्य : तोमर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए देश में अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 35 देश हिस्सा लेंगे। इसकी जानकारी देते हुए कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अगले तीन वर्षों में कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के मद्देनजर सभी संबद्ध मंत्रालय समन्वय स्थापित कर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

मेल की तैयारियों का ब्यौरा देते हुए तोमर ने बताया कि 11-13 अक्टूबर को प्रगति मैदान में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेले में 150 से अधिक घरेलू सहकारी संस्थाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। इसमें कृषि मंत्रालय के साथ उद्योग, वाणिज्य और विदेश मंत्रालय के संबद्ध सभी संस्थाएं इसकी तैयारियों में लगी हुई हैं। मेले के आयोजन में छह साझेदार राज्य तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, मेघालय और गोवा प्रमुख हैं, जबकि बांग्लादेश साझेदार देश के रूप में शिरकत कर रहा है।

तोमर ने बताया कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह मेला समुचित मंच साबित होगा, जहां से हमारे उत्पादक सहकारी संस्थाएं विश्व स्तर पर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकेंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल वैश्विक बाजार में भारत 30 बिलियन डॉलर (करीब 2.10 लाख करोड़ रुपये) मूल्य का निर्यात करता है। इसे वर्ष 2022 तक 60 बिलियन डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने का भरोसा है।

- 11-13 अक्टूबर तक प्रगति मैदान में चलेगा सहकारी व्यापार मेला
- घरेलू सहकारी संस्थाओं को वैश्विक बाजार में मिलेगा मौका

तीन दिनों का सहकारी मेला निर्यात प्रोत्साहन में मदद करेगा। प्रतीकात्मक

एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाओं से देश के 94 फीसद किसानों का संबंध है। इसलिए सहकारी क्षेत्र के निर्यात का अलग से आंकड़ा तैयार करना आसान नहीं होगा। तोमर ने बताया कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, थाइलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ब्राजील, मलेशिया, इजरायल, जर्मनी और ईरान के प्रतिनिधिमंडल यहां पहुंच गए हैं। लगभग तीन दर्जन से अधिक विदेशी पांडाल स्थापित कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस मंच पर घरेलू सहकारी संस्थाओं को विदेशी प्रतिनिधियों के साथ व्यापार करने का मौका मिलेगा। इस दौरान वैल्यू चेन, कोल्ड स्टोर चेन, डेयरी, निर्यात प्रौद्योगिकी, जलवायु अनुकूलन, कृषि प्रसंस्करण उद्योग, पैकेजिंग, भंडारण, मशीनरी, ब्रांड संवर्धन, मार्केटिंग, सहकारी बैंकिंग, कृषि टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, पशुधन, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में अनुभव का आदान प्रदान हो सकेगा।

रेपो रेट में और कटौती संभव : आरबीआइ

मुंबई, आइएएनएस : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रेपो रेट में और कटौती पर विचार करती रहेगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के इस चरण में यह नहीं कहा जा सकता कि रेपो रेट की न्यूनतम सीमा क्या हो जहां से इसे और नहीं घटाया जा सकता है। अगली बैठक में एमपीसी ही यह तय करेगी कि रेपो रेट घटाया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन इतना तय है कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आरबीआइ रेपो रेट में कटौती की अपनी सोच पर आगे बढ़ता रहेगा।

दास से पूछा गया था कि आरबीआइ रेपो रेट को पांच या 4.75 परसेंट तक लाया जा सकता है या नहीं, जो इसका सर्वकालिक निचला स्तर है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या मौजूदा वक्त में आरबीआइ रेपो रेट को उससे भी नीचे ला सकता है। इसके जवाब में दास ने कहा कि नीतिगत ब्याज दर (रेपो रेट) का निचला स्तर क्या हो, अभी हमने यह तय नहीं किया है। हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि जब तक जीडीपी विकास दर की हालत वर्तमान जैसी रहती है और इसे गति देने की जरूरत दिखती है, तब तक हम रेपो रेट में कटौती का रास्ता खुला रखेंगे। इसलिए आप यह अनुमान नहीं लगा सकते कि रेपो रेट में कटौती की सीमा क्या होगी।

गौरतलब है कि आरबीआइ ने पिछले हफ्ते रेपो रेट में 25 आधार अंकों की और कटौती की थी। उसके बाद मौजूदा रेपो रेट 5.15 परसेंट रह गया है, जो मार्च, 2010 के बाद रेपो रेट का निचला स्तर है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर में एमपीसी की इस वर्ष की आखिरी बैठक में रेपो रेट में और कटौती की गुंजाइश बन रही है और वह घटकर पांच फीसद के नीचे रह सकता है।

- अगली बैठक में एमपीसी द्वारा की जा सकती है एक और कटौती
- रेपो रेट की निचली सीमा के बारे में बैंक नहीं कर रहा विचार
- इस वर्ष अब तक पांचों बार हो चुकी है रेपो रेट में कटौती

एनबीएफसी को मौद्रिक मदद पर विचार नहीं

मुंबई, आइएएनएस : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन ने कहा है कि बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को किसी भी वित्तीय मदद के बारे में विचार नहीं कर रहा है। उनके मुताबिक रिजर्व बैंक का मत है कि बाजार में तरलता या नकदी की कोई कमी नहीं है। एमपीसी मीटिंग के बाद विश्लेषकों के साथ बैठक में विश्वनाथन का कहना था कि यह देखना कर्जदाताओं का काम है कि किसी ग्राहक को वह कर्ज देने का फैसला करते हैं और किसे नहीं।

अमेरिका ने चीन की 28 इकाइयों को काली सूची में डाला

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने चीन के शिनजियांग प्रांत में काम कर रहीं 28 इकाइयों को काली सूची में डाल दिया है। इस प्रांत में स्थित इकाइयों पर मानवाधिकार समेत कई अन्य नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। काली सूची में शामिल की गई ये इकाइयां अब किसी भी अमेरिकी कंपनी के साथ कोई कारोबार नहीं कर पाएंगी। इन इकाइयों में व्यक्ति या कंपनियां शामिल हैं।

अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि शिनजियांग में स्थित इन इकाइयों पर उइगर स्वायत्तशासी क्षेत्र के अंदर उइगरों और अन्य प्रमुख मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन का आरोप है। ये कंपनियां चीन सरकार द्वारा उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन के अभियान में सहयोग करती हैं। इन इकाइयों के साथ अमेरिकी कंपनियां अब कोई खरीद-फरोख्त नहीं करेंगी। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा कि अमेरिकी सरकार और वाणिज्य मंत्रालय चीन के अंदर एथनिक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के बर्बर दमन को अब और बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं हैं। सरकार नहीं चाहती कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त व्यापार वाले हमारे वातावरण में विकसित तकनीक का उपयोग चीन में निहत्थी अल्पसंख्यक जनसंख्या के दमन में किया जाए।

- सूची में शामिल सभी इकाइयां चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित
- इस प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन समेत चीन पर कई आरोप

उइगर अल्पसंख्यकों की जासूसी और दमन पर अमेरिका ने अपनाया सख्त रुख। प्रतीकात्मक

अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि शिनजियांग उइगर स्वायत्तशासी क्षेत्र में स्थित ये इकाइयां इस क्षेत्र के अलावा चीन के अन्य हिस्सों में भी चीन की दमनकारी नीतियों में साथ देती हैं। इनमें चीन द्वारा सामूहिक ऐच्छिक हिरासत, उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकों के माध्यम से निगरानी और अन्य दमनकारी गतिविधियां शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक इकाइयों में ऐसे व्यक्तियों या कंपनियों को शामिल किया गया है जिन पर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति हितों को खतरा पहुंचाने या खतरे की हद तक शामिल रहने का आरोप है।

गौरतलब है कि अमेरिका ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है, जब चीन के साथ ट्रेड वार पर उसकी द्विपक्षीय वार्ता 10 अक्टूबर से प्रस्तावित है। इसमें अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लाइटहाइजर और वित्त मंत्री स्वीवन न्यूचिन करेंगे। वार्ता में चीन के दल की कमान वाइस प्रीमियर ल्यू ही के हाथों में होगी। चीन और अमेरिका पिछले 10 महीनों से कारोबारी समझौते पर वार्ता कर रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों फिर विश्वास के साथ कहा है कि चीन के साथ जल्द ठोस समझौता हो जाने की उम्मीद है। हालांकि वे यह भी कहते रहे हैं कि चीन उनके कार्यकाल में यह सौदा होने देने के मूड में नहीं दिख रहा है। दोनों कंपनियों के बीच पिछले वर्ष शुरू हुआ ट्रेड वार ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां दुनियाभर की संस्थाओं को ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की चिंता सताने लगी है। आइएमएफ की प्रमुख ने पिछले दिनों कहा कि अगर अमेरिका-चीन का ट्रेड वार जल्द नहीं सुलझा, तो दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है।

चुनौती

पांच वर्षों में 10 राज्यों की तरफ से 2,31,260 करोड़ रुपये की कृषि कर्ज माफी का एलान, अभी तक 1,54,168 करोड़ रुपये की राशि का ही बजट में हुआ प्रावधान

राज्यों के बजट पर किसान कर्ज माफी की फांस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले पांच-छह वर्षों से देश की राजनीति में कृषि कर्ज माफी योजना को जिस तरह से आजमाया जाने लगा है उसका असर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है। विगत पांच वर्षों में इन राज्यों ने 2,31,260 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज को माफ किया है। लेकिन अभी तक राज्यों ने अपने बजट से सिर्फ 1,51,168 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक व यूपी जैसे राज्यों ने अपनी माली हालत अगले दो-तीन वर्षों में ठीक नहीं की तो किसान कर्ज माफी के तहत दी गई राशि के समायोजन में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर ऐसे वक्त में जब मौजूदा आर्थिक मंदी की वजह से अमूमन सभी राज्यों के राजस्व के तमाम स्रोत सूखने के कयास लगाए जा रहे हैं।

कृषि कर्ज माफी को लेकर पहले भी कई बार एतराज जता चुके भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर अपनी नाखुशी जताई है। आरबीआइ की एक नई रिपोर्ट में राज्यों की माली हालत पर विपरीत असर पड़ने के साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किस तरह से इससे एक बड़े वर्ग में कृषि कर्ज की संस्कृति प्रभावित होती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014-15 में दो राज्यों (आंध्र प्रदेश व तेलंगाना) ने किसान कर्ज माफी का एलान किया था, जबकि वर्ष 2018-19 में चार बड़े राज्यों (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़) ने इसे लागू किया। इन दोनो के बीच में यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र व तमिलनाडु में भी इसे लागू किया गया। चालू वित्त वर्ष (2019-20) में इन राज्यों की तरफ से 39,703 करोड़ रुपये का प्रावधान संयुक्त तौर पर अपने बजट में किया गया है। ये राज्य अपने कुल सालाना बजट का 3.5 फीसद तक हिस्सा सिर्फ कृषि कर्ज माफी योजना को लागू करने के लिए ही खर्च कर रहे हैं। अभी दो-तीन वर्षों तक इस मद में खर्च होता रहेगा।

फाइल फोटो

केंद्रीय बैंक ने कृषि कर्ज माफी योजना सही है या गलत है, इस बारे में स्पष्ट तौर पर कोई निर्णय तो नहीं दिया है लेकिन कुछ तुलनात्मक अध्ययनों के जरिये इसकी प्रासंगिकता को सामने रखने की कोशिश जरूर की है। मसलन, उक्त 10 राज्यों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करने पर जितनी राशि का प्रावधान किया है उससे चार गुणा ज्यादा राशि कृषि कर्ज माफी योजना के लिए किया है। साथ ही इसके परोक्ष तौर पर पड़ने वाले असर को भी आरबीआइ ने गंभीर बताया है। सनद रहे कि हाल के वर्षों में राज्यों के चुनाव से पहले किसानों के कर्ज को माफ करने को लेकर एक तरह से राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा शुरू हो गई थी। तमाम राजनीतिक दल इस तरह की घोषणाएं करते हैं। 1990 से 2000 के दौरान राज्यों के स्तर पर सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए थे और उसके बाद वर्ष 2007-08 में केंद्र ने 56 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए थे। लेकिन वर्ष 2014-15 के बाद से दस राज्यों ने मिल कर कई गुणा ज्यादा कृषि कर्ज को माफ कर दिया है।

राज्य	वित्त वर्ष	कर्ज माफी (करोड़ रु. में)
आंध्र प्रदेश	(14-15)	24,000
तेलंगाना	(14-15)	17,000
तमिलनाडु	(16-17)	5280
महाराष्ट्र	(17-18)	34,020
यूपी	(17-18)	35,360
पंजाब	(17-18)	10,000
कर्नाटक	(18-19)	44,000
राजस्थान	(18-19)	18,000
एमपी	(18-19)	36,500
छत्तीसगढ़	(18-19)	6100

रिलायंस एमएफ अब हुई निप्पों इंडिया म्यूचुअल फंड

मुंबई, प्रेट्र : अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस म्यूचुअल फंड का अब निप्पों इंडिया म्यूचुअल फंड हो गया है। जापान की निप्पों लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में रिलायंस म्यूचुअल फंड में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। दोनों कंपनियों के बीच डील वित्तीय क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े एफडीआइ में शुमार है। इसके साथ ही निप्पों इंडिया म्यूचुअल फंड भारत में सबसे बड़ी विदेशी स्वामित्व वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) बन गई है। संदीप सिक्का अपनी पुरानी प्रबंधन टीम के साथ आगे भी कंपनी का नेतृत्व करेंगे।

निप्पों लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रेसिडेंट हिरोशी शिमिजु ने कहा, 'भारतीय एएमसी सेक्टर बहुत आकर्षक है और इसमें लंबी अवधि के विकास की क्षमता हमारे लक्ष्यों के अनुरूप है। हमारा मानना है कि निप्पों इंडिया म्यूचुअल फंड की कोर प्रबंधन टीम इस विकास में अहम भूमिका निभाएगी।' गौरतलब है कि अनिल अंबानी नियंत्रित रिलायंस ग्रुप इस वक्त अपना पूरा कर्ज उतारने की कोशिशों के तहत कई संपत्तियों की बिक्री में जुटा हुआ है।

प्रतीकात्मक

बात पते की

- कंपनी का नेतृत्व अब भी संदीप सिक्का और उनकी पुरानी प्रबंधन टीम करेगा
- डील भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े एफडीआइ में शुमार
- निप्पों इंडिया म्यूचुअल फंड भारत में विदेशी स्वामित्व वाली सबसे बड़ी एएमसी
- जापान में हर 12वां व्यक्ति निप्पों लाइफ इंश्योरेंस का बीमा धारक

3845.8 करोड़ रुपये था संयुक्त राष्ट्र का बजट वर्ष 2018-19 के लिए। इसमें अमेरिका का योगदान 22 फीसद रहा। इसमें शांति स्थापना से जुड़े कार्यों के लिए होने वाला खर्च शामिल नहीं है।

कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को विपक्षी नेता ने धोखेबाज कहा

क्यूबेक में एक चुनावी बहस के दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (बाएं) और विपक्षी नेता एंड्र्यू सीयर। एपी

ओटावा, रायटर/एपी : कनाडा में 21 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं। इसको लेकर देश का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नेता कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सोमवार शाम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और विपक्षी नेता एंड्र्यू सीयर के बीच टीवी पर आयोजित एक बहस में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चर्चा के दौरान दोनों के बीच जमकर तू-तू, मैं-मैं हुई। पीएम पर आरोपों की बौछार करते हुए विपक्षी नेता सीयर अचानक आपा खो बैठे। उन्होंने ट्रूडो को एक नंबर का धोखेबाज करार दिया। फिर क्या था? ट्रूडो भी उखड़ गए। एंड्र्यू की दोहरी नागरिकता पर सवाल उठाते हुए वह भी आक्रामक हो गए।

दरअसल टीवी बहस शुरू होते ही कंजरवेटिव पार्टी के नेता एंड्र्यू ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता ट्रूडो को घेरने की कोशिश की। उन्हें फर्जी कह कर संबोधित किया। आरोपों की झड़ी लगाते हुए विपक्षी नेता ने आगे कहा कि ट्रूडो फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं हैं। कनाडा में चुनावी प्रक्रिया के तहत आयोजित यह दूसरी बहस थी। इसमें कुल छह राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 338 सदस्यों वाली कनाडाई संसद के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होने हैं। बहस के दौरान पीएम ट्रूडो ने एंड्र्यू को घेरते हुए उनकी दोहरी नागरिकता का मुद्दा जोरशोर से उठाया। वह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चुनाव को लेकर हुए एक हालिया सर्वे के अनुसार, कंजरवेटिव पार्टी इस बार सत्तारूढ़ लिबरल को सत्ता से बाहर कर सकती है।

ट्रंप बोले, अनंत काल तक नहीं लड़ सकते

- सीरिया से सैनिक वापस बुलाने पर की टिप्पणी, कहा– उनका देश पुलिस फोर्स नहीं
- उत्तरी सीरिया में तुर्की, कुर्द लड़ाकों के खिलाफ शुरू करने वाला है अभियान

वाशिंगटन, प्रेट्र/आइएएनएस : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तरी सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के अपने फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कोई पुलिस फोर्स नहीं है। हम अनंत काल तक युद्ध नहीं लड़ सकते। ट्रंप ने यह फैसला ऐसे समय किया, जब सीरिया के इस क्षेत्र में तुर्की, कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अभियान शुरू करने वाला है।

व्हाइट हाउस ने गत रविवार को सीरिया की उत्तरी सीमाओं से अमेरिकी सैनिकों को बुलाने का एलान किया था। अमेरिका के इस कदम से सबसे ज्यादा कुर्द प्रभावित होंगे। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) के खिलाफ लड़ाई में कुर्द अमेरिका के मुख्य सहयोगी थे। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, 'हम अपने सैनिकों को स्वदेश वापस बुलाना चाहते हैं। अमेरिका वहां (सीरिया) पुलिस फोर्स की तरह है। अब हम वहां पर लंबे समय तक रहने नहीं जा रहे हैं।' ट्रंप ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सीरिया और अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों को वापस बुलाने का वादा किया था। व्हाइट हाउस ने कहा था कि तुर्की के अभियान के लिए सैनिकों को हटाया जा रहा है।

व्हाइट हाउस में तुर्की और सीरिया मामले पर बोलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

तुर्की उत्तरी सीरिया में सैन्य अभियान के लिए तैयार : तुर्की ने मंगलवार को कहा कि उत्तरी सीरिया में सैन्य अभियान शुरू किए जाने की तैयारी पूरी हो गई है। इस क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का एलान होने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि उनकी सेना सीरिया में कुर्दों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए तैयार है। तुर्की कुर्दों को आतंकी मानता है। उनका कहना है कि कुर्द तुर्की में सक्रिय अलगाववादी संगठनों के सबसे बड़े मददगार हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुर्की को चेताया : ट्रंप ने उत्तरी सीरिया में तुर्की के प्रस्तावित अभियान पर चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की के अभियान से अगर अमेरिकी सैनिकों या सहयोगियों को कोई नुकसान पहुंचा तो वह उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे।

रिपब्लिकन सांसदों ने की ट्रंप की आलोचना : ट्रंप के इस फैसले का उनकी रिपब्लिकन पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। कई सांसदों ने उनकी तीखी आलोचना की और कहा कि राष्ट्रपति का कदम कुर्दों के साथ विश्वासघात है। संसद के ऊपरी सदन सीनेट में रिपब्लिकन नेता मिच मैककोनेल, सीनेटर लिंडसे ग्राहम और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व दूत निकी हेली ने भी ट्रंप के फैसले की आलोचना की। ग्राहम ने उनके कदम को बड़ी भूल करार दिया है।

रूस ने कहा, अमेरिका ने नहीं दी सूचना

मॉस्को, रायटर : रूस ने कहा कि अमेरिका ने उत्तरी सीरिया से अपने सैनिक बुलाने के बारे में पूर्व में कोई सूचना नहीं दी। तुर्की ने भी अपने अभियान के बारे में जानकारी नहीं दी है। वहां के हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं। रूस और ईरान सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन के समर्थक हैं।

तुर्की की सैन्य कार्रवाई से भड़का ईरान

तेहरान, एएफपी : सीरिया में तुर्की की सैन्य कार्रवाई की खबर से ईरान भड़क गया है। ईरान के विदेश मंत्री जावद जरीफ ने अपने तुर्की समकक्ष को फोन कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि सीरिया में तुर्की के कदम का तेहरान विरोध करता है।

महाभियोग जांच को डोनाल्ड ट्रंप ने बताया धोखा

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए शुरू की गई जांच को लेकर विपक्षी डेमोक्रेटिक सांसदों पर फिर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने महाभियोग जांच को धोखा करार देते हुए संसदीय समिति के अध्यक्ष एडम शिफ के खिलाफ जांच की मांग की है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की एक समिति जांच कर रही है। इस सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में है। ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, 'महाभियोग जांच धोखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। लेकिन विपक्षी डेमोक्रेट्स ने गलती की है। एडम शिफ के खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिकी लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने संसद के साथ धोखा किया है।' व्हिसलब्लोअर की शिकायत पर प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने पिछले माह ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए जांच शुरू करने का एलान किया था। प्रतिनिधि सभा की खुफिया मामलों की समिति इसकी जांच कर रही है। व्हिसलब्लोअर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ट्रंप ने गत जेलेंस्की से फोन पर बात की थी और जो बिडेन को बदनाम करने के लिए उन पर दबाव बनाया था।

न्यूज गैलरी

नाश्ते में मिला बाल तो कर दिया पत्नी का मुंडन

ढाका : बांग्लादेश में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी का जबरदस्ती मुंडन सिर्फ इसलिए कर दिया, क्योंकि जब वह सुबह का नाश्ता कर रहा था तो उसे खाने में एक बाल मिला। हालांकि बाद में शिकायत होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यह मामला बांग्लादेश में जोयपुरहाट जिले के एक गांव का है। गांव वालों के अनुसार, सोमवार सुबह 35 वर्षीय बबलू मंडल को उसकी पत्नी ने नाश्ते में चावल और दूध दिया। इसी नाश्ते में उसे इंसानी बाल मिला। इसके बाद गुस्से में बबलू ने अपनी पत्नी के बाल जबरदस्ती काट दिए। जिले के पुलिस अधीक्षक शहरयार खान ने बताया कि गांव वालों की शिकायत पर बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया। (एएफपी)

हादसे के बाद पहली बार बोइंग को मिला मैक्स विमान का आर्डर

बेंगलुरु : परिचालन से हटाए जाने के बाद पहली बार बोइंग को एक 737 मैक्स विमान का आर्डर मिला है। कंपनी ने बताया है कि 2019 के पहले नौ महीनों में इस तरह के विमानों की डिलीवरी एक साल पहले की तुलना में आधी रह गई है। बता दें कि इस साल मार्च में इथोपिया एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में विमान में सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई थी। (रायटर)

पाक ने भारतीय दंपती को शारदा पीठ में नहीं दी पूजा की अनुमति

नई दिल्ली : पाकिस्तान ने हांगकांग में रह रहे एक भारतीय दंपती को गुलाम कश्मीर के नीलम घाटी में स्थित शारदा पीठ में पूजा की अनुमति नहीं दी। हालांकि, पीटी वेंकटरमण और सुजाता को पीठ से 100 किमी दूर तस्वीरों की पूजा करने की अनुमति जरूर प्रदान कर दी। एक वीडियो में वेंकटरमण ने कहा, हम लोग 30 सितंबर को माता शारदा देवी के दर्शन के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचे थे। हमने अधिकारियों से दर्शन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र देने का अनुरोध किया था, लेकिन हमें इसकी अनुमति नहीं दी गई। 72 साल बाद यहां इस तरह की पूजा हुई है। दंपती वैध वीजा पर नीलम घाटी आया था। (एएनआइ)

ब्रिटेन के सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट में 13 गिरफ्तार

लंदन : पुलिस ने ब्रिटेन में अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट में शामिल होने के संदेह में मंगलवार को 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग कथित रूप से उस अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूह का हिस्सा हैं, जिस पर हजारों करोड़ रुपये का 50 टन ड्रग्स नीदरलैंड से ब्रिटेन लाने का आरोप है। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोग 24 से 59 साल के बीच के हैं और इन्हें मंगलवार सुबह लंदन, मैनचेस्टर, लीड्स और इंग्लैंड के उत्तर में स्थिति पांच कस्बों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। (एएफपी)

इस महीने खाली हो सकता है यूएन का खजाना : गुतेरस

महासचिव ने कहा ▸ 23 करोड़ डॉलर का नकदी संकट गहराया

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने कुल बजट का केवल 70 फीसद किया भुगतान

संयुक्त राष्ट्र, एएफपी : सदस्य देशों की उदासीनता के कारण संयुक्त राष्ट्र इन दिनों आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर (1,638 करोड़ रुपये) के नकदी संकट का सामना कर रहा है। आशंका है कि इस महीने (अक्टूबर) के अंत तक इसका खजाना खाली हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में काम करने वाले 37 हजार कर्मियों को लिखे पत्र में गुतेरस ने सोमवार को कहा, 'कर्मचारियों को वेतन व अन्य भत्ते देने के लिए खर्चों में कमी लाने संबंधी अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे।' उन्होंने लिखा, 'सदस्य देशों ने 2019 के लिए जरूरी हमारे नियमित बजट का केवल 70 फीसद ही भुगतान किया है। इसके कारण सितंबर में संगठन के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी हो गई है। इस माह के अंत तक पहले के नकदी भंडार के खत्म होने का खतरा है।'

एंटोनियो गुतेरस। फाइल

सम्मेलन व बैठकें टाली जाएंगी, सेवाओं में होगी कटौती : गुतेरस ने खर्च में कमी लाने के लिए सम्मेलनों व बैठकों को टालने तथा सेवाओं में कटौती का उल्लेख किया है। उन्होंने केवल जरूरी कामकाज के लिए ही आधिकारिक यात्रा करने तथा ऊर्जा बचत के लिए कदम उठाने की बात कही है।

सदस्य देशों ने योगदान राशि बढ़ाने से कर दिया है इन्कार : संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के अनुसार गुतेरस ने इस साल की शुरुआत में सदस्य देशों से वैश्विक निकाय की नकदी संबंधी समस्या दूर करने के लिए योगदान राशि बढ़ाने को कहा था, लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया। गुतेरस ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिए आखिरकार सदस्य देश ही जिम्मेदार हैं।'

भारत ने बकाया भुगतान न होने पर जताई चिंता

संयुक्त राष्ट्र के 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर (925.84 करोड़ रुपये) के बकाया भुगतान को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। यह स्थिति तब है जब नियमित बजट वित्त वर्ष के खत्म होने में सिर्फ तीन महीने बाकी हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव महेश कुमार ने सोमवार को कहा, 'हम यह जानकर चिंतित हैं कि मौजूदा नियमित बजट वित्त वर्ष खत्म होने में सिर्फ तीन महीने रह गए हैं और इस साल तथा पिछले साल का करीब 13 करोड़ डॉलर बकाया है। इस बकाया भुगतान का असर सत्र के दौरान समिति के कामकाज पर भी होगा।' संयुक्त राष्ट्र की पांचवीं समिति के कामकाज को लेकर आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि बिना किसी शर्त के समय पर पूरा भुगतान सदस्य देशों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब हम वर्ष 2020 की बजट राशि पर विमर्श करें तब इसकी प्रक्रिया और अभ्यासों पर भी बात होनी चाहिए।

मैक्रों का इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रण

पेरिस, एएनआइ : फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ 'बेरहम लड़ाई' छेड़ने का प्रण लिया है। उन्होंने फ्रांस के समाज को इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रति हर वक्त सचेत रहने को कहा है।

पेरिस पुलिस के मुख्यालय में छूरेबाजी में चार पुलिसकर्मियों की हत्या के अगले दिन मंगलवार को राष्ट्रपति मैक्रों ने एक शोकसभा में अपना गहरा क्षोभ जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाएं अकेले और सरकार की सभी संबद्ध सेवाएं मिलकर भी कई सिरों वाले इस्लामिक सर्प निजात नहीं पा सकी हैं। मैक्रों ने प्राचीन यूनानी कथा के दैत्य 'हाइड्रा' का जिक्र करते हुए कई ओर से बढ़ रहे खतरे को बताने की कोशिश की है।

पुलिस मुख्यालय के पास स्थित नात्रदाम कैथेड्रल में उन्होंने कहा कि फ्रांस कई सालों से इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हो रहा है। यह चिंताजनक स्थिति है। अब यह पूरे राष्ट्र पर निर्भर है कि वह एकजुट हो और कुछ करने के लिए तैयार रहे। अब हमारे समाज को सतर्क होना पड़ेगा। ताकि हरेक पर नजर रखी जा सके कि आसपास किसी पर इस्लामिक कट्टरपंथ के प्रभाव में आने का खतरा तो नहीं है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हमलावर 45 वर्षीय माइकल हारपन के कुछ ही समय पूर्व इस्लाम कुबूल करने और कट्टरपंथी बन जाने की बात सामने आई है। उसने 2015 में हुए शार्ली आबदो अखबार के दफ्तर में हुए आतंकी हमले का समर्थन भी किया था।

काश शी की तरह भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सकता : इमरान

- भ्रष्टाचार के खिलाफ चीनी राष्ट्रपति के अभियान को सराहा
- चीन के सैन्य नेतृत्व के साथ बाजवा ने कश्मीर के मसले पर की चर्चा

बीजिंग, आइएएनएस : चीन की यात्रा पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रपति शी चिनफिंग की सराहना की है। इमरान खान ने कहा कि काश वो भी चिनफिंग के रास्ते पर चलते हुए अपने देश में 500 भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सकते। इमरान खान चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को संबोधित कर रहे थे।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान ने कहा कि राष्ट्रपति चिनफिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने सुना है कि चीन में पिछले पांच साल के दौरान 400 मंत्री स्तर के लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में सजा मिली है और उन्हें जेल में डाला गया है। इमरान ने कहा कि उनके देश में भ्रष्टाचार के मामलों की प्रक्रिया बहुत लंबी है। देश में निवेश की राह में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। इससे पहले इमरान ने चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग से मुलाकात की और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। राष्ट्रपति चिनफिंग समेत चीन के अन्य शीर्ष नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री बनने के बाद से इमरान की यह तीसरी चीन यात्रा है। इमरान खान के साथ पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी हैं। वह पीएम ली के साथ मुलाकात के दौरान भी मौजूद रहे। इससे पहले बाजवा ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर आर्मी जनरल हैन वीगुओ और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष जनरल शू किलियांग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि इनकी बैठक में कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हुई। बाजवा ने चीनी सैन्य अधिकारियों को कश्मीर के हालात के बारे में बताया।

बीजिंग में इमरान खान ने चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग से मुलाकात की। एपी

इमरान सरकार ने पहले साल में लिया रिकार्ड कर्ज

- देश के कुल कर्ज में 7509 अरब पाकिस्तानी रुपये का हुआ इजाफा
- विदेश से 2804 अरब और घरेलू स्रोतों से 4705 अरब का लिया कर्ज

इस्लामाबाद, एएनआइ : इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही रिकार्ड कर्ज लिया है। इसके चलते पड़ोसी मुल्क पर 7509 अरब पाकिस्तानी रुपये का कर्ज और बढ़ गया है। इस अवधि में विदेश से 2804 अरब पाकिस्तानी रुपये का कर्ज पाक सरकार ने लिया है।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के एक साल के कार्यकाल में देश के कुल कर्ज में 7509 अरब (पाकिस्तानी) रुपये की वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कर्ज के यह आंकड़े स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भिजवा दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि अगस्त 2018 से अगस्त 2019 के बीच विदेश से 2804 अरब रुपये का और घरेलू स्रोतों से 4705 अरब पाकिस्तानी रुपये का कर्ज लिया गया। सूत्रों ने बताया कि स्टेट बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में पाकिस्तान के सार्वजनिक कर्ज में 1.43 फीसदी का इजाफा हुआ है। संघीय सरकार का यह कर्जा बढ़कर 32,240 अरब पाकिस्तानी रुपये हो गया है। अगस्त 2018 में यह कर्ज 24,732 अरब पाकिस्तानी रुपये था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीने में सरकार का कर संग्रह 960 अरब पाकिस्तानी रुपये का रहा जोकि एक ट्रिलियन रुपये के लक्ष्य से कम है।

महिला अधिकार को 'हथियार' बनाने पर पाक की निंदा की

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर में अपने सियासी फायदे के लिए महिला अधिकार मुद्दे को 'हथियार' की तरह इस्तेमाल करने पर भारत ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि यह विडंबना ही है कि जिस देश में सम्मान के नाम पर महिला के जीवन के अधिकार का आए दिन उल्लंघन होता है और उसके दोषियों को दंडित भी नहीं किया जाता है वही भारत के बारे में 'बेबुनियाद' बातें कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव पालौमी त्रिपाठी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 'एडवांसमेंट ऑफ वीमन' विषय पर तीसरे समिति सत्र में कहा, 'ऐसे समय जब हम महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को साकार करने की दिशा में काम करने के अपने दृढ़ संकल्प दोहरा रहे हैं...बेमानी फिकरेबाजी और स्वार्थपूर्ण राजनीतिक लाभों के महिला अधिकार के मुद्दे को 'हथियार' के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह नहीं है। आज एक प्रतिनिधि ने मेरे देश के आंतरिक मुद्दों के बारे में अवांछित टिप्पणी कर असंवेदनशील तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया।'

यूरोपीय यूनियन ने ब्रिटेन को दी चेतावनी कहा– ब्रेक्जिट पर दोषारोपण बंद करे

- ब्रिटेन उत्तरी आयरलैंड को ईयू के कस्टम यूनियन में रखने के खिलाफ
- जर्मन चांसलर पर अस्वीकार्य मांग करने का लगाया आरोप

लंदन, रायटर : ब्रेक्जिट को लेकर यूरोपीय यूनियन (ईयू) और ब्रिटेन के बीच तल्खी बढ़ गई है। ईयू ने मंगलवार को ब्रिटेन से कहा कि वह ब्रेक्जिट पर मूर्खतापूर्ण दोषारोपण बंद करे। ईयू का यह कठोर बयान ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के दफ्तर डाउनिंग स्ट्रीट के सूत्र के उस बयान के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता संभव नहीं है क्योंकि जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने ऐसी मांग रखी है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने पिछले हफ्ते एक प्रस्ताव रखा था। जिसमें अन्य कई बिंदुओं के साथ ही उत्तरी आयरलैंड को ईयू के कस्टम यूनियन से अलग रखने की बात कही गई थी। मंगलवार को जॉनसन और मर्केल के बीच फोन पर बात हुई। जॉनसन के दफ्तर के सूत्र ने बताया कि मर्केल ने साफ कहा है कि अगर उत्तरी आयरलैंड को ईयू के कस्टम यूनियन से अलग रखा जाता है तो फिर कोई समझौता संभव नहीं है।

इस पर यूरोपीयन कौंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ट्वीट कर जॉनसन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जॉनसन बेवकूफी भरे दोषारोपण कर रहे हैं, वह न तो कोई समझौता करना चाहते हैं, न ब्रेक्जिट में देरी चाहते हैं, न ही यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं।

ईयू से ब्रिटेन के अलग होने में अब सिर्फ 23 दिन बचे हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच अलगाव के बाद के आपसी संबंधों को लेकर किसी तरह समझौता होता नहीं दिख रहा है। ब्रेक्जिट में देरी या बिना समझौते ब्रेक्जिट को लेकर दोनों पक्ष खुद को पाक-साफ दिखाने की कोशिश करने में जुट गए हैं।

बिना समझौता ब्रेक्जिट की तैयारी में जुटा ब्रिटेन : ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन यह लगातार साफ करते रहे हैं कि उनका देश ईयू से 31 अक्टूबर को अलग हो जाएगा, भले ही कोई समझौता हो या नहीं। समझौते के समर्थक सांसदों के दबाव में वह चुनाव कराने की बात तक कह चुके हैं। इसको लेकर अपने देश में कारोबारियों और आम लोगों की चिंता को कम करने के लिए उनकी सरकार ने मंगलवार को एक आकस्मिक योजना का प्रकाशन किया, जिसमें मेडिकल सामान के सप्लायरों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। 155 पेज के 'नो-डील रेडीनेस रिपोर्ट' नामक इस रिपोर्ट में देश की सीमाओं, लोगों के अधिकार, ऊर्जा, उद्योग और उत्तरी आयरलैंड को लेकर उठाए जाने वाले कदमों का जिक्रभी है।

खराब हालात का सामना करने की तैयारी में आयरलैंड : आयरलैंड ने मंगलवार को 2020 के लिए बिना समझौते वाले ब्रेक्जिट के हालात को देखते हुए बजट पेश किया। इसमें कुछ ऐसे उपाय किए गए हैं कि ईयू से बिना किसी समझौते के ब्रिटेन के अलग होने की स्थिति में कंपनियों को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। ब्रिटेन के अधिकार वाले उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड की सीमाएं लगती है। इसको देखते हुए आयरलैंड सरकार ने कहा है कि अगर ब्रिटेन बिना समझौते के अलग होता है तो आर्थिक विकास ठहर सकता है और 80 हजार से ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं।

धरती बचाने की जंग

ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर उतरे पर्यावरण प्रदर्शनकारी

यातायात को किया बाधित, पिछले दो दिनों में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध

पर्थ, एपी/आइएएनएस : जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से धरती को बचाने की मुहिम के तहत दुनिया भर में दो दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन का असर ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में भी दिखा। मंगलवार को भी बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और आवागमन को बाधित कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में पिछले दो दिनों के दौरान 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।

ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कंक्रीट से भरे पीपों में फंसे तीन लोगों के जरिये धरती पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को दर्शाया गया। जबकि एक प्रदर्शनकारी ने शहर के एक पुल से लटक कर अपना विरोध जाहिर किया। इस शहर में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिडनी शहर में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने मधुमक्खी की ड्रेस में प्रदर्शन किया।

पर्यावरण समूह एक्सटिंक्शन रिबेलियन की अपील पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कई यूरोपीय शहरों में विरोध प्रदर्शन किया और यातायात को बाधित कर दिया। लंदन से लेकर बर्लिन तक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इन शहरों में भी कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है।

लंदन में मंगवलार को पर्यावरण समूह एक्सटिंक्शन रिबेलियन के कार्यकर्ताओं ने ओक के पौधों के साथ संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। एएफपी

न्यूयॉर्क में भी 100 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार : अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी बड़े पैमाने पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर की यातायात व्यवस्था बाधित करने पर करीब 100 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए।

पर्यावरण कार्यकर्ताओं की मांग : ब्रिटेन के पर्यावरण समूह एक्सटिंक्शन रिबेलियन के आह्वान पर दुनिया के करीब 50 देशों में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समूह की मांग है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और साल 2025 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य के स्तर पर लाया जाए।

फेसबुक के खिलाफ जांच करेंगे 40 अमेरिकी अटार्नी जनरल

- ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा को लेकर होगी जांच

सैन फ्रांसिस्को, आइएएनएस : अमेरिका में फेसबुक के खिलाफ बड़ी जांच की जमीन तैयार हो गई है। दुनिया की इस दिग्गज सोशल नेटवर्किंग साइट के खिलाफ जांच के लिए करीब 40 अमेरिकी राज्यों के अटार्नी जनरलों ने हाथ मिलाया है। वे एक साथ मिलकर जांच करेंगे। मीडिया में आई खबरों के अनुसार, इन अटार्नी जनरलों ने सोमवार को न्याय विभाग और संघीय व्यापार आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की।

न्यूयॉर्क की अटार्नी जनरल लेटिटिआ जेम्स ने कहा, 'फेसबुक की जांच को लेकर हमारी (अटार्नी जनरलों) न्याय विभाग व संघीय व्यापार आयोग के अधिकारियों के साथ बात हुई। हम फेसबुक के खिलाफ यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर रहे हैं कि क्या उसके कृत्यों से ग्राहकों का डाटा खतरे में पड़ा था या नहीं? इसका भी पता लगाया जाएगा कि क्या ग्राहकों को मिलने वाली गुणवत्ता में कोई कमी की गई या विज्ञापन के लिए दाम बढ़ाया गया?' अमेरिकी संसद की एंटीट्रस्ट कमेटी पहले से ही फेसबुक, गूगल, एपल, अमेजन और दूसरी टेक कंपनियों के खिलाफ जांच कर रही है। इसमें यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या ये कंपनियां प्रतिस्पर्धा में बाधक बनीं या इनके कृत्य से ग्राहकों को नुकसान पहुंचा?

देना होगा 284 करोड़ जुर्माना

फेसबुक को वीडियो एड से जुड़े एक मामले के निपटारे के लिए चार करोड़ डॉलर (करीब 284 करोड़ रुपये) का जुर्माना भरना होगा। फेसबुक ने अपने प्लेटफार्म पर चल रहे वीडियो एड के समय की गणना करने में गलती की थी। इस चूक के लिए विज्ञापनदाताओं ने फेसबुक पर मुकदमा किया था। इनकी याचिकाओं पर अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग ने यह फैसला सुनाया है।

ये भी जानिए
अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने घर में 29 टेस्ट में 21.29 के औसत से 329 विकेट लिए जबकि हरभजन और कुंबले की जोड़ी ने 34 टेस्ट में 27.23 के औसत से 356 विकेट लिए थे।

विराट ने खोला भारत में तेज गेंदबाजों की सफलता का राज

कोहली ने कहा, व्यवहार व मानसिक स्थिति में बदलाव लाए तेज गेंदबाज, प्रमुख स्पिनर अश्विन व जडेजा की गेंदबाजी की भी तारीफ की

विराट कोहली • फाइल फोटो, एएफपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : बीते कुछ वर्षों से टीम इंडिया की गेंदबाजी शानदार रही है। मैच घरेलू पिचों पर हों या फिर विदेशी पिचों पर, भारतीय गेंदबाज अपनी तेज और स्पिन गेंदबाजी के मिश्रण के साथ दुनिया भर में कामयाब हुए हैं। टेस्ट मैच में 20 विकेट निकालना अब टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए कोई चुनौतीभरा काम नहीं लगता। विशाखापत्तनम टेस्ट में भारत ने मेहमान दक्षिण अफ्रीका को 203 रन से मात दी। इस जीत के टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भारतीय टीम की गेंदबाजी की कामयाबी का राज साझा किया।

घरेलू सपाट पिचों पर भारतीय तेज गेंदबाजों की कामयाबी का राज बताते हुए कोहली ने कहा, मैं मानता हूं कि हमारे तेज गेंदबाज पिछले दो साल में अपने व्यवहार और मानसिक स्थिति में जो बदलाव लाए हैं वो शानदार है। अगर तेज गेंदबाज मैदान से बाहर आते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि यह सारा काम अब स्पिनरों को ही करना होगा। ऐसे में अंतिम एकादश में उन्हें खिलाना न्यायसंगत नहीं है। अब वे भारत में भी अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर गर्मी और उमस भरा माहौल है तो वे हार मान लें। वे छोटे स्पैल के लिए जरूर कहते हैं, ताकि मैच में वे अपना 100 प्रतिशत झोंक सकें, ये जरूरी संवाद है जो दोनों ही ओर से जरूरी होता है। मैं मानता हूं कि टीम के लिए ऐसा करते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। ये सब नजरिये की वजह से है। शमी, इशांत, जसप्रीत और उमेश ये सभी वो सब जरूरी काम कर रहे हैं जो खेल में हम उनसे चाहते हैं। यहां तक छोटे-छोटे स्पैल में एक-दो विकेट निकालने से स्पिनरों को भी मदद मिलती है, जो दूसरे छोर से दबदबा बना रहे होते हैं। इससे टीम को थोड़ी-बहुत व राहत मिलती है। ये शानदार है कि हमारे तेज गेंदबाज भी विपरीत हालात में भी विकेट निकालने को आतुर रहते हैं।

एसजी गेंद में हुआ सुधार : जब पिछली बार हम यहां (घरेलू सत्र में) खेले थे उसकी तुलना में इस बार की एसजी गेंद बहुत शानदार है। इसमें कुछ हद तक सुधार किया गया है। हम चाहते हैं कि यह गेंद 80 ओवरों तक सख्त बनी रहे। अगर यह 40-45 ओवरों में ही नरम होने लगेगी तो फिर खेल में कुछ होता नहीं दिखेगा। यह स्थिति टेस्ट क्रिकेट के लिए आदर्श नहीं है। सख्त गेंद स्वभाविक रूप से थोड़ी ज्यादा उछलती है। इससे बल्लेबाजों को मुश्किलें आती हैं। हम इसे लगातार होते देखना चाहते हैं। अगर 80 नहीं तो करीब 60 ओवरों तक तो गेंद सख्त रहनी ही चाहिए। इससे हम खेल में लगातार बने रहेंगे। गेंदबाज आपकी ओर आते रहते हैं और आपके लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं, तब आपको रन बनाने में सक्षम रहना होता है। यही टेस्ट क्रिकेट का असली रोमांच और सारांश है।

शानदार रहे अश्विन व जडेजा : कोहली ने मुख्य स्पिनरों रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा के प्रदर्शन को लेकर कहा, हम हमेशा जानते हैं कि दूसरी पारी में जाकर ही खेल निर्णायक होगा। जड्डू और ऐश (जडेजा और अश्विन) दोनों ने ही बहुत शानदार प्रदर्शन किया। पहली पारी में अश्विन ने हमें सही स्थिति में पहुंचाया। पिच सपाट थी और उन्हें कुछ बाउंड्री भी मिल गई थीं। लेकिन, आपको यह भी मानना होगा कि हमने भी यहां 500 रन बनाए थे। इसलिए पिच में कोई खराबी नहीं थी। सच यह है कि अश्विन ने हमें उस पारी में सात विकेट दिलाए, जो उनके शानदार प्रयासों का नतीजा था और दूसरी पारी में जडेजा ने अपने एक ही स्पैल में हमें जल्दी-जल्दी सफलताएं दिलाईं।

बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर : पहले टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर कोहली ने कहा, रोहित दोनों पारियों में उम्दा खेले। पहली पारी में उनके साथ मयंक भी शानदार थे। दूसरी पारी में भी उन्होंने शानदार शुरुआत की। पुजारा सही ताल के साथ खेले, जिन्होंने हमारे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि जब हम बल्लेबाजी पर आए तो हम कुछ और अतिरिक्त रन बना पाए, जिससे हम विरोधी टीम को एक चुनौती भरा लक्ष्य दे पाए। यह मुश्किल काम था क्योंकि यहां मौसम भी चुनौतीपूर्ण था और पिच भी लगातार धीमी होती जा रही थी।

गेंदबाज	टेस्ट	पारी	ओवर	मेडन	रन	विकेट	पारी में सर्वश्रेष्ठ	मैच में सर्वश्रेष्ठ	औसत	इकॉनमी	स्ट्रा. रेट	पांच विकेट	10 विकेट
कोहली की कप्तानी में भारतीय तेज गेंदबाजों का भारत में प्रदर्शन													
उमेश यादव	19	38	513.4	102	1553	55	6/88	10/133	28.23	3.02	56.0	1	1
मुहम्मद शमी	10	20	296	61	879	34	5/35	6/116	25.85	2.96	52.2	1	0
इशांत शर्मा	12	23	307.3	76	819	23	3/37	5/80	35.6	2.66	80.2	0	0
भुवनेश्वर	5	10	130.3	34	367	18	5/48	8/96	20.38	2.81	43.5	1	0
वरुण आरोन	2	3	20	1	72	2	1/03	1/21	36	3.6	60.0	0	0
कोहली की कप्तानी में भारतीय स्पिनरों का भारत में प्रदर्शन													
आर अश्विन	24	46	1176	256	3206	147	7/59	13/140	21.80	2.72	48.0	12	4
रवींद्र जडेजा	24	47	1103.5	298	2513	123	7/48	10/154	20.43	2.27	53.8	6	1
कुलदीप यादव	3	6	94	9	340	14	5/57	6/119	24.28	3.61	40.2	1	0
अमित मिश्रा	4	8	118.5	17	396	12	3/51	4/60	33.00	3.33	59.4	0	0
जयंत यादव	4	8	104.3	19	367	11	3/30	4/68	33.36	3.51	57.0	0	0
01 जनवरी 2018 के बाद कोहली की कप्तानी में भारतीय तेज गेंदबाजों का भारत में प्रदर्शन													
उमेश यादव	3	6	65.5	11	213	15	6/88	10/133	14.20	3.23	26.3	1	1
मुहम्मद शमी	2	4	40.5	8	115	7	5/35	5/82	16.42	2.81	35.0	1	0
इशांत शर्मा	2	4	35	6	117	5	2/17	4/45	23.40	3.34	42.0	0	0
01 जनवरी 2018 के बाद कोहली की कप्तानी में भारतीय स्पिनरों का भारत में प्रदर्शन													
रविचंद्रन अश्विन	4	8	149.2	35	429	22	7/145	8/189	19.50	2.87	40.7	1	0
रवींद्र जडेजा	4	8	128.4	24	384	19	4/17	6/35	20.21	2.98	40.6	0	0
कुलदीप यादव	2	4	66.0	6	249	10	5/57	6/119	24.90	3.77	39.6	1	0

नोट : इसमें उन्हीं गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जिन्होंने कम से कम एक विकेट लिया है।

> मैं भारतीय हालात को अच्छी तरह से जानता हूं। यहां (पुणे) की पिच थोड़ी सी ज्यादा लाल है और इस स्थिति में सामान्य रूप से यहां ज्यादा स्पिन के अनुकूल हालात होंगे। इसलिए उम्मीद है कि गेंद पहले टेस्ट की तुलना में ज्यादा स्पिन करेगी।
> **फाफ डुप्लेसिस**, कप्तान, दक्षिण अफ्रीका

> हमारे खिलाड़ी एक टीम के तौर पर अपने प्रदर्शन में और सुधार करने पर ध्यान दे रहे हैं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का लुत्फ उठा रहे हैं। आप चाहें तो इसे जैसे चाहें वैसे देखें, लेकिन हमारे खिलाड़ी विपरीत स्थिति का लुत्फ उठा रहे हैं और अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं।
> **सेनुरान मुथुस्वामी**, ऑलराउंडर, दक्षिण अफ्रीका

दायें से भारतीय तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी, इशांत शर्मा और उमेश यादव • फाइल फोटो, प्रेट्र

हम पिचों की मांग नहीं करते : अरुण

पुणे, प्रेट्र : भारतीय गेंदबाजी कोच भरत अरुण अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से खुश हैं कि उन्होंने अपने कौशल के बूते पिच की प्रकृति का असर खुद के प्रदर्शन पर नहीं पड़ने दिया। मुहम्मद शमी ने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में दूसरी पारी में नीची और धीमी पिच पर शानदार प्रदर्शन किया, जबकि पिच के स्पिनरों के मुफीद होने की उम्मीद थी जिस पर रविचंद्रन अश्विन ने तब सात विकेट हासिल किए जब बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी। अरुण ने गेंदबाजी इकाई के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा, 'हमें जो पिचें मिलती हैं हम उनकी मांग नहीं करते। हमें दुनिया की नंबर एक टीम बनने के लिए जो भी परिस्थितियां मिलें, उन्हें घरेलू हालात के रूप में स्वीकार करना होगा।' उन्होंने कहा कि परिस्थितियों पर निर्भर रहने के बजाय हम कौशल पर ध्यान दे रहे हैं। इस पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज ने कहा, 'जब हम विदेश जाते हैं तो हम विकेट के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि हम इसे घरेलू परिस्थितियों के रूप में देखेंगे क्योंकि विकेट दोनों टीमों के लिए समान ही है। हम विकेट पर ध्यान देने के बजाय अपनी गेंदबाजी पर काम करेंगे।'

सात राज्य संघों पर चुनाव अधिकारी की नजर

बीसीसीआइ
- एमपीसीए के सदस्य ने की है इन संघों के खिलाफ शिकायत
- उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर नहीं ले पाएंगे चुनाव में भाग

हरित एन जोशी (मिड-डे), मुंबई : मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता के सात राज्य संघों के खिलाफ शिकायत और आपत्तियों के बाद बीसीसीआइ के चुनाव अधिकारी एन गोपालास्वामी इस पर कार्रवाई कर सकते हैं।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि गोपालास्वामी गुप्ता की सभी सात राज्य संघों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर रहे हैं। इन सात राज्यों में मध्य प्रदेश (एमपीसीए), उत्तर प्रदेश (यूपीसीए), दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए), महाराष्ट्र (एमसीए), हरियाणा (एचसीए), तमिलनाडु (टीएनसीए) और कर्नाटक (केएससीए) शामिल हैं।

अगर चुनाव अधिकारी ने इन सभी सात राज्यों को उल्लंघन का दोषी पाया तो यह राज्य संघ बीसीसीआइ चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। गोपालास्वामी ने 26 सितंबर को जारी नोटिस में कहा था कि इस चुनाव में सभी राज्य संघ अपने प्रतिनिधि का नाम सुनिश्चित करके आगे बढ़ाए। गुप्ता ने अपनी शिकायतों में सात राज्य संघों के बीसीसीआइ संविधान का उल्लंघन करने का दोषी पाया था। उनके अपने राज्य संघ में राजू सिंह एक ही समय पर तीन पदों पर बैठे हैं। साथ ही उनका आरोप है कि एमपीसीए में कई मामलों में संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। डीडीसीए में उन्होंने आरोप लगाया कि ओपी शर्मा दिल्ली सरकार में विधायक हैं, साथ ही वह डीडीसीए में कोषाध्यक्ष भी हैं, जो 6(5)डी नियम का उल्लंघन है। कर्नाटक में चुनाव अधिकारी ने बीसीसीआइ में ब्रजेश पटेल के राज्य संघ के प्रतिनिधि होने पर सवाल उठाया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। गुप्ता ने यूपीसीए के प्रतिनिधि राजीव शुक्ला पर भी कई आरोप लगाए।

रोहित ने किया पेड़ों की कटाई का विरोध

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मंगलवार को ट्वीट कर मुंबई की आरे कॉलोनी में हो रही पेड़ों की कटाई का विरोध किया है। रोहित ने लिखा, 'इस खबर में भले ही कुछ ज्यादा क्यों न हो, लेकिन पेड़ों की कटाई काफी बुरी बात है। मुंबई का यह हिस्सा हराभरा रहता है और यहां के तापमान में भी हल्की सी गिरावट रहती है, इसका कारण आरे कॉलोनी है। हम कैसे इसे छीन सकते हैं। साथ ही हजारों जानवरों के बारे में मत भूलिए, जिनके पास अब रहने को जगह नहीं होगी।' सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हालांकि आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी।

क्रिकेट प्रशंसकों के निशाने पर आए हार्दिक पांड्या

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान को उनके जन्मदिन पर जिस अंदाज में बधाई दी है वह क्रिकेट प्रशंसकों को रास नहीं आई और उन्होंने पांड्या की कड़ी निंदा की है।

जहीर सोमवार को 41 साल के हो गए और हार्दिक ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि जन्मदिन मुबारक हो जैक। मुझे उम्मीद है आप भी गेंद को मैदान से बाहर मारेंगे जैसे कि मैंने यहां किया। हार्दिक ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह एक घरेलू मैच में जहीर की गेंद पर छक्का मार रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट किया कि अहंकार तुझे ले डूबेगा मेरे भाई पांड्या..विनम्र बनें मूर्ख नहीं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि उम्मीद है कि हार्दिक आप टॉक शो के बाहर भी बेहतरीन प्रदर्शन करोगे और भारत के लिए विश्व कप जीतने में सफल हो पाओगे जैसा कि जहीर ने किया। पांड्या ने हाल ही में लंदन में अपनी पीठ की सर्जरी कराई है।

मंधाना दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना चोट के चलते दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से बाहर हो गई हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मंधाना को कुछ दिन पहले अभ्यास के दौरान पैर की अंगुली में चोट लग गई थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम बुधवार से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी।

हरभजन और वीना ट्विटर पर भिड़े

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और पाकिस्तानी अभिनेत्री वीना मलिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के यूएनजीए में दिए गए भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए। इमरान के भाषण पर हरभजन ने ट्वीट किया था कि यूएनजीए के भाषण में भारत के खिलाफ परमाणु युद्ध के संकेत दिए गए। एक मुख्य वक्ता होने के नाते इमरान खान द्वारा खूनी संघर्ष, अंत के लिए लड़ाई जैसे शब्दों का प्रयोग दो देशों के बीच सिर्फ नफरत को बढ़ावा देगा। एक खिलाड़ी होने के नाते मुझे उनसे शांति को बढ़ावा देने की उम्मीद थी। वीना ने जवाब देते हुए लिखा कि इमरान ने अपने भाषण में शांति की बात कही थी। उन्होंने उस डर और हकीकत की बात की थी जो कर्फ्यू हटने के बाद निश्चित तौर पर आएगा और दुर्भाग्यवश खूनी संघर्ष होगा।

विश्व महिला मुक्केबाजी

मेरी कॉम क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं स्वीटी बोरा बाहर

उलान उदे (रूस), प्रेट्र : भारत की दिग्गज मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम ने मंगलवार को थाइलैंड की जितपोंग जुतमस को दूसरे दौर में मात दे विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 51 किलोग्राम भारवर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मेरी कॉम ने थाइलैंड की खिलाड़ी को 5-0 से मात देते हुए अंतिम-8 में जगह बनाई।

पांच रेफरियों ने मेरी कॉम के पक्ष में 29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 30-27 से फैसला दिया। मेरी को पहले दौर में बाई मिली थी। अपने बदले हुए भारवर्ग 51 किलोग्राम में पहले विश्व खिताब के लिए रिंग में उतरी मेरी कॉम ने अपनी पहचान के मुताबिक ही खेल का मुजाहिरा किया। दोनों मुक्केबाजों ने आक्रामक शुरुआत की थी और यही कारण था कि कई बार रेफरी को इन दोनों को अलग करने के लिए कहना पड़ा। मेरी पहले दौर के अंत में थोड़ा आत्मरक्षा से खेलने लगीं। उन्होंने मौका देखते ही अच्छे पंच बरसाए। दूसरे दौर में भी यही हाल रहा। दोनों मुक्केबाज अपनी आक्रामकता में कमी नहीं कर रही थीं। मेरी 1-2 के संयोजन से अंक बटोरने की कोशिश में थीं और सही जगह पंच लगाने में भी सफल हो रही थीं, साथ ही वह अपनी फुर्ती के कारण जितपोंग के पंचों से अच्छा बचाव भी कर रही थीं।

तीसरे दौर में भी मेरी ने दायें और बायें जैब का अच्छा इस्तेमाल किया और जितपोंग के करीबन आने पर अपरकट भी लगाए। अंततः मेरी के हिस्से जीत आई। अगले दौर में मेरी का सामना कोलंबिया की इंग्रीट वालेंसिया से होगा। वह पैन अमेरिका विजेता हैं और रियो ओलंपिक-2016 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं।

स्वीटी को लगा झटका : वहीं 75 किलोग्राम भारवर्ग में स्वीटी बोरा को प्री-क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें वेल्स की लॉरेन प्राइस ने 3-1 से मात दे चैंपियनशिप से बाहर का रास्ता दिखाया।

विश्व कप पर निगाहें, स्मिथ व वार्नर की टी-20 टीम में वापसी

सिडनी, एएफपी : टेस्ट और वनडे टीम में जगह बनाने के बाद पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की टी-20 टीम में भी वापसी की। ऑस्ट्रेलिया ने अगले साल घर पर होने वाले टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैचों के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को 14 सदस्यीय टी-20 टीम में शामिल किया है।

इन दोनों स्टार बल्लेबाजों को गेंद से छेड़छाड़ मामले में एक साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इसके बाद उन्होंने टेस्ट, वनडे और अब टी-20 में वापसी की है। मुख्य चयनकर्ता ट्रेवर हांस ने कहा, 'हम स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी पर स्वागत करते हैं। स्टीव सभी प्रारूपों में विश्वस्तरीय बल्लेबाज हैं जबकि वार्नर टी-20 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज हैं। वह इस साल सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए इंडियन प्रीमियर लीग में भी सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे।' जिस टी-20 टीम का चयन किया गया है वह इस महीने के अंतिम सप्त से शुरू होने वाली सीरीजों में श्रीलंका और पाकिस्तान का सामना करेगी लेकिन हांस ने कहा कि उनकी निगाहें अगले साल के विश्व कप पर हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक साल बाद पुरुषों के टी-20 विश्व कप की मेजबानी करेगा और हमने उसे ध्यान में रखकर इस टीम का चयन किया है।' ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड में 27 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके बाद वह पाकिस्तान के खिलाफ तीन नवंबर से तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगा।

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस प्रकार है : आरोन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन मैकडरमॉट, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, बिली स्टेनलेक, मिशेल स्टार्क, एश्टन टर्नर, एंड्रयू टाय, डेविड वार्नर, एडम जांपा।

रीढ़ का ऑपरेशन करवाएंगे तेज गेंदबाज बहरनडॉर्फ : ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जेसन बहरनडॉर्फ रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाएंगे और इस कारण 2019-20 के घरेलू सत्र में नहीं खेल पाएंगे। सीमित ओवरों के क्रिकेट के विशेषज्ञ बहरनडॉर्फ ने हाल में 11 वनडे और सात टी-20 मैच खेल थे। जून में विश्व कप के दौरान वह शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने लार्ड्स में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 44 रन देकर पांच विकेट लिए थे जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। वह पीठ में दर्द के कारण ऑस्ट्रेलिया लौट आए थे। यह दर्द उन्हें 2015 से परेशान कर रहा है। विशेषज्ञों और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सा दल से विचार विमर्श के बाद बहरनडॉर्फ ने न्यूजीलैंड जाकर अगले सप्ताह रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञ रोवान स्कोटेन से ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। बहरनडॉर्फ ने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद हमने फैसला किया कि दर्द से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका ऑपरेशन है। मैंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कई गेंदबाजों से बात की जिन्होंने इस तरह का ऑपरेशन करवाया था और उन सभी का परिणाम को लेकर सकारात्मक रवैया था।

चैरिटी के लिए साथ में फुटबॉल खेले धौनी और पेस : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने यहां चैरिटी फुटबॉल मैच में हिस्सा लिया। धौनी का कामकाज देखने वाली कंपनी रिति स्पोर्ट्स ने फेसबुक पर इन दोनों खिलाड़ियों और कई अन्य की तस्वीरें साझा की। धौनी और पेस को अभ्यास की जर्सी पहने हुए दिखाया गया है जिसमें 'प्लेइंग फॉर ह्यूमेनिटी' लिखा हुआ है। चैरिटी का कारण और मैच की तिथि स्पष्ट नहीं है। बता दें कि पूर्व भारतीय कप्तान इन दिनों दो महीने के ब्रेक पर हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स में समाप्त हुए विश्व कप के बाद से ही वह टीम इंडिया के लिए नीली जर्सी में खेलते नहीं दिखे हैं।

क्रिकेट डायरी

शून्य पर आउट होकर उमर अकमल ने की विश्व रिकॉर्ड की बराबरी

कराची : पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने के मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान तिलकरत्ने दिलशान की बराबरी कर ली है। अकमल श्रीलंका के खिलाफ सोमवार को खेले गए पहले टी-20 मैच में शून्य पर आउट हो गए थे। अकमल 84 टी-20 मैचों में 10वीं बार शून्य पर आउट हुए हैं। श्रीलंका के दिलशान भी टी-20 में 10 बार शून्य पर आउट हुए हैं। अब अंतराष्ट्रीय टी-20 में सर्वाधिक 0 बनाने के मामले में ये दोनों बल्लेबाज संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। उमर अकमल मौजूदा सीरीज के पहले मैच में भी शून्य पर ही आउट हुए थे। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए दोनों मैचों में उमर गोल्डन डक का शिकार बने। पाकिस्तान का यह बल्लेबाज तीन साल बाद अंतराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में लौटा है। पाकिस्तान की टीम पहले ही श्रीलंका से टी-20 सीरीज गंवा चुकी है। यह पहला मौका है, जब श्रीलंका ने पाकिस्तान को टी-20 सीरीज में मात दी हो। सीरीज का तीसरा मैच बुधवार को खेला जाएगा। 10 बार 0 पर आउट होने वाले दिलशान ने अपने करियर में 80 टी-20 मैच खेले हैं। इस सूची में तीसरा नाम इंग्लैंड के ल्यूक राइट का है, जो नौ बार खाता नहीं खोल पाए थे। भारत के रोहित शर्मा छह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं। उनके नाम अभी तक 98 टी-20 मैच दर्ज हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी

उत्तर प्रदेश की जीत में चमके प्रियम गर्ग दिल्ली को हराया

वडोदरा, प्रेट्र : शिखर धवन की अर्धशतकीय पारी के बावजूद उत्तर प्रदेश ने युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग की तेजतर्रार पारी के दम पर मंगलवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप बी मैच में दिल्ली को पांच विकेट से शिकस्त दे दी। सीमित ओवरों में भारतीय पारी का आगाज करने वाले धवन ने 74 गेंद में 54 रन की पारी खेली जिनके बाद छठे नंबर के बल्लेबाज हिम्मत सिंह ने 77 गेंद में 64 रन बनाकर दिल्ली को 50 ओवर में आठ विकेट पर 204 रन बनाने में मदद की।

उत्तर प्रदेश ने खराब शुरुआत से उबरते हुए 29 ओवर में पांच विकेट पर 207 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रियम गर्ग ने 52 गेंद में 79 और उपेंद्र यादव ने 62 गेंद में 57 रन बनाए। उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों में मोहसिन खान ने तीन विकेट जबकि अंकित राजपूत ने दो विकेट लिए।

हरियाणा की करारी हार : एक अन्य मैच में विदर्भ ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बूते हरियाणा पर नौ विकेट से जीत हासिल की। विदर्भ के लिए दर्शन नलकंडे ने 25 रन देकर चार विकेट झटके। कप्तान अमित मिश्रा का टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला उलटा पड़ गया और हरियाणा की टीम 30.5 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। जवाब में विदर्भ ने 20.4 ओवर में एक विकेट पर 85 रन बनाकर जीत हासिल की।

उत्तराखंड की जीत : प्लेट ग्रुप के मैच में उत्तराखंड ने नगालैंड को सात विकेट से हराया। उत्तराखंड के लिए अवनीश सुधा ने सर्वाधिक 77 व तन्मय श्रीवास्तव ने नाबाद 54 रन बनाए। नगालैंड के लिए स्टुअर्ट बिन्नी ने 107 रनों की शतकीय पारी खेली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी नगालैंड 44.5 ओवर में 174 रन पर सिमट गई। जवाब में उत्तराखंड ने 36.2 ओवर में सात विकेट पर 176 रन बना जीत दर्ज की।

ऑस्ट्रेलियन ओपन से ग्रैंडस्लैम में वापसी करेंगे ब्रिटेन के एंडी मरे

टेनिस डायरी

> कूल्हे की सर्जरी के बाद अगले साल पहला ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट खेलने उतरेंगे एंडी

मेलबर्न, एएफपी : एंडी मरे अगले साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट में वापसी करेंगे। इस बात की घोषणा आयोजकों ने मंगलवार को की। ब्रिटिश खिलाड़ी मरे ने एक साल पहले अपने कूल्हे की सर्जरी कराई थी और अब वह फिटनेस और फॉर्म हासिल करने में लगे हुए हैं।

तीन बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन मरे अभी विश्व टेनिस सिंगल्स रैंकिंग में 289वें नंबर पर हैं, जबकि एक सप्ताह पहले तक वह 503वें स्थान पर थे। 32 वर्षीय मरे ने सोमवार को शंघाई मास्टर्स में अर्जेंटीना के जुआन इग्नेसियो लोंडेरो को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया, जहां मंगलवार को उन्हें इटली के फैबियो फोगनिनी से तीन घंटे से ज्यादा समय तक चले मुकाबले में 6-7, 6-2, 6-7 से शिकस्त झेलनी पड़ी। इससे पहले वह पिछले सप्ताह चीन ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के आयोजकों ने कहा कि पूर्व नंबर एक खिलाड़ी मरे ने साल के पहले ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट में खेलने की पुष्टि कर दी है।

आयोजकों ने यह भी बताया कि वह इस टूर्नामेंट के मुख्य दौर में खेलेंगे, ताकि वह अपनी ऊर्जा को बचा सकें। मरे मेलबर्न पार्क में पांच बार फाइनल खेल चुके हैं, जहां उन्हें चार बार नोवाक जोकोविक से और एक बार रोजर फेडरर से हार मिली है। मालूम हो कि छह महीने पहले मरे ने कूल्हे के दर्द के कारण भविष्य में खेलने पर संशय जताई थी और इसकी घोषणा करते समय वह भावुक भी हो गए थे, लेकिन समय के साथ पहले उन्होंने डबल्स और फिर सिंगल्स में वापसी की है और अब वह अच्छा खेल दिखा रहे हैं। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों को मरे के अलावा बेल्जियम की दिग्गज टेनिस स्टार किम किलस्टर्स के भी इस टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है, जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास को तोड़ने की घोषणा की थी।

2013 में मरे 77 साल बाद विंबलडन जीतने वाले पहले ब्रिटिश खिलाड़ी बने थे। तब वहां के लोगों ने उनमें फ्रेड पेरी की झलक देखने लगे थे। 2012 में यूएस ओपन जीतने वाले मरे 2016 में एक बार फिर विंबलडन चैंपियन बने। इसके अलावा ब्रिटेन के मरे ने अपने नाम दो ओलंपिक स्वर्ण पदक भी दर्ज कराए।

तीसरे दौर में पहुंचे फेडरर

शंघाई : स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने शंघाई मास्टर्स में स्पेन के एल्बर्ट रामोस विनोलास को 6-2, 7-6 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया। दूसरी वरीय फेडरर ने इस दौरान कोई भी ब्रेक प्वाइंट नहीं गंवाया, जो तीसरी बार इस टूर्नामेंट में खिताबी जीत की उम्मीद में हैं। फेडरर ने पहला सेट बेहद आसानी से अपने नाम किया, लेकिन दूसरे सेट में रामोस ने उनकी जमकर परीक्षा ली। इन दोनों खिलाड़ियों की इससे पहले 2015 के शंघाई मास्टर्स में भिड़ंत हुई थी जहां रामोस ने फेडरर को हराया था। उस हार का बदला लेने के बाद फेडरर ने कहा कि पिछले मैच में मिली हार उनके जेहन में थी। उधर तीसरी वरीय रूस के डेनिल मेदवेदेव ने ब्रिटेन के क्वालीफायर कैमरून नूरी को 6-3, 6-1 से हराया। वहीं अमेरिका के जॉन इस्नर और रैली ओपेल्का ने भी दूसरे दौर में जगह बनाई। इस्नर ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डि मिनॉर को 7-6, 6-4 से हराया, जबकि ओपेल्का ने सर्बिया के डुसान लाजोविक को 6-3, 6-4 से शिकस्त दी।

बोपन्ना-शापोवालोव क्वार्टर फाइनल में

शंघाई : भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार डेनिस शापोवालोव ने मंगलवार को कारेन खाचानोव और आंद्रे रूबलेव की रूसी जोड़ी को सीधे सेटों में हराकर शंघाई मास्टर्स के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और कनाडा की इस जोड़ी ने शुरुआती दौर में खाचानोव और रूबलेव की जोड़ी को 6-1, 6-4 से मात दी। पहले दौर के इस मुकाबले में पहले सेट में आसान जीत के बाद बोपन्ना और शापोवालोव दूसरे सेट में भी जीत जीत दर्ज की।

रघुनाथ जी की नगरी में देव मिलन

भव्यता ▶ शोभायात्रा के साथ शुरू हुआ कुल्लू का अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव

सात दिन तक चलने वाले उत्सव में पहले दिन 259 देवी-देवता कुल्लू पहुंचे

जागरण संवाददाता, कुल्लू

देव मिलन के प्रतीक हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ भगवान रघुनाथ की भव्य शोभायात्रा के साथ मंगलवार को हो गया। राज परिवार की दादी कही जाने वालीं माता हिडिंबा की मंजूरी और बिजली महादेव के आगमन के साथ माता भेखली का इशारा मिलने के बाद चार बजे भगवान रघुनाथ रथ से मैदान में पहुंचे। इसके बाद भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसमें जिला के 70 देवी-देवता शामिल हुए। सात दिवसीय दशहरा उत्सव के पहले दिन रथ मैदान में हजारों लोगों की उपस्थित में आरंभ हुए इस देव मिलन में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

उत्सव के लिए सोमवार से ही देवताओं का आगमन शुरू हो गया था। पहले दिन 259 देवी-देवता कुल्लू पहुंच चुके हैं। इस बार 331 देवी-देवताओं को निमंत्रण दिया गया था। कुल्लू घाटी ढोल नगाड़ों व देवधुनों से गूंज उठी है। चार बजे के करीब भगवान रघुनाथ पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में पहुंचे। उनके साथ राज परिवार के सदस्य थे। उनको पालकी से रथ में बैठाया गया। इसमें भगवान राम के साथ माता सीता व लक्ष्मण की मूर्तियां भी थीं। छड़ी बरदार महेश्वर सिंह और अन्य ने भगवान रघुनाथ की पूजा के बाद शोभायात्रा का आगाज करवाया है। ढोल नगाड़ों और नरसिंगों, शहनाई की स्वरलहरियों के साथ जय श्रीराम के उद्घोष के बीच सैकड़ों लोगों ने रथ की रस्सी खींचकर पुण्य कमाया। रथयात्रा के दौरान भगवान का रथ उनके अस्थाई शिविर तक गया। यहां पर देवताओं ने भगवान रघुनाथ के दर हाजिरी भरी और उसके बाद अपने-अपने स्थानों के लिए रवाना हो गए।

बालू नाग व शृंगा ऋषि का मिलन, यात्रा में नहीं हुए शामिल : धुर विवाद के चलते पुलिस के पहरे में रहने वाले बंजार घाटी के देवता बालू नाग और शृंगा ऋषि इस बार भी रथयात्रा में शामिल नहीं हुए। मेले में पहुंचते ही दोनों को पुलिस के पहरे में रखा गया है। दोनों ने भगवान रघुनाथ के दर जाकर दिन में शीश नवाया। बीच रास्ते में जब देवता बालू नाग जा रहे थे तो शृंगा ऋषि मिले। दोनों का भव्य देवमिलन ढालपुर के रास्ते में हुआ। इसके बाद दोनों देवता अपने-अपने मार्ग की ओर बढ़ गए।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मंगलवार को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ की शोभायात्रा के दौरान उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। जागरण

एक माह पहले हो गया था भगवान रघुनाथ के वस्त्रों का चयन

जागरण संवाददाता, कुल्लू : घाटी के अधिष्ठाता देवता भगवान रघुनाथ को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के दौरान पहनाए जाने वाले वस्त्रों का चयन माह पहले हो गया था। पितृ पक्ष के चलते इस बार इनका चयन पहले ही कर लिया गया था। भगवान रघुनाथ के वस्त्र राज परिवार के सदस्य तैयार करते हैं। सात दिन अलग-अलग रंग के वस्त्र भगवान रघुनाथ को पहनाए जाते हैं।

हर वर्ष दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर राज परिवार के सदस्य भगवान रघुनाथ के लिए उच्च गुणवत्ता के वस्त्रों का चयन करते हैं। इस बार पितृ पक्ष के चलते भगवान रघुनाथ के वस्त्रों का चयन पहले कर लिया गया था। नवरात्र में इन्हें तैयार किया गया। शृंगार के लिए अलग से व्यवस्था होती है। इन कपड़ों का रंग दिन के हिसाब से तय होता है। वस्त्र तैयार होने के बाद पुरोहित इनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसके बाद इन्हें भगवान को पहनाया जाता है। वस्त्र पहनाने के दौरान पुजारी व राज परिवार के दो सदस्य शिविर में मौजूद रहते हैं। महिलाओं को इस शिविर में रहने की इजाजत नहीं होती है। रहने वालों में छड़ीबदार सहित एक अन्य परिवार का सदस्य शामिल होता है। इस दौरान रोजाना पूजा-अर्चना के बाद यह कपड़े भगवान रघुनाथ को पहनाए जाते हैं।

...तो इसलिए देर से जला सबसे बड़ा रावण का पुतला

शंकर सिंह, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में पिछले कई हफ्तों से चर्चा का विषय रहा 221 फीट के रावण के पुतले का मंगलवार को दहन हो गया। धनास के पास स्थित रीहेबिलिटेशन कॉलोनी के पास स्थित ग्राउंड में बने देश के सबसे ऊंचे पुतले का दहन पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर ने किया। पुतले का दहन एक मिनट में ही हो गया। रावण को बनाने में लगभग तीन माह का समय लगा था और इस पर करीब 30 लाख रुपये का खर्च आया था। इसे देखने के लिए शाम पांच बजते ही मैदान लोगों से खचाखच भर गया। लोगों को पार्किंग की जगह भी बमुश्किल से मिली। कई लोगों ने अपनी बाइक और गाड़ी कॉलोनी में ही खड़ी की तो कई धनास की शुरुआत में ही अपनी गाड़ी खड़ी करके पहुंचे।

कार्यक्रम में पंजाब के गवर्नर वीपी सिंह बदनौर और चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष संजय टंडन शामिल हुए। शाम 6:55 बजे गवर्नर ने जैसे ही रिमोट से रावण दहन के लिए रिमोट का बटन दबाया तो वो नहीं चला। इसके बाद उन्होंने दोबारा बटन दबाया तो वो भी विफल रहा। स्टेज पर जय श्रीराम के नारे लगते रहे, लेकिन रावण दहन नहीं हो पा रहा था। तभी आयोजकों को पता चला कि जैमर लगा होने की वजह से रिमोट काम नहीं कर पाया। इसके बाद बार-बार आग्रह करने के बावजूद गवर्नर की सिक्योरिटी ने जैमर नहीं हटाया। बाद में गवर्नर ने सिक्योरिटी को इसके लिए डांटा तो जैमर को हटाया गया। इसके चलते जो रावण छत्र से शुरू होकर मुकुट, तलवार और ढाल से जलना शुरू होना था वह पैरों से जलना शुरू होकर ऊपर की ओर जला। अंत में छत्र जल ही नहीं पाया।

चंडीगढ़ में मंगलवार को 221 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। उपेंद्र सेन गुप्त

जमाई रावण को सुबह पूजा, अनुमति मांग शाम को किया वध

मप्र के मंदसौर में खानपुरा स्थित रावण की मूर्ति के पैरों में लच्छा बांधकर आशीर्वाद मांगते लोग। पंकज परमार

नईदुनिया, मंदसौर/उज्जैन

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में विजयादशमी पर्व पर अनूठी परंपरा का निर्वाह किया गया। खानपुरा में मंगलवार सुबह नामदेव वैष्णव समाज ने जमाई रावण की मूर्ति की पूजा की। मूर्ति के पैरों में लच्छा (धागा) बांधकर वर्षभर कष्टों को दूर रखने के लिए आशीर्वाद मांगा। आरती कर शाम को वध के लिए आने की अनुमति मांगी। गोधुलि बेला में रावण की मूर्ति के गले में पटाखे की लड़ बांधकर प्रतीकात्मक वध किया गया। मालूम हो, समाज के लोग रावण को अपना जमाई मानते हैं।

इसी प्रकार जिले के ग्राम धमनार में दोपहर बाद रावण की मूर्ति के समक्ष राम-रावण की सेना के बीच जलते हुए टोपलों (बांस की टोकरी) व शब्द बाणों से प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। इसमें राम की सेना के गोलू धाकड़ ने रावण की मूर्ति पर चढ़कर नाक पर मुक्का मारा और प्रतीकात्मक वध किया। उधर, इंदौर के परदेसीपुरा स्थित प्राचीन रावण मंदिर में लंकापति रावण का पूजन करने सैकड़ों लोग पहुंचे। यहां सुबह हवन और यज्ञ किया गया। सभी ने जय लंकेश के नारे भी लगाए।

मंदसौर के धमनार में रावण के पुतले की नाक पर मुक्का मारकर किया गया प्रतीकात्मक वध। मुकेश सोनी

चांदी की पालकी में दशहरा मैदान पहुंचे भगवान महाकाल : उज्जैन में विजयादशमी पर भगवान महाकाल चांदी की पालकी में विराजित होकर दशहरा मैदान पहुंचे। भगवान मनमहेश स्वरूप में विराजित थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल ने भगवान को सलामी दी। इसके बाद सवारी मंदिर से रवाना हुई। दशहरा मैदान में पूजन किया गया। इसके बाद सवारी पुनः मंदिर लौटी।

शहर की सीमा से है सवारी का संबंध : जानकारों के मुताबिक, महाकाल की सवारी का संबंध शहर की सीमा से है। प्राचीनकाल में वर्षाकाल खत्म होने पर राजा मां शक्ति की उपासना करते थे। शस्त्र पूजन करते थे। राजा राज्य की रक्षा करने के लिए सक्षम है, यह बताने को बलि देते थे। शहर की सीमा तक सवारी के रूप में जाते थे। उज्जैन के राजाधिराज महाकाल हैं, इसलिए इसी परंपरा में उनकी सवारी भी निकाली जाती है।

शीतकाल के लिए 17 नवंबर को बंद होंगे बदरीनाथ धाम के कपाट

जागरण टीम, गढ़वाल : चार धाम यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। शीतकाल के लिए धामों के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। विजयादशमी के पावन पर्व पर बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि का एलान कर दिया गया। धाम के कपाट 17 नवंबर को सायं 5.13 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मंगलवार को केदारनाथ और गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त भी निकाला गया, जबकि यमुनोत्री के लिए मुहूर्त बुधवार को निकाला जाएगा। गौरतलब है कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैय्या दूज पर 29 अक्टूबर और गंगोत्री के कपाट अन्नकूट पर्व पर 28 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे।

मंगलवार को बदरीनाथ धाम में रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की उपस्थिति में बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल ने तिथि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुसार 13 नवंबर से कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत 13 को गणेश पूजन, 14 को आदि केदारश्वर के कपाट बंद, 15 को खडग व पुस्तक पूजा और 16 नवंबर को देवी लक्ष्मी को गर्भ गृह में आने का न्योता दिया जाएगा। 17 नवंबर को कपाट बंद होने के अवसर पर भगवान का फूलों से शृंगार होगा। धर्माधिकारी ने बताया कि कपाट बंद होने के अवसर पर भगवान बदरीनाथ को पहनाए जाने वाला घृत कंबल को बनाने का कार्य माणा की कन्याओं ने शुरू कर दिया है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने का मुहूर्त भी निकाला गया।

छग में काली मिर्च से कर रहे 'उजाले' की खेती

जागरण विशेष ▶ एक पंथ दो काज, अच्छी आमदनी के साथ साल के वनों का संरक्षण करने में भी मिलेगी मदद

पूनमदास मानिकपुरी, कोंडागांव

आर्थिक रूप से वनों पर ही निर्भर रहने वाले आदिवासियों ने तंगी और बदहाली के अंधेरे में उजाला भरने के लिए काली मिर्च की खेती शुरू की है। काली मिर्च से आमदनी तो होगी ही, वहीं साल के जिन पेड़ों पर काली मिर्च की लताएं चढ़ी होंगी, उनका संरक्षण भी हो सकेगा।

छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय कोंडागांव से करीब 15 किलोमीटर दूर लंजोड़ा सल्फीपदर गांव के 72 परिवार इस युक्ति को आजमा रहे हैं। समाजसेवी हरि सिंह सिदार ने ग्रामीण आदिवासी परिवारों को इसकी प्रेरणा दी। हरि सिंह के मुताबिक, करीब 50 हजार मिश्रित पेड़ों को काली मिर्च लगाने के लिए चिह्नित किया गया। प्रति परिवार के हिस्से लगभग 700 पेड़ आए। इनके ही इर्दगिर्द काली मिर्च की पौध लगाई गई, जिनकी लताएं इन पेड़ों से लिपटी हुई हैं। ये सभी परिवार अपने पेड़ों की सुरक्षा करते हैं। पहले महिलाएं ही रखवाली को निकलती थीं, लेकिन अब पुरुष भी साथ होते हैं। उन्होंने बताया कि लंजोड़ा के बाद बालोंड, कांटागांव, भीरागांव, गारे, जुंगानी आदि 50 गांवों के ग्रामीण भी काली मिर्च के पौधे लगाने की तैयारी में हैं। इसके लिए उद्यानिकी विभाग दो लाख पौधे तैयार कर रहा है। ग्रामीण बिसरूराम, पंचम सिंह, हैमवती और रामदई कहते हैं कि पहले साल पेड़ों की अवैध कटाई हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। सभी ग्रामीण इनकी सुरक्षा करते हैं। इससे जंगल समृद्ध हो रहे हैं।

उद्यानिकी एवं कृषि महाविद्यालय, कुमरावंड, जगदलपुर के वैज्ञानिक डॉ. कृष्णपाल सिंह कहते हैं कि काली मिर्च में करीब चार साल में फल आना शुरू हो जाता है। 30 से 35 साल तक फल मिलता है। शुरुआत में तीन-चार किलो फल आता है, जो बढ़कर 12-15 किलो तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि 500 रुपये प्रति किलो की दर से भी यदि काली मिर्च बेची जाएगी तो प्रति परिवार अच्छी खासी आमदनी होगी।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

छग के लंजोड़ा सल्फीपदर गांव में साल के पेड़ के करीब काली मिर्च का पौधा रोपते ग्रामीण। नईदुनिया

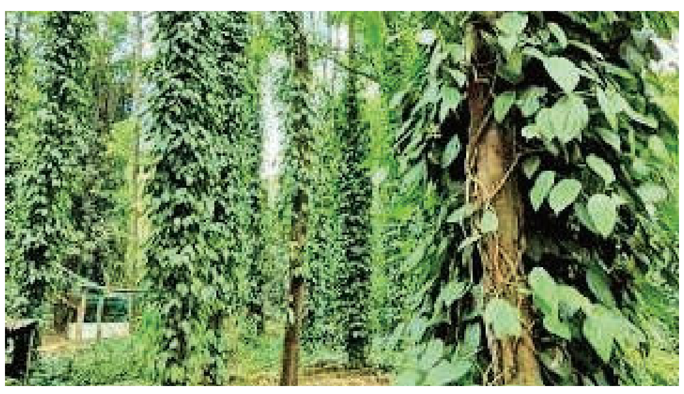
साल के पेड़ पर लिपटीं काली मिर्च की लताएं। नईदुनिया

यह प्रयोग हर लिहाज से उपयोगी साबित हो रहा है। ग्रामीणों का उत्साह देख उन्हें सामुदायिक वन अधिकार प्रदान भी किया जाएगा। उद्यानिकी विभाग को काली मिर्च के पौधे तैयार करने को कहा गया है। फल आते तक ग्रामीणों को जंगल में अदरक, अरबी, केऊकंद आदि लगाने के लिए बीज प्रदान किया गया है, जिससे उनकी आमदनी होती रहे। वनों में मौजूद वृक्षों के पत्तों से कंपोस्ट खाद तैयार हो रही है।
– नीलकंठ टेकाम, कलेक्टर, कोंडागांव, छत्तीसगढ़

कोंडागांव में काली मिर्च की पैदावार के जरिये साल वनों को बचाने का प्रयोग अनुकरणीय है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाएगा। इसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार विशेष योजना बनाएगी।
– मुहम्मद अकबर, वन मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

देश के पहले प्लॉगर बंगाल में साफ कर रहे दुर्गा पूजा पांडाल

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▶ मिशन 'रन टू मेक इंडिया लिटर फ्री' के तहत रिपु दमन पहुंचे कोलकाता

▶ उत्सव के दौरान खानपान से फैलने वाली गंदगी के चलते चुना यह समय

देश के पहले प्लॉगर रिपु दमन बेवली ने अपने मिशन 'रन टू मेक इंडिया लिटर फ्री' के तहत मंगलवार को बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान पांडालों की सफाई की। इस मिशन के तहत वह दौड़ने के साथ देश के 50 शहरों की सफाई कर रहे हैं।

रिपु दमन ने कहा कि इस महीने के लिए कोलकाता को चुनने का मकसद यह था कि यहां उत्सव का माहौल रहता है। दुर्गा पूजा के मौके पर यहां लोग देवी दुर्गा की आराधना के साथ जमकर खानपान का लुफ्त उठाते हैं। इस कारण पूजा पांडालों के आसपास गंदगी फैल जाती है। इसीलिए कूड़े को रोकने के लिए लोगों के बीच एक संदेश देने के लिए वह पांडालों की सफाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बुधवार को खड़गपुर जाएंगे। तीन नवंबर को दिल्ली में अपनी दौड़ का समापन करेंगे। वह चाहते हैं कि लोग सिर्फ सफाई ही ना करें, बल्कि वह इतने जिम्मेदार बनें कि इधर-उधर कूड़ा डालना बंद कर दें। गौरतलब है कि प्लॉगिंग में जॉगिंग करते हुए कूड़ा उठाया जाता है।

कौन होता है प्लॉगर : प्लॉगर मतलब वह शख्स जो सेहत ही नहीं बल्कि स्वच्छता के लिए भी दौड़ता है। प्लॉगर जिस रास्ते में दौड़ता है, उस पर मिलने वाले कचरे को हटाकर शहर को स्वच्छ रखता है। इसके जरिये वह लोगों को बेहतर और स्वच्छ जीवन का कॉन्सेप्ट अपनाने और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए प्रेरित करता है। देश के पहले प्लॉगर रिपु दमन सफाई में बेंचमार्क हैं।

प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं तारीफ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात' में रिपु दमन की काफी प्रशंसा की थी। गौरतलब है कि दिल्ली के रिपु दमन ने पांच सितंबर 2019 को कोच्ची से 1000 किलोमीटर की स्वच्छता दौड़ (प्लॉग रन) शुरू की थी और अपनी इसी यात्रा के दौरान उनका ये अभियान जारी है। रिपु दमन स्वच्छता अभियान के तहत इसे एक नई मिसाल कायम करना चाहते हैं।

2017 में शुरू किया था अभियान

रिपु दमन अच्छी-खासी नौकरी छोड़कर 2017 में प्लॉगर्स ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। इसमें देश को स्वच्छ बनाने का जज्बा रखने वाले और लोग भी जुड़े। जानकारी के अनुसार रिपु दमन दो साल में देश के 21 शहरों में 300 स्वच्छता दौड़ लगा चुके हैं।

देश के पहले प्लॉगर रिपु दमन बेवली सफाई करते हुए। एएनआइ

जागरण सरोकार

ड्रमस्टिक के बीजों के पाउडर से बनाई किट, टी-बैग की तरह आसानी से किया जा सकेगा इस्तेमाल, पांच मिनट में एक लीटर दूषित पानी पीने योग्य बन जाएगा

सहजन से बना वाटर प्यूरीफायर डायरिया और पीलिया से दिलाएगा मुक्ति

सुनील शर्मा, सोलन

सहजन यानी ड्रमस्टिक के बीजों के पाउडर से बनाए गए इस वाटर प्यूरीफायर का इस्तेमाल टी-बैग की तरह ही आसानी से किया जा सकता है। इससे पांच मिनट में एक लीटर दूषित पानी पीने योग्य बन जाता है। कीमत मात्र 50 पैसे है। जी हां, पानी को अब जीवाणुमुक्त और शुद्ध बनाना आसान हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय ने यह वाटर प्यूरीफायर किट तैयार की है। इससे डायरिया और पीलिया रोकने में मदद मिलेगी।

स्वस्थ समाज

शूलिनी विवि में इस प्रोजेक्ट पर तीन साल से काम चल रहा था। लक्ष्य यह था कि औषधीय रसायनों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सस्ता और आसान वाटर प्यूरीफायर तैयार किया जाए, जो गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को दूषित जल से होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचा सके। शोधार्थियों ने सहजन (ड्रमस्टिक) के बीजों में मौजूद जीवाणुरोधी औषधीय गुणों को इस काम के लिए सबसे उपयुक्त पाया। ट्रायल पूरे होने के बाद तय हुआ कि इससे टी-बैग की तर्ज पर वाटर प्यूरीफायर किट तैयार की जाएगी। सहजन के बीजों को पीस कर, पाउडर को छोटी सी थैली (टी-बैग की तरह) में भर जब इसे सामान्य पानी (एक लीटर) में पांच से दस मिनट तक डुबोया गया, तो इसके जीवाणुरोधी रसायनों ने पानी को जीवाणुरहित बना दिया। दूषित पानी अब पीने योग्य बन गया था।

इस प्रोजेक्ट के लिए छात्रा अमनप्रीत कौर को बेल्जियम की यंग वाटर फेलोशिप मिली है। भारत सरकार ने उन्हें अध्ययन के लिए यंग इंडिया अवॉर्ड के तहत दस लाख रुपये दिए हैं। अमनप्रीत का मॉडल देशभर में पहले स्थान पर रहा है। वह कहती हैं, 'नदियों में सीवर के पानी को छोड़े जाने, भूजल के अशुद्ध होने और टूटी-फूटी पाइपलाइन जैसे अनेक दूसरे कारणों से पानी अशुद्ध हो रहा है। जीवाणुओं के कारण हर वर्ष कई लोगों की जान चली जाती है। दूषित जल में मौजूद जीवाणुओं से डायरिया और पीलिया जैसे रोग फैलते हैं। यह किट ऐसे सभी बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। सहजन के बीजों में मौजूद विशेष प्रोटीन जीवाणुरोधी औषधि का काम करता है।'

गांवों तक पहुंचाने की तैयारी : शूलिनी विश्वविद्यालय के प्रबंधक विशाल आनंद, प्रो. पीके खोसला और अतुल खोसला अमनप्रीत की उपलब्धि से उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि इस किट को गांवों तक पहुंचाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसे इस तरह से भी बनाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल बड़े बर्तनों, घड़े आदि में भी हो सके।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics positive-news

अमनप्रीत कौर। जागरण

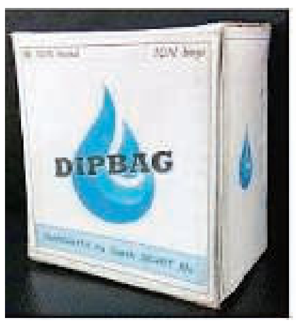

वाटर किट, जिससे पानी साफ करने में मदद मिलेगी। जागरण

इन्होंने निभाई अहम भूमिका

डीन, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट प्रो. सौरभ कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस प्रोजेक्ट की सफलता में बायोटेक्नॉलाजी में पीएचडी अमनप्रीत कौर, पीएचडी की ही छात्रा आलिया अली और इशांत शर्मा (एमटेक) का योगदान है। अमनप्रीत पंजाब के फरीदकोट की रहने वाली हैं। अमनप्रीत ने कहा कि इस युक्ति का इस्तेमाल लोग खुद भी पानी शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं।

भारतीय प्रादेशिक सेना का गठन हुआ

1949 में आज ही देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी.राजागोपालाचारी ने प्रादेशिक सेना का गठन किया था। इस सेना के सदस्य 1962, 1965 और 1971 में हुए सैन्य अभियान का हिस्सा थे। कपिल देव और महेंद्र सिंह धौनी प्रादेशिक सेना के सदस्य हैं।

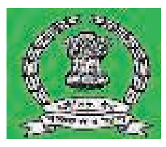

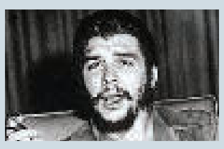

अर्जेंटीना के प्रसिद्ध क्रांतिकारी चे ग्वेरा की हत्या

1967 में आज ही चे ग्वेरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चे ग्वेरा को क्यूबा में हुई क्रांति का मुख्य नायक माना जाता है। उन्होंने दक्षिण अमेरिका के कई देशों में क्रांति लाकर उन्हें स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया। वह डॉक्टर, लेखक, सामरिक रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ भी थे।

उस्ताद अमजद अली खान को जन्मदिन मुबारक हो

1945 में आज ही ग्वालियर में संगीत के सेनिया बंगश घराने की छठी पीढ़ी में जन्म लेने वाले उस्ताद अमजद अली खान को संगीत विरासत में मिला। उन्होंने महज 12 साल की उम्र में एकल सरोद वादन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। उन्होंने शिवांजली, हरिप्रिया कानदा, किरण रंजनी, सुहाग भैरव, ललित ध्वनि, श्याम श्री और जवाहर मंजरी जैसे कई रागों की रचना की। उन्हें यूनेस्को पुरस्कार, कला रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी और तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

इधर-उधर की

कनाडा में दंपती ने उगाया 800 किग्रा का कद्दू

टोरंटो, एजेंसी : कनाडा में हर साल पंपकिन फेस्ट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस साल भी यहां के ब्रूस काउंटी में स्थित पोर्ट एल्गिन गांव में पिछले हफ्ते यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें लोग सैकड़ों किग्रा के कद्दू लेकर पहुंचे। लेकिन कैमरॉन के जेन और फिल हंट नामक दंपती ने 803 .54 किग्रा का कद्दू लाकर यह प्रतियोगिता जीत ली। दंपति ने जब इतना भारी और विशाल कद्दू प्रतियोगिता में पेश किया तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। विजेता के तौर पर उन्हें 1.60 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। जेन और फिल हंट दंपती ने साल 1990 में एक प्रतियोगिता देखी थी, जिसमें बड़े-बड़े आकार की सब्जियों को पेश किया गया था। इसके बाद से उनके अंदर भी बड़ी-बड़ी सब्जियां उगाने का जुनून सवार हो गया।

ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने वाले तीन वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल

सम्मान ▶ पीबल्स को मिलेगी पुरस्कार की आधी राशि, बाकी दोनों में बंटेगी बाकी आधी रकम

पहला एक्सोप्लेनेट खोजने वाले विजेताओं में मिशेल मेयर और क्यूलोज भी

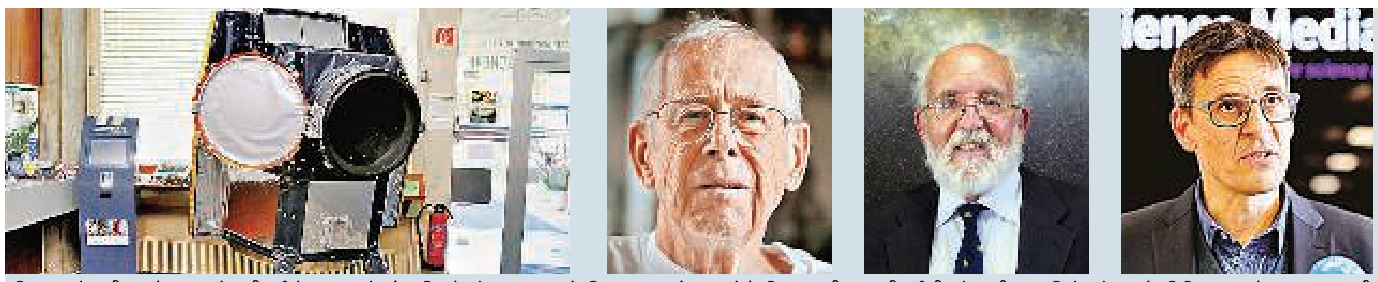

स्विटजरलैंड की एक वेशधाला में रखी गई सेटलाइट (चेप्सो)। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के विकासक्रम को समझने के लिए इसकी मदद ली गई थी। जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्लूलोज। एपी

स्टॉकहोम, एएफपी : ब्रह्मांड के विकासक्रम और अनंत ब्रह्मांड में हमारी स्थिति को समझने की दिशा में अहम शोध करने वाले तीन वैज्ञानिकों को इस साल भौतिकी के नोबेल के लिए चुना गया है। इनमें कनाडाई मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स और स्विट्जरलैंड के मिशेल मेयर व डिडियर क्यूलोज शामिल हैं। शोध की महत्ता को देखते हुए पीबल्स को पुरस्कार की आधी राशि मिलेगी। शेष आधी राशि अन्य दोनों वैज्ञानिकों में बराबर बांटी जाएगी।

भौतिकी और रसायन के नोबेल पुरस्कारों की जिम्मेदारी संभालने वाली रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के महासचिव प्रोफेसर गोरन हेंसन ने बताया कि पीबल्स की खोज से हमें यह समझने में मदद मिली कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ। इस खोज के लिए उन्हें कुल पुरस्कार की आधी राशि यानी 45 लाख स्वीडिश क्रोनर (करीब 3.23 करोड़ रुपये) दी जाएगी। अक्टूबर, 1995 में हमारी सौर व्यवस्था के बाहर पहले ग्रह (एक्सोप्लेनेट) की खोज करने वाले मेयर और क्यूलोज को बाकी राशि में से बराबर पुरस्कार मिलेगा। विजेताओं का चयन करने वाली ज्यूरी ने कहा कि इन खोजों ने ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी अवधारणा को बदलकर रख दिया।

पीबल्स अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अल्बर्ट आइंस्टीन प्रोफेसर ऑफ साइंस के तौर पर कार्यरत हैं। वहीं मेयर और क्यूलोज यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा के प्रोफेसर हैं। क्यूलोज ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हैं।

पिछले साल भी रहे थे तीन विजेता : पिछले साल अमेरिका के आर्थर अश्किन, फ्रांस के गेरार्ड मौरू और अमेरिका की डोना स्ट्रिकलैंड को लेजर से जुड़ी खोज के लिए भौतिकी का नोबेल मिला था। 1903 में मैरी क्यूरी और 1963 में जर्मन मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक मारिया ग्योपर्ट मेयर के बाद स्ट्रिकलैंड भौतिकी का नोबेल पाने वाली तीसरी महिला वैज्ञानिक हैं।

आज रसायन विज्ञान के विजेता का नाम आएगा सामने : सोमवार को चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल विजेताओं के एलान के साथ इस साल के नामों की घोषणा का दौर शुरू हुआ है। बुधवार को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और गुरुवार को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वालों के नाम का एलान किया जाएगा। पिछले साल विवाद के चलते स्थगित होने के कारण इस 2018 और 2019 दोनों वर्षों के लिए साहित्य का नोबेल दिया जाना है। शुक्रवार को शांति का नोबेल जीतने वाले का नाम बताया जाएगा। 14 अक्टूबर को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता के एलान के साथ इस साल के विजेताओं की घोषणा का क्रम पूरा होगा। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य व अर्थशास्त्र का नोबेल और ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाएगा।

जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा के नाम पर लगा दांव

इस बार शांति के नोबेल के लिए सट्टेबाजों ने युवा पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर दांव लगाया है। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण सम्मेलन में ग्रेटा ने अपने संबोधन से पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। स्वीडन में रहने वाली 16 वर्षीय ग्रेटा एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। यह विकार ऑटिज्म की शुरुआती स्थिति है। ग्रेटा ने अपने तीखे भाषण में वैश्विक नेताओं पर यह आरोप लगाया था कि वे जलवायु परिवर्तन पर कुछ करने में विफल रहे हैं।

शोध अनुसंधान

मेक्सिको के जंगल में मिला नया एंटी बायोटिक

वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के जंगल में एक नया एंटी बायोटिक खोजा है। यह एंटी बायोटिक यहां की मिट्टी में बना है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस एंटी बायोटिक की मदद से पौधों एवं मानवों को बैक्टीरिया संक्रमण से बचाने की नई दवा तैयार की जा सकती है। यह अनुमान भी है कि यह एंटी बायोटिक एक प्लांट प्रोबायोटिक की तरह काम कर सकता है, जो संक्रमण से बचने में पौधों की मदद करने और उनके विकास में सहायक होगा। इस एंटी बायोटिक को फेजोलिसिन नाम दिया गया है। फेजोलिसिन को वहां की फलियों वाले पौधों की जड़ों में खतरनाक बैक्टीरिया को प्रवेश से रोकने में सक्षम पाया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह हाल के दिनों में बैक्टीरिया तेजी से दवा प्रतिरोधी हुए हैं, ऐसे में नए एंटी बायोटिक की खोज बहुत जरूरी है। फेजोलिसिन की खोज इस दिशा में नए रास्ते खोल सकती है। - प्रेट्र

दिल की सलामती के लिए हर उम्र में व्यायाम जरूरी

नियमित व्यायाम दिल की बीमारी से जूझ रहे हर उम्र के मरीज के लिए बहुत जरूरी है। शोधकर्ताओं ने कहा कि बड़ी उम्र के साथ कई परेशानियां आती हैं, जिससे इस उम्र में व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। दिल से जुड़ी कोई बीमारी होने के बाद स्थिति और बिगड़ने लगती है। बड़ी उम्र में लोग अक्सर व्यायाम शुरू करने से भी घबराते हैं। उन्हें यह शंका रहती है कि इस उम्र में व्यायाम से खास लाभ नहीं होगा। हालांकि 733 मरीजों पर किए गए अध्ययन में यह डर निराधार साबित हुआ है। शोधकर्ताओं ने कहा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, जो दिल की बीमारी के चलते अवसाद का शिकार हो गए थे, उन्हें भी नियमित व्यायाम से बहुत लाभ मिला। नियमित व्यायाम बड़ी उम्र में दिल की बीमारियों के कारण होने वाले असमय मौत के मामलों को कम कर सकता है। - आइएएनएस

3डी प्रिंटर के उत्सर्जन से भी खराब हो सकते हैं फेफड़े

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : 3डी प्रिंटर हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इनसे उत्सर्जित होने वाले सूक्ष्म कण इंडोर एयर क्वालिटी (भीतरी हवा की गुणवत्ता) को खराब करते हैं, जिससे लोग श्वसन संबंधी विकारों से ग्रसित हो सकते हैं।

जार्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और यूएल केमिकल सेफ्टी रिसर्च ग्रुप के शोधकर्ताओं ने 3डी प्रिंटर से निकलने वाले सूक्ष्म कणों को एकत्र किया और अध्ययन कर यह पता लगाया कि ये कण कैसे हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं।

इस अध्ययन के नेतृत्वकर्ता और जॉर्जिया टेक स्कूल ऑफ अर्थ एंड एटमॉफियरिक साइंस के प्रोफेसर रोडनी वेबर ने कहा, 'अध्ययन के दौरान हमने पाया कि 3डी प्रिंटर से निकलने वाले सूक्ष्म कण हमारे शरीर के लिए बेहद घातक होते हैं। हमें इसके उत्सर्जन से बचने के पुख्ता उपाय खोजने के बाद ही इन्हें प्रयोग में लाना चाहिए।'

आमतौर पर 3डी प्रिंटर का प्रयोग प्लास्टिक को गलाकर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक को गलाने के दौरान कई तरह की विषाक्त गैसों का उत्सर्जन भी होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं जो वायुमंडल में घुल कर उसे जहरीला बना देते हैं। बता दें कि वर्तमान में 3डी प्रिंटर की बाजार लगभग 990 करोड़ रुपये का है।

प्रतीकात्मक

पिछले अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया था कि सामान्यतः प्लास्टिक को गलाने के लिए ज्यादा गर्म तापमान की जरूरत होती है। इससे और ज्यादा उत्सर्जन होता है, जबकि कम तापमान में प्लास्टिक को गलाने से पॉलीलेक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इन दोनों के यौगिकों का अध्ययन करने पर यह देखा गया है कि हमारे श्वसन तंत्र के लिए यह बेहद घातक हैं।

हमारे सौरमंडल में अब शनि के पास सबसे ज्यादा चांद

▶ शोधकर्ताओं ने गृह की परिक्रमा कर रहे 20 नए चंद्रमा खोजे

▶ अभी तक चंद्रमाओं की संख्या में बृहस्पति था सबसे आगे

वाशिंगटन, प्रेट्र : अनंत रहस्यों से भरे ब्रह्मांड में शोधकर्ता लगातार नई खोजें कर रहे हैं। अब शोधकर्ताओं ने शनि गृह की परिक्रमा कर रहे 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे इस गृह के चंद्रमाओं के संख्या 82 हो गई है। हमारे सौरमंडल में अभी तक बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा 79 चांद थे, लेकिन इस खोज के बाद शनि सबसे आगे निकल गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह खोज शनि की उत्पत्ति व विकास पर और प्रकाश डाल सकती है।

हवाई में स्थित सुबारू टेलीस्कोप की मदद से इन चंद्रमाओं की खोज करने वाले शोधकर्ताओं में अमेरिका स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के स्कॉट एस. शेफर्ड भी शामिल रहे। खोज के प्रमुख शेफर्ड के मुताबिक, तलाशे गए सभी चंद्रमाओं का व्यास करीब पांच किलोमीटर है। इनमें से तीन चांद शनि के अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा में उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, जबकि 17 विपरीत दिशा में।

परिक्रमा करने में लगता है इतना समय : अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं ने बताया कि तीन चांद जो शनि की दिशा में ही उसकी परिक्रमा कर रहे हैं उनमें से दो तीसरे की तुलना में इस गृह के नजदीक हैं। इन दो चंद्रमाओं को शनि की परिक्रमा करने में दो साल का समय लगता है, जबकि तीसरे को अधिक दूरी के कारण तीन साल।

वैज्ञानिकों की यह खोज शनि की उत्पत्ति व विकास पर और प्रकाश डाल सकती है। प्रतीकात्मक

यह मिल सकती है जानकारी : शेफर्ड के मुताबिक, इन चंद्रमाओं की कक्षाओं के अध्ययन से इनकी उत्पत्ति का पता चल सकता है। साथ ही इनकी उत्पत्ति के समय शनि के आसपास की स्थितियों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। इससे शनि की उत्पत्ति के साथ उसमें आए बदलावों के अलावा अन्य गृहों की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। खोजकर्ताओं में शेफर्ड के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लास एंजिलिस के डेविड जेविट और हवाई यूनिवर्सिटी के जन क्लेयना भी शामिल रहे।

कहीं बड़े चांद से तो नहीं टूटे ये : शोधकर्ताओं ने संभावना जताई है कि ये छोटे-छोटे चांद किसी बड़े चांद से टूटकर बने हो सकते हैं। शेफर्ड के मुताबिक, ये छोटे चांद अपने मुख्य चांद से टूट कर भी शनि की परिक्रमा करने में सक्षम रहे, जो अहम बात है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन से पता लगाया है कि शनि की उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहे चांद अपने अक्ष पर उतना ही झुके हुए हैं, जितना इनसे पूर्व खोजे गए चांद। इससे इस संभावना को और बल मिलता है कि ये सभी चांद एक बड़े चांद से टूट कर बने हैं।

शेफर्ड कहते हैं, इस तरह के बाहरी चंद्रमाओं का समूह बृहस्पति के आसपास भी दिखाई देता है। यह इस बात का संकेत करते हैं कि सैटर्नियन प्रणाली में या बाहरी चीजों जैसे क्षुद्रग्रहों या धूमकेतुओं को पार करने के दौरान टकराव हुआ।

पहले भी खोज चुके हैं चांद : शेफर्ड इससे पहले भी इस तरह की खोज कर चुके हैं। वह बृहस्पति की परिक्रमा कर रहे 12 चंद्रमाओं की तलाश कर चुके हैं। बता दें कि कार्नेगी कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस ने खोजे गए नए चंद्रमाओं में से पांच के नामकरण के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता भी शुरू की है।

विक्टर करेगा जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक

यह नौ साल का सफेद पूंछ वाला गरुण (ईगल) है। इसका नाम विक्टर है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर साल-दर साल पिघल रहे हैं। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए फ्रांस में वैज्ञानिकों ने एक अभिनव पहल शुरू की है। वैज्ञानिकों ने विक्टर को 360 कैमरों से लैस किया है। यह ग्लेशियरों और पहाड़ों के ऊपर उड़कर कैमरों के जरिये वहां की बिगड़ती स्थिति के बारे में पुख्ता सुबूत एकत्र कर वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। जल्दी ही विक्टर को 'अल्पाइन ईगल रेस' में भी भाग लेने के लिए उतारा जाएगा। रायटर

फ्रांस में सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान

फ्रांस में इन दिनों किसान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल, सरकार ने खेती और घरों के आस-पास कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगा दी है, जिसका किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को दो किसान यूनियनों के आहवान पर प्रदर्शनकारियों ने पूर्वी फ्रांस के पास ए-4 राजमार्ग पर अपने ट्रैक्टरों को खड़ा कर दिया, जिससे ट्रैफिक ठप हो गया। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। एएफपी

स्क्रीन शॉट

हिट फिल्म देना चाहते हैं शाह रुख

पिछले साल रिलीज फिल्म 'जीरो' के बॉक्स ऑफिस पर न चलने के बाद शाह रुख ने अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा पर आधारित बायोपिक करने से भी इन्कार कर दिया था। अपने जन्मदिन (दो नवंबर) को वह 'टेड टॉक शो' का दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि वह एक ऐसी फिल्म पर काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वह हिट होगी। दरअसल, मंगलवार को सोशल मीडिया पर वह अपने प्रशंसकों के सवालों के जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वह अपनी अगली फिल्म लेकर कब आ रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि वह कुछ स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वह किस प्रकार की फिल्म में काम करना चाहते हैं? सवाल के जवाब में शाह रुख ने कहा- हिट जैसी। संभवतः बात यहीं खत्म नहीं हुई? एक प्रशंसक ने पूछा कि सुना है कि आप 'धूम' की चौथी किस्त में भी काम कर रहे हैं। शाह रुख ने मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए लिखा, 'सुना तो मैंने भी है, अगर तुम्हें कुछ खबर मिले तो देना।' वहीं एक यूजर ने फिल्म 'रा.वन' का मजाक बनाते हुए कहा कि सर आज दशहरा है तो 'रा.वन' की सीडी जला क्यों नहीं देते हैं। इस पर शाह रुख ने लिखा- अरे, कितना जले पर नमक छिड़कोगे?

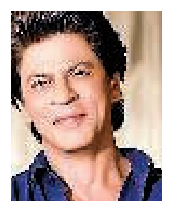

अनिल कपूर की तमन्ना हुई पूरी

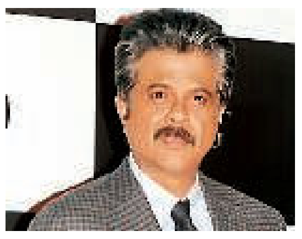

बतौर अभिनेता अनिल कपूर की पहली फिल्म 'वो सात दिन' को रिलीज हुए 36 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड तथा हॉलीवुड में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। फिल्म 'तख्त' में अनिल कपूर पहली बार फिल्ममेकर करण जौहर के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि अनिल कपूर अर्से से करण के साथ किसी फिल्म में काम करना चाहते थे।

उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार फिल्म समीक्षक और लेखक मुहम्मद खालिद की किताब 'द अलादिया सिस्टर्स' के लांच के मौके पर किया। मुंबई में करण जौहर, आशा पारेख, और जावेद अख्तर जैसे हस्तियों की मौजूदगी में इस किताब को लांच किया गया। इस मौके पर अनिल कपूर ने कहा कि वह और करण कई वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं। दोनों करीबी दोस्त भी हैं। वह हमेशा से करण और उनके पिता के साथ फिल्मों में काम करना चाहता थे, पर यह संभव नहीं हो पाया। इतने वर्षों के बाद दोनों पहली बार फिल्म 'तख्त' में एकसाथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे भी साथ काम करने की भी उम्मीद जताई। इस मौके पर अनिल यह कहना नहीं भूले कि खालिद मुहम्मद ने अपनी फिल्म समीक्षा में उनकी दो सुपरहिट फिल्मों 'बेटा', और 'लम्हे' की कड़ी आलोचना की थी। इसके लिए अनिल को बुरा भी लगा था। बाद में 'बेटा' के लिए अनिल को फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर के खिताब से भी नवाजा गया था। मल्टीस्टारर 'तख्त' में अनिल कपूर साथ रणवीर सिंह, विक्की कौशल, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान और भूमि पेडणेकर मुख्य भूमिका में हैं। मुगलकालीन पृष्ठभूमि पर आधारित यह पीरियड फिल्म अगले साल रिलीज होगी। उससे पहले अगले महीने रिलीज होने वाली 'पागलपंती' में अनिल कॉमेडी करते दिखेंगे।

अब 'सूर्यवंशी' की शूटिंग करेंगे रणवीर सिंह

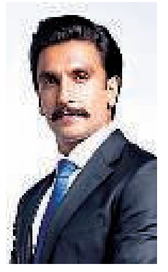

फिल्म '83 की शूटिंग पूरी होने पर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने बीते सोमवार को पूरी टीम को पार्टी दी थी। रणवीर ने इस बात का खास ख्याल रखा कि पार्टी में कास्ट और क्रू एंज्वॉय करें। फिर रणवीर अपनी अगली फिल्म सूर्यवंशी की शूटिंग के लिए हैदराबाद रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को रणवीर ने पार्टी में टीम के साथ खूब डांस किया। शूटिंग के दौरान उनके साथ रणवीर का परिवार जैसा रिश्ता बन गया था। पार्टी के खत्म होने बाद रणवीर सीधे एयरपोर्ट रवाना हो गए। हैदराबाद में वह रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'सूर्यवंशी' की शूटिंग करेंगे। वहां पर वह करीब एक हफ्ते तक रहेंगे। फिल्म में अक्षय कुमार एंटी टेररिज्म स्क्वॉड के चीफ की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन अपने सिंघम जबकि रणवीर सिंबा के किरदार में कैमियो करते दिखेंगे।

'वास्तव' ने मुझे वास्तव में अभिनेता बनाया

अभिनेता संजय दत्त मानते हैं कि उन्हें सही मायनों में एक्टर के रूप में पहचान उनकी फिल्म 'वास्तव' ने दी है। फिल्म के 20 साल पूरे होने पर संजय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'वास्तव के 20 साल पूरे होने की खुशी मना रहा हूं। एक ऐसी फिल्म, जिसने मुझे सही मायनों में अभिनेता बनाया।' यह फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कड़वी सच्चाई को बताती है। महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित फिल्म में नम्रता शिरोडकर, संजय नारवेकर, मनीष बहल, रीमा लागू और शिवाजी भी थे। संजय की आने वाली फिल्मों में आशुतोष गोवारिकर निर्देशित 'पानीपत' है। इस फिल्म में अर्जुन कपूर और कृति सैनन भी नजर आएंगे। हाल ही में संजय दत्त की फिल्म 'प्रस्थानम' रिलीज हुई थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस में बनी इस फिल्म को डायरेक्टर देवा कात्ता ने निर्देशित किया था। फिल्म फैमिली ड्रामा है, जिसके केंद्र में राजनीति है। संजय दत्त बाहुबली नेता का किरदार निभा रहे हैं, जो विधवा महिला से शादी करता है। सत्ता पाने की चाह में संजय के दोनों बेटे आपस में उलझते नजर आते हैं।

अध्ययन

यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के शोधकर्ताओं ने कहा- चार हजार साल पहले चरम मौसमी घटनाओं के कारण हुई थी प्राचीन विशालकाय हाथियों की मौत

आर्कटिक आइलैंड में हुई आखिरी मैमथ की मौत

▶ हिम युग के दौर में साइबेरिया में पाए जाते थे मैमथ

▶ ग्लोबल वार्मिंग के कारण खत्म हो गई इनकी आबादी

▶ यह अध्ययन जर्नल क्वाटर्नरी साइंस रिव्यू में प्रकाशित हुआ है

आर्कटिक महासागर के रेंगल आइलैंड में रहता था आखिरी मैमथ। प्रतीकात्मक

लंदन, प्रेट्र : हिम युग के दौर में साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाने वाले मैमथ (विशालकाय हाथी) हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। जीवाश्मों का अध्ययन कर शोधकर्ताओं इनके रहन-सहन के बारे में नई-नई जानकारियां समय-समय पर देते रहते हैं। मैमथ बारे में हाल ही में हुए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि आर्कटिक महासागर के रेंगल आइलैंड में रहने वाले दुनिया के आखिरी मैमथ की मौत चरम मौसमी घटनाओं के कारण चार हजार साल पहले हुई थी। फिनलैंड की हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं सहित एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने उन चरम मौसमी घटनाओं के परिदृश्यों को एक कंप्यूटर मॉडल के जरिये बनाकर इन विशालकाय हाथियों के विलुप्त होने के कारण का पता लगाया है।

जर्नल क्वाटर्नरी साइंस रिव्यू में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, हिम युग के आखिरी समय (एक लाख से 15 हजार साल पहले) तक मैमथ उत्तरी गोलार्द्ध में स्पेन से लेकर अलास्का तक फैले रहते थे। 15 हजार साल पहले शुरू हुई ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनके आवास धीरे-धीरे उत्तरी साइबेरिया और अलास्का में ही सीमित हो गए। समुद्री पानी का स्तर बढ़ने के कारण रेंगल आइलैंड में रहने वाले मैमथ दूसरी दुनिया से कट गए और यहां इसकी आबादी अगले सात हजार साल तक जीवित रही। शोधकर्ताओं की टीम में जर्मनी की ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी और रशियन एकेडमी ऑफ साइंस के शोधकर्ता भी शामिल थे। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने उत्तरी साइबेरिया, अलास्का, यूकान और रैंगल आइलैंड से मिले मैमथ के जीवाश्मों (दांत, हड्डियां आदि) का अध्ययन किया।

इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि रैंगल आइलैंड पर मैमथ के जीवाश्म गर्मी बढ़ने के बाद भी दस हजार साल तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे। इसका अर्थ है कि ग्लोबल वार्मिंग के शुरू होने के बाद भी कई सालों तक मैमथ ने खुद को जलवायु के अनुकूल बनाए रखने की कोशिश की होगी। वहीं, दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के मैदानों में मैमथ 15,000 साल पहले ही गायब हो गए थे, जबकि अलास्का के सेंट पॉल द्वीप के मैमथ 5,600 साल पहले विलुप्त हो गए थे।

अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने कहा कि दोनों ही मामलों में इनकी आबादी के अंतिम प्रतिनिधियों की शारीरिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले, जिसका अर्थ है कि विलुप्त होने से पहले उनके पर्यावरण में भारी बदलाव आया होगा।